चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

जनता की समस्याएं और चुनौतियां

पेज-3

सुशासन और विकास का कड़वा सच

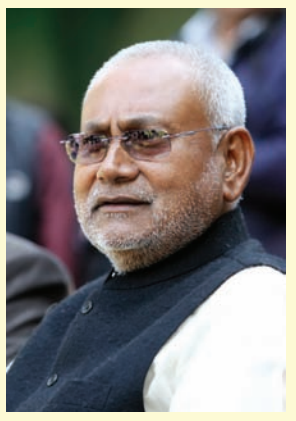

पेज-4

गंगा मैली हो गई

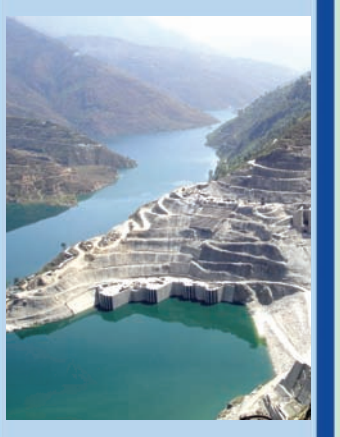

पेज-6

साई की महिमा

पेज-12

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 28 मार्च–03 अप्रैल 2011 | मूल्य 5 रुपये

नक़ली नोट रिज़र्व बैंक और सरकार

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

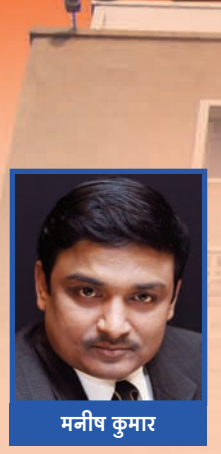

मनीष कुमार

नक़ली नोट पर अब तक का सबसे बड़ा ख़ुलासा

रिज़र्व बैंक के ख़ज़ाने में नक़ली नोट कैसे पहुंचे

सीबीआई ने रिज़र्व बैंक में क्यों छापा मारा

असली और नक़ली नोट में फ़र्क़ क्यों नहीं कर पा रही सरकार

नक़ली नोट के ख़ुलासे से यूरोप में भूचाल क्यों आया

देश के रिज़र्व बैंक के वाल्ट पर सीबीआई ने छापा डाला. उसे वहां पांच सौ और हज़ार रुपये के नक़ली नोट मिले. वरिष्ठ अधिकारियों से सीबीआई ने पूछताछ भी की. दरअसल सीबीआई ने नेपाल–भारत सीमा के साठ से सत्तर विभिन्न बैंकों की शाखाओं पर छापा डाला था, जहां से नक़ली नोटों का कारोबार चल रहा था. इन बैंकों के अधिकारियों ने सीबीआई से कहा कि उन्हें ये नक़ली नोट भारत के रिजर्व बैंक से मिल रहे हैं. इस पूरी घटना को भारत सरकार ने देश से और देश की संसद से छुपा लिया. या शायद सीबीआई ने भारत सरकार को इस घटना के बारे में कुछ बताया ही नहीं. देश अंधेरे में और देश को तबाह करने वाले रोशनी में हैं. आइए, आपको आज़ाद भारत के सबसे बड़े आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताते हैं, जिसे हमने पांच महीने की तलाश के बाद आपके सामने रखने का फ़ैसला किया है. कहानी है रिज़र्व बैंक के माध्यम से देश के अपराधियों द्वारा नक़ली नोटों का कारोबार करने की.

नक़ली नोटों के कारोबार ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अपने जाल में जकड़ लिया है. आम जनता के हाथों में नक़ली नोट हैं, पर उसे ख़बर तक नहीं है. बैंक में नक़ली नोट मिल रहे हैं, एटीएम नक़ली नोट उगल रहे हैं. असली–नक़ली नोट पहचानने वाली मशीन नक़ली नोट को असली बता रही है. इस देश में क्या हो रहा है, यह समझ के बाहर है. चौथी दुनिया की तहक़ीक़ात से यह पता चला है कि जो कंपनी भारत के लिए करेंसी छापती रही, वही 500 और 1000 के नक़ली नोट भी छाप रही है. हमारी तहक़ीक़ात से यह अंदेशा होता है कि देश की सरकार और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जाने–अनजाने में नोट छापने वाली विदेशी कंपनी के पार्टनर बन चुके हैं. अब सवाल यही है कि इस ख़तरनाक साज़िश पर देश की सरकार और एजेंसियां क्यों चुप हैं?

एक जानकारी जो पूरे देश से छुपा ली गई, अगस्त 2010 में सीबीआई की टीम ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वाल्ट में छापा मारा. सीबीआई के अधिकारियों का दिमाग़ उस समय सन्न रह गया, जब उन्हें पता चला कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ख़ज़ाने में नक़ली नोट हैं. रिज़र्व बैंक से मिले नक़ली नोट वही नोट थे, जिसे पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी नेपाल के रास्ते भारत भेज रही है. सवाल यह है कि भारत के रिजर्व बैंक में नक़ली नोट कहां से आए? क्या आईएसआई की पहुंच रिज़र्व बैंक की तिजोरी तक है या फिर कोई बहुत ही भयंकर साज़िश है, जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को खोखला कर चुकी है. सीबीआई इस सनसनीखेज मामले की तहक़ीक़ात कर रही है. छह बैंक कर्मचारियों से सीबीआई ने पूछताछ भी की है. इतने महीने बीत जाने के बावजूद किसी को यह पता नहीं है कि जांच में क्या निकला? सीबीआई और वित्त मंत्रालय को देश को बताना चाहिए कि बैंक अधिकारियों ने जांच के दौरान क्या कहा? नक़ली नोटों के इस ख़तरनाक खेल पर सरकार, संसद और जांच एजेंसियां क्यों चुप है तथा संसद अंधेरे में क्यों है?

अब सवाल यह है कि सीबीआई को मुंबई के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में छापा मारने की ज़रूरत क्यों पड़ी? रिजर्व बैंक से पहले नेपाल बॉर्डर से सटे बिहार और उत्तर प्रदेश के क़रीब 70–80 बैंकों में छापा पड़ा. इन बैंकों में इसलिए छापा पड़ा, क्योंकि जांच एजेंसियों को ख़बर मिली है कि पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई नेपाल के रास्ते भारत में नक़ली नोट भेज रही है. बॉर्डर के इलाक़े के बैंकों में नक़ली नोटों का लेन–देन हो रहा है. आईएसआई के रैकेट के ज़रिए 500 रुपये के नोट 250 रुपये में बेचे जा रहे हैं. छापे के दौरान इन बैंकों में असली नोट भी मिले और नक़ली नोट भी. जांच एजेंसियों को लगा कि नक़ली नोट नेपाल के ज़रिए बैंक तक पहुंचे हैं, लेकिन जब पूछताछ हुई तो सीबीआई के होश उड़ गए. कुछ बैंक अधिकारियों की पकड़–धकड़ हुई. ये बैंक अधिकारी रोने लगे, अपने बच्चों की कसमें खाने लगे. उन लोगों ने बताया कि उन्हें नक़ली नोटों के बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि ये नोट रिजर्व बैंक से आए हैं. यह किसी एक बैंक की कहानी होती तो इसे नकारा भी जा सकता था, लेकिन हर जगह यही पैटर्न मिला. यहां से मिली जानकारी के बाद ही सीबीआई ने फ़ैसला लिया कि अगर नक़ली नोट रिजर्व बैंक से आ रहे हैं तो वहीं जाकर देखा जाए कि मामला क्या है. सीबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पहुंची, यहां उसे नक़ली नोट मिले. हैरानी की बात यह है कि रिज़र्व बैंक में मिले नक़ली नोट वही नोट थे, जिन्हें आईएसआई नेपाल के ज़रिए भारत भेजती है.

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया में नक़ली नोट कहां से आए, इस गुत्थी को समझने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में नक़ली नोटों के मामले को समझना ज़रूरी है. दरअसल हुआ यह कि आईएसआई की गतिविधियों की वजह से यहां आएदिन नक़ली नोट पकड़े जाते हैं. मामला अदालत पहुंचता है. बहुत सारे केसों में वकीलों ने अनजाने में जज के सामने यह दलील दी कि पहले यह तो तय हो जाए कि ये नोट नक़ली हैं. इन वकीलों को शायद जाली नोट के कारोबार के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था, सिर्फ़ कोर्ट से वक़्त लेने के लिए उन्होंने यह दलील दी थी. कोर्ट ने जब्त हुए नोटों को जांच के लिए सरकारी लैब भेज दिया, ताकि यह तय हो सके कि ज़ब्त किए गए नोट नक़ली हैं. रिपोर्ट आती है कि नोट असली हैं. मतलब यह कि असली और नक़ली नोटों के कागज, इंक, छपाई और सुरक्षा चिन्ह सब एक जैसे हैं. जांच एजेंसियों के होश उड़ गए कि अगर ये नोट असली हैं तो फिर 500 का नोट 250 में क्यों बिक रहा है. उन्हें तसल्ली नहीं हुई. फिर इन्हीं नोटों को टोक्यो और हांगकांग की लैब में भेजा गया. वहां से भी रिपोर्ट आई

(शेष पृष्ठ 2 पर)

डे ला रू का नेपाल और आईएसआई कनेक्शन

रोबेर्तो ग्योरी

कंधार हाईजैक की कहानी बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन इस अध्याय का एक ऐसा पहलू है, जो अब तक दुनिया की नज़र से छुपा हुआ है. इस IC-814 में एक ऐसा शख़्स बैठा था, जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे. इस आदमी को दुनिया भर में करेंसी किंग के नाम से जाना जाता है. इसका असली नाम है रोबेर्टो ग्योरी. यह इस जहाज में दो महिलाओं के साथ सफ़र कर रहा था. दोनों महिलाएं स्विट्जरलैंड की नागरिक थीं. रोबेर्टो खुद दो देशों की नागरिकता रखता है, जिसमें पहला है इटली और दूसरा स्विट्जरलैंड. रोबेर्टो को करेंसी किंग इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह डे ला रू नाम की कंपनी का मालिक है. रोबेर्टो ग्योरी को अपने पिता से यह कंपनी मिली. दुनिया की करेंसी छापने का 90 फ़ीसदी बिजनेस इस कंपनी के पास है. यह कंपनी दुनिया के कई देशों के नोट छापती है. यही कंपनी पाकिस्तान की आईएसआई के लिए भी काम करती है. जैसे ही यह जहाज हाईजैक हुआ, स्विट्जरलैंड ने एक विशिष्ट दल को हाईजैकर्स से बातचीत करने कंधार भेजा. साथ ही उसने भारत सरकार पर यह दबाव बनाया कि वह किसी भी क़ीमत पर करेंसी किंग रोबेर्टो ग्योरी और उनके मित्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करे. ग्योरी बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहा था. आतंकियों ने उसे प्लेन के सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा दिया. लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन ग्योरी आराम से अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था. उसके पास सैटेलाइट पेन ड्राइव और फोन थे.यह आदमी कंधार के हाईजैक जहाज में क्या कर रहा था, यह बात किसी की समझ में नहीं आई है. नेपाल में ऐसी क्या बात है, जिससे स्विट्जरलैंड के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया भर के नोटों को छापने वाली कंपनी के मालिक को वहां आना पड़ा. क्या वह नेपाल जाने से पहले भारत आया था. ये सिर्फ़ सवाल हैं, जिनका जवाब सरकार के पास होना चाहिए. संसद के सदस्यों को पता होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए थी. संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी. शायद हिंदुस्तान में फैले जाली नोटों का भेद खुल जाता.

नक़ली नोटों का मायाजाल

सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि 2006 से 2009 के बीच 7.34 लाख सौ रुपये के नोट, 5.76 लाख पांच सौ रुपये के नोट और 1.09 लाख एक हज़ार रुपये के नोट बरामद किए गए. नायक कमेटी के मुताबिक़, देश में लगभग 1,69,000 करोड़ जाली नोट बाज़ार में हैं. नक़ली नोटों का कारोबार कितना ख़तरनाक रूप ले चुका है, यह जानने के लिए पिछले कुछ सालों में हुई कुछ महत्वपूर्ण बैठकों केबारे में जानते हैं. इन बैठकों से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश की एजेंसियां सब कुछ जानते हुए भी बेबस और लाचार हैं. इस धंधे की जड़ में क्या है, यह हमारे ख़ुफ़िया विभाग को पता है. नक़ली नोटों के लिए बनी ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत नक़ली नोट प्रिंट करने वालों के स्रोत तक नहीं पहुंच सका है. नोट छापने वाले प्रेस विदेशों में लगे हैं. इसलिए इस मुहिम में विदेश मंत्रालय की मदद लेनी होगी, ताकि उन देशों पर दबाव डाला जा सके. 13 अगस्त, 2009 को सीबीआई ने एक बयान दिया कि नक़ली नोट छापने वालों के पास भारतीय नोट बनाने वाला गुप्त सांचा है, नोट बनाने वाली स्पेशल इंक और पेपर की पूरी जानकारी है. इसी वजह से देश में असली दिखने वाले नक़ली नोट भेजे जा रहे हैं. सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि नक़ली नोटों के मामलों की तहक़ीक़ात के लिए देश की कई एजेंसियों के सहयोग से एक स्पेशल टीम बनाई गई है. 13 सितंबर, 2009 को नॉर्थ ब्लॉक में स्थित इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड क्वार्टर में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें इकोनोमिक इंटेलिजेंस की सारी अहम एजेंसियों ने हिस्सा लिया. इसमें डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, वित्त मंत्रालय, सीबीआई और सेंट्रल इकोनोमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रतिनिधि मौजूद थे. इस मीटिंग का निष्कर्ष यह निकला कि जाली नोटों का कारोबार अब अपराध से बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है. इससे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईबी, डीआरआई, ईडी, सीबीआई, सीईआईबी, कस्टम और अर्धसैनिक बलों के प्रतिनिधि मौजूद थे. इस बैठक में यह तय हुआ कि ब्रिटेन के साथ यूरोप के दूसरे देशों से इस मामले में बातचीत होगी, जहां से नोट बनाने वाले पेपर और इंक की सप्लाई होती है. तो अब सवाल उठता है कि इतने दिनों बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, जांच एजेंसियों को किसकेआदेश का इंतजार है?

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार से संबंधित कई मामलों में निर्णय करते वक्त कड़ा रुख अपनाया, उससे एक उम्मीद तो जगती ही है.

दिल्ली का बाबू

अदालत की शरण

लगातार हो रहे और मानों कभी ख़त्म न होने वाले ख़ुलासों ने लोक सेवा से संबंधित अधिकारियों को परेशान कर रखा है. नतीजतन, लोक सेवा में लगातार आ रही इस गिरावट से पूर्व नौकरशाह चिंतित दिख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध कर रहे हैं कि वह इस मामले में दख़ल दे. ज़्यादातर पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह एक अभूतपूर्व क़दम है. पूर्व कैबिनेट सचिव टी एस आर सुब्रमण्यम और अन्य 82 पूर्व बाबुओं, जिनमें अवकाशप्राप्त चुनाव आयुक्त, कूटनीतिज्ञ, मुख्य सचिव और पुलिस अधिकारी शामिल हैं, ने सुप्रीम कोर्ट से प्रशासनिक सुधारों को लागू कराने का अनुरोध किया है. सूत्रों के मुताबिक़, याचिका डालने वाले लोगों में टी एस आर सुब्रमण्यम के अलावा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी एस कृष्णमूर्ति एवं एन गोपालास्वामी, पूर्व सीबीआई निदेशक जोगिंदर सिंह और पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं मणिपुर के राज्यपाल वेद मारवाह के नाम शामिल हैं. ज़ाहिर है, ये पूर्व बाबू अकेले ऐसे लोग नहीं हैं, जिन्होंने बेहतर शासन में आ रहे गतिरोध को लेकर पहले कोई कोशिश नहीं की थी. लेकिन उम्मीद है कि इस बार इनके सामूहिक प्रयास रंग लाएंगे. पिछले दिनों जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार से संबंधित कई मामलों में निर्णय करते वक्त कड़ा रुख अपनाया, उससे एक उम्मीद तो जगती ही है. कम से कम इन पूर्व बाबुओं को यह उम्मीद तो है कि शायद कोर्ट के कड़े रुख़ से ही प्रशासनिक सुधार की गति थोड़ी और बढ़ जाए.

उच्च स्तर पर सड़न

दिलीप चेरियन

यह वक़्त हमारी कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता. हाल-फ़िलहाल में कुछ पीएसयू के मुखिया ग़लत वजह से सुर्ख़ियों में छाए रहे. सबसे बड़ा झटका नाल्को के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक ए के श्रीवास्तव और उनकी पत्नी की गिरफ़्तारी से लगा. इन दोनों पर घूसखोरी के आरोप थे. अभी सीबीआई ने जांच शुरू ही की थी कि एक और मामला सामने आया. कोयला मंत्रालय के बाबू सीबीआई को वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि. के मुखिया डी सी गर्ग के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने से रोकने की कोशिश कर रहे थे. जबकि सतर्कता अधिकारियों ने सीबीआई से मामला दर्ज करने की अनुशंसा कर दी थी. सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई के पास मुख्य सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट से मिले पर्याप्त सबूत हैं, जो बताते हैं कि कैसे गर्ग ने एक प्राइवेट कांट्रेक्टर का पक्ष लिया और जिसकी वजह से कोयले से जुड़ी पीएसयू को भारी घाटा उठाना पड़ा. एक साल पहले ही सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कोयला मंत्रालय के सचिव सी बालाकृष्णन को पत्र लिखकर गर्ग के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की अनुमति मांगी थी. सूत्रों के मुताबिक़, तबसे वह फाइल आगे बढ़ी ही नहीं. बावजूद इसके कि सीबीआई ने इस बारे में कई रिमाइंडर भी भेजे. सीबीआई के निदेशक अश्विनी कुमार ने भी अपनी तरफ़ से रिमाइंडर भेजा, लेकिन कुछ नहीं हुआ.

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

अफ़ज़ल अमानुल्लाह नॉर्थ ब्लॉक में!

इस बात की संभावना जताई जा रही है कि बिहार कैडर और 1979 बैच के आईएएस अधिकारी अफ़ज़ल अमानुल्लाह भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव या इसके समकक्ष पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं. अमानुल्लाह फ़िलहाल कैबिनेट सचिवालय, पटना में प्रधान सचिव के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं.

बिस्वास बने निदेशक

आईएफएस अधिकारी शोमिता बिस्वास को जल्द ही सी एस भारती की जगह परमाणु ऊर्जा विभाग का नया निदेशक बनाया जा सकता है.

अशोक एनसीएससी पहुंचे

हिमाचल प्रदेश कैडर और 1977 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक ठाकुर को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया सचिव बनाया जा रहा है. यह आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आता है. अशोक ठाकुर राम लुभाया की जगह लेंगे, जो एक साल बीत जाने के बाद भी आयोग में अपना पदभार ग्रहण करने में असफल रहे थे.

हुडको के सीएमडी बने बलिगार

वर्ष 1980 बैच के आईएएस अधिकारी वी पी बलिगार को हुडको का नया सीएमडी बनाया गया है. अभी तक शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉ. पी के मोहंती के पास हुडको का अतिरिक्त प्रभार था.

अमित की जगह वीणा

वर्ष 1982 बैच की आईडीएएस अधिकारी वीणा प्रसाद को जल्द ही रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पद पर नियुक्त किया जाना है. उन्हें अमित कोइश की जगह लाया जा रहा है.

नक़ली नोट, रिज़र्व बैंक और सरकार

पृष्ठ एक का शेष

कि ये नोट असली हैं. फिर इन्हें अमेरिका भेजा गया. नक़ली नोट कितने असली हैं, इसका पता तब चला, जब अमेरिका की एक लैब ने यह कहा कि ये नोट नक़ली हैं. लैब ने यह भी कहा कि दोनों में इतनी समानताएं हैं कि जिन्हें पकड़ना मुश्किल है और जो विषमताएं हैं, वे भी जानबूझ कर डाली गई हैं और नोट बनाने वाली कोई बेहतरीन कंपनी ही ऐसे नोट बना सकती है. अमेरिका की लैब ने जांच एजेंसियों को पूरा प्रूव दे दिया और तरीक़ा बताया कि कैसे नक़ली नोटों को पहचाना जा सकता है. इस लैब ने बताया कि इन नक़ली नोटों में एक छोटी सी जगह है, जहां छेड़छाड़ हुई है. इसके बाद ही नेपाल बॉर्डर से सटे बैंकों में छापेमारी का सिलसिला शुरू हुआ. नक़ली नोटों की पहचान हो गई, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि नेपाल से आने वाले 500 एवं 1000 के नोट और रिज़र्व बैंक में मिलने वाले नक़ली नोट एक ही तरह के कैसे हैं. जिस नक़ली नोट को आईएसआई भेज रही है, वही नोट रिजर्व बैंक में कैसे आया. दोनों जगह पकड़े गए नक़ली नोटों के काग़ज़, इंक और छपाई एक जैसी क्यों है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत के 500 और 1000 के जो नोट हैं, उनकी क्वालिटी ऐसी है, जिसे आसानी से नहीं बनाया जा सकता है और पाकिस्तान के पास वह टेक्नोलॉजी है ही नहीं. इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जहां से ये नक़ली नोट आईएसआई को मिल रहे हैं, वहीं से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को भी सप्लाई हो रहे हैं. अब दो ही बातें हो सकती हैं. यह जांच एजेंसियों को तय करना है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों की मिलीभगत से नक़ली नोट आया या फिर हमारी अर्थव्यवस्था ही अंतरराष्ट्रीय माफ़िया गैंग की साज़िश का शिकार हो गई है. अब सवाल उठता है कि ये नक़ली नोट छापता कौन है.

हमारी तहक़ीक़ात डे ला रू नाम की कंपनी तक पहुंच गई. जो जानकारी हासिल हुई, उससे यह साबित होता है कि नक़ली नोटों के कारोबार की जड़ में यही कंपनी है. डे ला रू कंपनी का सबसे बड़ा करार रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ था, जिसे यह स्पेशल वॉटरमार्क वाला बैंक नोट पेपर सप्लाई करती रही है. पिछले कुछ समय से इस कंपनी में भूचाल आया हुआ है. जब रिजर्व बैंक में छापा पड़ा तो डे ला रू के शेयर लुढ़क गए. यूरोप में ख़राब करेंसी नोटों की सप्लाई का मामला छा गया. इस कंपनी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कुछ ऐसे नोट दे दिए, जो असली नहीं थे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टीम इंग्लैंड गई, उसने डे ला रू कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की. नतीजा यह हुआ कि कंपनी ने हम्प्शायर की अपनी यूनिट में उत्पादन और आगे की शिपमेंट बंद कर दी. डे ला रू कंपनी के अधिकारियों ने भरोसा दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहा कि कंपनी से जुड़ी कई गंभीर चिंताएं हैं. अंग्रेजी में कहें तो सीरियस कंसर्नस. टीम वापस भारत आ गई. डे ला रू कंपनी की 25 फीसदी कमाई भारत से होती है. इस ख़बर के आते ही डे ला रू कंपनी के शेयर धराशायी हो गए. यूरोप में हंगामा मच गया, लेकिन हिंदुस्तान में न वित्त मंत्री ने कुछ कहा, न ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई बयान दिया. रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधियों ने जो चिंताएं बताईं, वे चिंताएं कैसी हैं. इन चिंताओं की गंभीरता कितनी है. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ डील बचाने के लिए कंपनी ने माना कि भारत के रिज़र्व बैंक को दिए जा रहे करेंसी पेपर के उत्पादन में जो ग़लतियां हुईं, वे गंभीर हैं. बाद में कंपनी के चीफ एक्जीक्यूटिव जेम्स हसी को 13 अगस्त, 2010 को इस्तीफ़ा देना पड़ा. ये ग़लतियां क्या हैं, सरकार चुप क्यों है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों ख़ामोश है. मज़ेदार बात यह है कि कंपनी के अंदर इस बात को लेकर जांच चल रही थी और एक हमारी संसद है, जिसे कुछ पता नहीं है.

5 जनवरी, 2011 को यह ख़बर आई कि भारत सरकार ने डे ला रू के साथ अपने संबंध ख़त्म कर लिए. पता यह चला कि 16,000 टन करेंसी पेपर के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने डे ला रू की चार प्रतियोगी कंपनियों को ठेका दे दिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डे ला रू को इस टेंडर में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित भी नहीं किया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार ने इतना बड़ा फ़ैसला क्यों लिया. इस फ़ैसले के पीछे तर्क क्या है. सरकार ने संसद को भरोसे में क्यों नहीं लिया. 28 जनवरी को डे ला रू कंपनी के टिम कोबोल्ड ने यह भी कहा कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि डे ला रू का अब आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोई समझौता होगा या नहीं. इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी डे ला रू से कौन बात कर रहा है और क्यों बात कर रहा है. मज़ेदार बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ख़ामोश रहा.

इस तहक़ीक़ात के दौरान एक सनसनीखेज सच सामने आया. डे ला रू कैश सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 2005 में सरकार ने दफ्तर खोलने की अनुमति दी. यह कंपनी करेंसी पेपर के अलावा पासपोर्ट, हाई सिक्योरिटी पेपर, सिक्योरिटी प्रिंट, होलोग्राम और कैश प्रोसेसिंग सोल्यूशन में डील करती है. यह भारत में असली और नक़ली नोटों की पहचान करने वाली मशीन भी बेचती है. मतलब यह है कि यही कंपनी नक़ली नोट भारत भेजती है और यही कंपनी नक़ली नोटों की जांच करने वाली मशीन भी लगाती है. शायद यही वजह है कि देश में नक़ली नोट भी मशीन में असली नज़र आते हैं. इस मशीन के सॉफ्टवेयर की अभी तक जांच नहीं की गई है, किसके इशारे पर और क्यों? जांच एजेंसियों को अविलंब ऐसी मशीनों को जब्त करना चाहिए, जो नक़ली नोटों को असली बताती हैं. सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि डे ला रू कंपनी के रिश्ते किन-किन आर्थिक संस्थानों से हैं. नोटों की जांच करने वाली मशीन की सप्लाई कहां-कहां हुई है.

हमारी जांच टीम को एक सूत्र ने बताया कि डे ला रू कंपनी का मालिक इटालियन माफ़िया के साथ मिलकर भारत के नक़ली नोटों का रैकेट चला रहा है. पाकिस्तान में आईएसआई या आतंकवादियों के पास जो नक़ली नोट आते हैं, वे सीधे यूरोप से आते हैं. भारत सरकार, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और देश की जांच एजेंसियां अब तक नक़ली नोटों पर नकेल इसलिए नहीं कस पाई हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां अब तक इस मामले में पाकिस्तान, हांगकांग, नेपाल और मलेशिया से आगे नहीं देख पा रही हैं. जो कुछ यूरोप में हो रहा है, उस पर हिंदुस्तान की सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चुप है.

अब सवाल उठता है कि जब देश की सबसे अहम एजेंसी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया, तब सरकार ने क्या किया. जब डे ला रू ने नक़ली नोट सप्लाई किए तो संसद को क्यों नहीं बताया गया. डे ला रू के साथ जब क़रार ख़त्म कर चार नई कंपनियों के साथ क़रार हुए तो विपक्ष को क्यों पता नहीं चला. क्या संसद में उन्हीं मामलों पर चर्चा होगी, जिनकी रिपोर्ट मीडिया में आती है. अगर जांच एजेंसियां ही कह रही हैं कि नक़ली नोट का काग़ज़ असली नोट के जैसा है तो फिर सप्लाई करने वाली कंपनी डे ला रू पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई. सरकार को किसके आदेश का इंतजार है. समझने वाली बात यह है कि एक हज़ार नोटों में से दस नोट अगर जाली हैं तो यह स्थिति देश की वित्तीय व्यवस्था को तबाह कर सकती है. हमारे देश में एक हज़ार नोटों में से कितने नोट जाली हैं, यह पता कर पाना भी मुश्किल है, क्योंकि जाली नोट अब हमारे बैंकों और एटीएम मशीनों से निकल रहे हैं.

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 3
दिल्ली, 28 मार्च–03 अप्रैल 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन व प्रसार +91 120 4783999
+91 9871194800
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16+4+4+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

तमिलनाडु की बात करें तो यहां एक अजीब सी स्थिति दिख रही है. घपले-घोटालों में नाक तक फंसी द्रमुक आख़िर कैसे मतदाताओं को सफ़ाई देगी.

विधानसभा चुनाव

जनता की समस्याएं और चुनौतियां

शशि शेखर

पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में अभी तक बात समीकरणों की हो रही है, संभावनाओं की हो रही है. कौन बनेगा मुख्यमंत्री या किस दल का किस दल के साथ गठबंधन होगा और किन शर्तों पर होगा. लेकिन इस सबके बीच जनता की बात यानी जनता की समस्याओं पर चर्चा जितनी होनी चाहिए, नहीं हो रही है. पश्चिम बंगाल में 34 सालों से वामपंथ का शासन है, लेकिन इस बार हालात थोड़े बदले नज़र आ रहे हैं. ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में वामपंथी दलों को गहरा झटका दिया था. नंदीग्राम और सिंगूर की घटना के बाद वामपंथी दल सचेत ज़रूर हुए हैं. यूपीए की नीतियों, महंगाई, 2-जी स्पेक्ट्रम और राष्ट्रमंडल खेल जैसे घोटालों को वामपंथी दल ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ अपना मज़बूत हथियार मान रहे हैं.

ममता बनर्जी को फायर ब्रांड नेता माना जाता है. वह विरोध की राजनीति पर सवार होकर आज सत्ता का लाभ ले रही हैं. बंगाल चुनाव में भले ही ममता को अपने तेवरों का फ़ायदा मिलता दिख रहा हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उनके पास पश्चिम बंगाल के लिए कोई एजेंडा है. ऐसा माना जा रहा है कि माओवादी ममता के पक्ष में हैं. कहा जा रहा है कि नंदीग्राम और सिंगूर में सीपीएम की रेड ब्रिगेड के ख़िलाफ़ तृणमूल कांग्रेस के संघर्ष को माओवादियों की ओर से मदद मिली. ममता बनर्जी सीपीएम के पिछले 34 सालों के शासन के दौरान पश्चिम बंगाल की हुई दुर्दशा को इस चुनाव में अपना मुख्य मुद्दा बनाना चाहती हैं, लेकिन नैनो जैसी परियोजना के विरोध के बाद ममता क्या जनता को बताएंगी कि अगर वह सत्ता में आती हैं तो पश्चिम बंगाल का विकास कैसे करेंगी? क्या सिर्फ़ सीपीएम को सत्ता से बेदख़ल कराकर ही वह पश्चिम बंगाल का भला कर देंगी? आख़िर उनके पास पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यकों के लिए क्या योजनाएं हैं, मज़दूरों के लिए क्या योजनाएं हैं और बेरोज़गार युवाओं के लिए क्या योजनाएं हैं...

ममता बनर्जी को फायर ब्रांड नेता माना जाता है. वह विरोध की राजनीति पर सवार होकर आज सत्ता का लाभ ले रही हैं. बंगाल चुनाव में भले ही ममता को अपने तेवरों का फ़ायदा मिलता दिख रहा हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उनके पास पश्चिम बंगाल के लिए कोई एजेंडा है.

असम अपनी क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर काफ़ी संवेदनशील रहा है. बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला यहां हमेशा से विवाद और हिंसा का कारण बनता रहा है. इस मुद्दे पर कांग्रेस और असम गण परिषद अपनी-अपनी राजनीति करती रही हैं और अभी भी कर रही हैं. ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि अवैध रूप से आकर रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए कांग्रेस का वोट बैंक हैं. इसकी वजह से असम जब-तब हिंसा की आग में जलता रहा है.

केरल में दलित ईसाइयों की हालत भी कम ख़राब नहीं है. आम तौर पर माना जाता है कि यह समुदाय आर्थिक तौर पर अपेक्षाकृत मज़बूत है, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है. जाति व्यवस्था यहां भी है. अगड़े-पिछड़े का मसला यहां भी है. यही हालत मुसलमानों में भी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की है.

ममता बनर्जी ने रेल मंत्री के नाते जिस ढंग से इस बार रेल बजट में बंगाल को तोहफ़े दिए, उससे दिख रहा था कि ममता ने यह बजट क्यों और किसे ध्यान में रखते हुए बनाया था, लेकिन उन्हें यह भी याद रखना होगा कि वह जिस सरकार में मंत्री हैं, वह सरकार महंगाई, घोटालों और भ्रष्टाचार के लिए भी ज़िम्मेदार है और इस बार जनता की याददाश्त भी कमज़ोर नहीं रहने वाली. नतीजतन, यह मानना भी सही नहीं होगा कि जनता आंख मूंदकर तृणमूल को समर्थन दे देगी. दूसरी ओर बुद्धदेव भट्टाचार्य भले ही भद्र लोक हों, लेकिन भारतीय राजनीति में जनता को भद्र लोक से ज़्यादा ज़रूरत विकास की है. जनता को ऐसा नेता चाहिए, जो सिर्फ़ विकास की बात ही न करें, बल्कि विकास भी करे. इस हिसाब से बुद्धदेव भट्टाचार्य विकास के मोर्चे पर असफल रहे. नंदीग्राम और सिंगूर का उदाहरण सामने है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल में उद्योग एवं कल-कारख़ाने जिस तेज़ी से बंद हुए, जूट मिलों का जो बुरा हाल हुआ, उससे बंगाल की आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई. माओवाद का बढ़ता प्रभाव भी अलग से एक समस्या बना.

बहरहाल, अब सवाल यह है कि इस सबके बीच जनता क्या करे? जनता की तो अपनी समस्याएं हैं, बेरोज़गार युवाओं की एक लंबी फ़ौज है, भूमिहीन किसानों और मज़दूरों की अच्छी-ख़ासी संख्या है, पश्चिम बंगाल से उद्योग-धंधे न जाने कब अपना बोरिया-बिस्तर बांध चुके हैं और नक्सल समस्या का हाल-फ़िलहाल कोई समाधान होता नहीं दिख रहा है. अब ऐसे में जनता किसे चुने, सीपीम को या नए सपने दिखा रही तृणमूल को? वैसे पश्चिम बंगाल सरकार ग़रीबों, मज़दूरों और मुसलमानों का ध्यान रखने का दावा तो करती रही है, लेकिन एक चौथाई आबादी मुसलमानों की होने के बावजूद राज्य की नौकरियों में सिर्फ़ 2.1 प्रतिशत मुसलमान हैं. केरल में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत लगभग बराबर है, पर वहां राज्य सरकार की नौकरियों में साढ़े दस प्रतिशत मुसलमान हैं.

केरल की हालत भी पश्चिम बंगाल से कुछ अलग नहीं है. यहां भी वामपंथी दलों को अपनी कुर्सी हिलती नज़र आ रही है. भ्रष्टाचार के मामले एक-एक करके वामपंथी सरकार को कठघरे में लाते रहे. मुख्यमंत्री बी एस अच्युतानंदन और राज्य माकपा के सचिव एम विजयन के बीच लगातार जारी संघर्ष ने पार्टी की छवि धूमिल करने का काम किया. अगर राज्य की जनता की समस्याओं पर ग़ौर करें तो पाते हैं कि अब तक केरल ने जो कुछ भी हासिल किया था, वह ख़त्म होने लगा है. यहां की सिर्फ़ दस प्रतिशत आबादी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 41 प्रतिशत उपभोग करती है. ग़रीब परिवारों से आने वाले 54 प्रतिशत लोग बेरोज़गार हैं, जबकि प्रभावशाली परिवारों के मामले में यह आंकड़ा 24.8 प्रतिशत है. केरल की अर्थव्यवस्था में उन लाखों लोगों की भी बड़ी भूमिका रही है, जो खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं, लेकिन केरल अपनी इस ताक़त का बेहतर इस्तेमाल कर पाने में असफल रहा. पर्यटन भी यहां एक बड़ा उद्योग साबित हो सकता था, जो नहीं हुआ. अगर राज्य सरकार इस पर समुचित ध्यान देती तो यहां से बेरोज़गारी की समस्या ख़त्म हो सकती थी, पलायन में भी कमी आती. ज़ाहिर है, राजनीतिक दल बेहतर अवसरों का इस्तेमाल नहीं कर पाए. आत्महत्याओं के मामले में केरल देश भर में अव्वल है. केरल में दलित ईसाइयों की हालत भी कम ख़राब नहीं है. आम तौर पर माना जाता है कि यह समुदाय आर्थिक तौर पर अपेक्षाकृत मज़बूत है, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है. जाति व्यवस्था यहां भी है. अगड़े-पिछड़े का मसला यहां भी है. यही हालत मुसलमानों में भी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की है. इस हालत में यह ज़रूरी हो जाता है कि यहां की सरकार इनके बारे में सोचें और सच्चर कमेटी एवं रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट को आधार मानते हुए इनके विकास के लिए ज़रूरी क़दम उठाए जाएं.

तमिलनाडु की बात करें तो यहां एक अजीब सी स्थिति दिख रही है. घपले-घोटालों में नाक तक फंसी द्रमुक आख़िर कैसे मतदाताओं को सफ़ाई देगी, इस सवाल का जवाब भी जनता को ख़ुद ही ढूंढना है? पहले राजा 2-जी स्पेक्ट्रम में फंसे, फिर उनकी गिरफ़्तारी हुई और अब कनिमोझी से सीबीआई की पूछताछ. कुछ इन्हीं सवालों के बीच इस बार द्रमुक चुनाव में उतरने जा रही है. असल में तमिलनाडु में चुनाव के दौरान भावनात्मक मुद्दे और लुभावने वादे ख़ूब काम करते हैं. मसलन रंगीन टीवी बांटकर भी यहां राजनीतिक दल सत्ता पा जाते हैं, लेकिन असल समस्याएं जस की तस रह जाती हैं. उम्मीद यही है कि जनता इस बार भावनात्मक मुद्दों के बजाय अपनी असल समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों का जवाब राजनीतिक दलों से मांगेगी.

इस चुनाव में कांग्रेस को असम में अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए ख़ासी मशक्कत करनी पड़ेगी. पूर्वी भारत का यह अहम राज्य चौतरफा समस्याओं से घिरा हुआ है. असम अपनी क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर काफ़ी संवेदनशील रहा है. बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला यहां हमेशा से विवाद और हिंसा का कारण बनता रहा है. इस मुद्दे पर कांग्रेस और असम गण परिषद अपनी-अपनी राजनीति करती रही हैं और अभी भी कर रही हैं. ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि अवैध रूप से आकर रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए कांग्रेस का वोट बैंक हैं. इसकी वजह से असम जब-तब हिंसा की आग में जलता रहा है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कुछ ठोस उपाय नहीं किया गया है. औद्योगिक विकास के नाम पर यहां शून्यता की स्थिति है. चाय बाग़ान के हालात उल्फ़ा एवं उग्रवादियों की वजह से ख़राब है. चाय बाग़ान में काम करने वाले मज़दूरों का रोज़गार छिन रहा है. असम में अल्पसंख्यकों की मौजूदगी अच्छी-ख़ासी संख्या में है, लेकिन उनकी हालत भी दयनीय है. एक और मुद्दा है बाढ़ का. पिछले साठ वर्षों से असम में हर साल बाढ़ का तांडव होता रहा है. इस वजह से ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के स्वरूप में परिवर्तन आया और उसके बाद हर साल बाढ़ तबाही के मंज़र दिखाने लगी. सरकार बाढ़ से होने वाली तबाही से राहत दिलाने के नाम पर पैसे तो ख़र्च करती है, लेकिन इस समस्या का एक स्थायी समाधान ढूंढ सकने में विफल रही है.

बहरहाल, पांचों राज्यों में सत्ताधारी दल या गठबंधन को अपनी कुर्सी बचाने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाना पड़ेगा. ख़ैर, यह चुनाव जनता के पास एक मौक़ा है. मौक़ा एक ऐसा नेता चुनने का, जो उनकी समस्याओं को समझे, महसूस करे और उनके समाधान के लिए हरसंभव कोशिश करे. अगर जनता यह मौक़ा गंवाती है तो एक बार फिर पांच साल तक पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा.

shashekhar@chauthiduniya.com

विधान परिषद की आश्वासन समिति में जदयू के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह द्वारा ध्यानाकर्षण के माध्यम से शिव लखन सिंह एवं सुरेश पासवान पर लगे आरोपों की जांच चल रही है.

पटना विधि विज्ञान प्रयोगशाला

सुशासन और विकास का कड़वा सच

फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

न्याय के साथ विकास और अपराध–भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने की बातें अच्छी लगती हैं तथा नीतीश कुमार ने अपना यह वादा पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश भी की, लेकिन क़ानून का राज अभी पूरी तरह क़ायम नहीं हुआ है. क़ानून का पालन कराने वाली एजेंसी ईमानदारी से काम नहीं कर रही है. पुलिस की कार्यशैली जस की तस है. अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) की स्थिति तो और भी दयनीय है. इसके अंतर्गत कार्यरत विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल), जिसकी रिपोर्ट किसी को गुनाहगार या बेगुनाह साबित करती है और जिसे अदालत फ़ैसला करते समय महत्व देती है, भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है. इसकी रिपोर्ट अब विश्वसनीय नहीं होती, यहां रिपोर्ट देने में पैसों का खुला खेल चलता है. इसकी ग़लत रिपोर्ट के कारण सैकड़ों बेक़सूर जेल की यातना भुगतने के लिए अभिशप्त हैं.

दुर्भाग्यवश विधि विज्ञान प्रयोगशाला गृह (आरक्षी) विभाग के अधीन काम करती है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है. यह प्रयोगशाला वर्षों से सरकारी उपेक्षा की शिकार है और अधिकारियों–कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है. इसकी हर प्रशाखा में निचले स्तर के कर्मचारियों और उच्चाधिकारियों का अभाव है. जांच रिपोर्ट देने का काम अप्रशिक्षित एवं अनाधिकृत कर्मचारी कर रहे हैं. एफएसएल में निदेशक और उप निदेशक के एक–एक पद सृजित हैं. डॉ. सैयद रियाजुल हसन की सेवानिवृत्ति के कारण निदेशक का पद एक अप्रैल, 1995 और दिनेश प्रसाद की सेवानिवृत्ति की वजह से उप निदेशक का पद एक फ़रवरी, 2001 से ख़ाली है. सहायक निदेशक को प्रभार देकर निदेशक का काम लिया जा रहा है. विष विज्ञान प्रशाखा में सृजित वरीय वैज्ञानिकों के दोनों पद प्रमोद कुमार झा एवं सुब्रत गुप्ता के सहायक निदेशक पद पर प्रोन्नत होने के बाद 26 अप्रैल, 1996 से ख़ाली हैं. सहायक निदेशक का स्वीकृत एकल पद एक जून, 2002 से रिक्त है. वरीय वैज्ञानिक सहायक तीन की जगह एक और प्रयोगशाला सहायक छह की जगह पांच कार्यरत हैं. विस्फोटक प्रशाखा में सहायक निदेशक का एक पद स्वीकृत है, जो पंचानन उपाध्याय के सेवानिवृत्त होने के बाद एक जून, 2001 से रिक्त है. प्रशाखा में दो प्रयोगशाला सहायकों की जगह एक सहायक कार्यरत है.

जीव विज्ञान प्रशाखा में सहायक निदेशक का पद रमाशंकर सिंह के झारखंड चले जाने से 8 जुलाई, 2006 से ख़ाली है और वरीय वैज्ञानिकों के दोनों पद ख़ाली हैं. इनमें से एक पद विनोद शंकर की उप निदेशक पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप एक जून, 1996 और दूसरा एक जनवरी, 1997 को ख़ाली हुआ था. प्रयोगशाला सहायक के 5 स्वीकृत पदों के विरुद्ध मात्र 3 सहायक काम कर रहे हैं. सामान्य रसायन प्रशाखा में एक फ़रवरी, 2003 से सहायक निदेशक नहीं है. सीरम विज्ञान प्रशाखा में सहायक निदेशकों के दो पद अलख निरंजन प्रसाद की उप निदेशक पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप 16 फ़रवरी, 1995 और धनंजय मिश्र की सेवानिवृत्ति के कारण एक मार्च, 2001 से रिक्त हैं. आग्नेयास्त्र प्रशाखा में एक अगस्त, 2001 से सहायक निदेशक नहीं है. यह पद विनोद कुमार मिश्र के सेवानिवृत्त होने से रिक्त हुआ है. इस प्रशाखा में वरीय वैज्ञानिक के स्वीकृत 4 पदों के विरुद्ध मात्र एक डॉ. अनिल कुमार सिन्हा काम कर रहे हैं. उपकरण प्रशाखा में सहायक निदेशक का पद भी खाली हो गया है. भौतिकी प्रशाखा में एक जनवरी, 2003 से सहायक निदेशक नहीं है और प्रयोगशाला सहायक के दोनों पद ख़ाली हैं.

अब बात करें एफएसएल द्वारा निर्गत रिपोर्ट्स की. इसकी विष विज्ञान प्रशाखा में बिसरा की जांच की जाती है. नियमत: प्रशाखा में तैनात सहायक निदेशक एवं वरीय वैज्ञानिकों (प्रशिक्षित राजपत्रित पदाधिकारी) द्वारा गठित टीम को बिसरा की जांच करनी चाहिए और परिणाम की रिपोर्ट सहायक निदेशक के हस्ताक्षर और निदेशक/प्रभारी निदेशक के प्रति हस्ताक्षर से निर्गत होनी चाहिए, लेकिन इस प्रशाखा में सहायक निदेशक का पद जून 2002 और वरीय वैज्ञानिकों के दोनों पद क़रीब डेढ़ दशक से रिक्त हैं. ऐसी स्थिति में इस प्रशाखा में बिसरा की जांच नहीं हो सकती है. बावजूद इसके जांच हो रही है और जांच प्रतिवेदन भी निर्गत किए जा रहे हैं तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारी सुरेश पासवान के हस्ताक्षर से क़रीब 560 बिसरा जांच प्रतिवेदन निर्गत हो चुके हैं. गृह (आरक्षी) विभाग के अवर सचिव के पत्र संख्या–6/विप–04/2009 गृ.आ. 7160 पटना, 28–10–09 और पुलिस अधीक्षक सीआईडी के पत्र संख्या–705/स्था. 29–07–09 में साफ़ कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 293 के तहत बिसरा जांच प्रतिवेदन पर सुरेश पासवान, जो प्रौद्योगिकी पदाधिकारी अराजपत्रित हैं, हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत नहीं हैं. इन पत्रों में प्रभारी निदेशक के रूप में डॉ. श्याम बिहारी उपाध्याय का नाम है. सुरेश पासवान को विष विज्ञान प्रशाखा एवं नारकोटिक्स में काम करने का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है. एफएसएल के ज्ञापांक 1323, 8–12–08 अंतर्गत तत्कालीन एवं वर्तमान प्रभारी निदेशक उमेश कुमार सिन्हा द्वारा सुरेश पासवान को जांच प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने का आदेश प्रदान किया गया था. इस सबके पीछे नाजायज़ कमाई एक बड़ा कारण है. उदाहरण के तौर पर बिसरा जांच प्रतिवेदन 54/2008 को लिया जा सकता है. फतुहा थाना कांड संख्या– 257/07 से संबंधित और 3 जुलाई, 2008 को निर्गत इस रिपोर्ट पर बतौर प्रभारी निदेशक शिव लखन सिंह के प्रति हस्ताक्षर एवं टेक्निकल ऑफिसर के रूप में सुरेश पासवान के हस्ताक्षर हैं. गृह (आरक्षी) विभाग की अधिसूचना के अनुसार, फ़रवरी 2008 से डॉ. श्याम बिहारी उपाध्याय प्रभारी निदेशक हैं, लेकिन बतौर प्रभारी निदेशक जांच प्रतिवेदनों पर प्रति हस्ताक्षर शिव लखन सिंह ने किए हैं, जबकि वह उपकरण प्रशाखा के सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत थे. प्रभारी निदेशक के रहते उनकी जगह शिव लखन सिंह द्वारा प्रभारी निदेशक के रूप में प्रति हस्ताक्षर करने का आख़िर क्या कारण था?

मेडिकल साइंस के मुताबिक़, मानव अंग बिसरा के रूप में काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता, लेकिन फतुहा थाना कांड संख्या 257/07 में बिसरा एफएसएल पहुंचते ही ख़राब हो गया. जानकारों के मुताबिक़, एफएसएल पटना द्वारा निर्गत रिपोर्ट्स में सम डार्क ब्राउन फ्लूड इसलिए लिखा जाता है और आशंका व्यक्त की जाती है कि वह बिसरा का गला रूप हो सकता है, ताकि उसकी दोबारा जांच न कराई जा सके. रिपोर्ट में थाइमेट पाना लिखा गया है, जबकि जांच से पता नहीं लगाया जा सकता कि किस ब्रांड की दवा/ज़हर का इस्तेमाल किया गया है. मसलन थाइमेट का निर्माण वायर कंपनी करती है और इसी कंपोजिशन के कीटनाशक का निर्माण दूसरी कंपनी पारामार नाम से करती है. इसलिए किसी भी जांच से पता नहीं किया जा सकता कि किस व्यक्ति की मृत्यु थाइमेट या पारामार खाने या खिलाने से हुई है, लेकिन इस रिपोर्ट में स्पष्ट थाइमेट का उल्लेख किया गया है, जो बिना जांच के किसी प्रकार के प्रभाव में आकर लिखा गया लगता है. इसी मामले में नालंदा मेडिकल कॉलेज से जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चार अंगों की हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट में भी ऐसी कोई बात नहीं पाई गई. एक अन्य रिपोर्ट एफएसएल 1233/2007 में भी यही किया गया.

जीव विज्ञान प्रशाखा में सहायक निदेशक का पद रमाशंकर सिंह के झारखंड चले जाने से 8 जुलाई, 2006 से ख़ाली है और वरीय वैज्ञानिकों के दोनों पद ख़ाली हैं. इनमें से एक पद विनोद शंकर की उप निदेशक पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप एक जून, 1996 और दूसरा एक जनवरी, 1997 को ख़ाली हुआ था. प्रयोगशाला सहायक के 5 स्वीकृत पदों के विरुद्ध मात्र 3 सहायक काम कर रहे हैं. सामान्य रसायन प्रशाखा में एक फ़रवरी, 2003 से सहायक निदेशक नहीं है.

अपराध अनुसंधान विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक यशवंत मल्होत्रा के ज्ञापांक 193 (ए), 16–09–08 में स्पष्ट अंकित है कि इस प्रयोगशाला में डीएनए की जांच मशीन से नहीं की जाती. कई सालों से यह मशीन ख़राब पड़ी है. वहीं सीआईडी के पुलिस अधीक्षक (सी) के पत्रांक 02, 07–01–09 के अनुसार एफएसएल पटना से 3 डीएनए जांच रिपोर्ट जारी की गई हैं. इनमें से एक रिपोर्ट एफएसएल–600, 04–09–08 को जारी की गई है, जिस पर रिपोर्टिंग ऑफिसर के रूप में टेक्नीशियन शिव कुमार और तत्कालीन प्रभारी डॉ. श्याम बिहारी उपाध्याय के हस्ताक्षर हैं. यहां नियुक्ति एवं प्रोन्नति का खेल भी निराला है. हाल में उप निदेशक के पद पर प्रोन्नत शिव लखन सिंह इसके उदाहरण हैं. उनकी नियुक्ति 1983 में आग्नेयास्त्र प्रशाखा में वरीय वैज्ञानिक के पद पर हुई थी. पुलिस मैनुअल के अनुसार उन्हें आग्नेयास्त्र प्रशाखा में ही प्रोन्नति दी जा सकती है, वह भी कम से कम 6 वर्षों का कार्यानुभव होने पर. जिस प्रशाखा में वरीय वैज्ञानिक का पद सृजित नहीं है, वहां सहायक निदेशक के पद पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है. उपकरण प्रशाखा में चूंकि वरीय वैज्ञानिक का पद सृजित नहीं है, इसलिए वहां सहायक निदेशक के पद पर बीपीएससी के ज़रिए नियुक्ति की जानी चाहिए थी, परंतु बिना विज्ञापन निकाले और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से रोस्टर क्लीयरेंस लिए शिव लखन सिंह को आग्नेयास्त्र प्रशाखा से उपकरण प्रशाखा का सहायक निदेशक बना दिया गया. इनकी नियुक्ति से संबंधित गृह (आरक्षी) विभाग की संचिका–6/विविप्र में यह बात स्पष्ट रूप से अंकित है. शिव लखन सिंह द्वारा अपनी नियुक्ति के संबंध में भी परस्पर विरोधी सूचनाएं दी गईं, जो एक तरह से सूचना अधिकार क़ानून का मखौल उड़ाना है. ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई न होना आश्चर्य की बात है.

मालूम हो कि शिव लखन सिंह को कभी भी गृह (आरक्षी) विभाग द्वारा प्रभारी निदेशक बनाने की अधिसूचना जारी नहीं की गई. प्रभारी निदेशक के स्थानांतरण के समय उन्हें इस पद का प्रभार रूटीन वर्क के लिए सौंपा गया था. प्रभार में रहने वाला व्यक्ति सिर्फ़ रूटीन कार्य कर सकता है. उसे प्रभारी निदेशक के रूप में प्रति हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं है, लेकिन शिव लखन सिंह ऐसा करते रहे हैं. चकित करने वाली बात यह है कि लोकायुक्त कार्यालय में शिव लखन सिंह के ख़िलाफ़ चार परिवाद दायर रहने और निगरानी विभाग में शिकायत लंबित रहने के बावजूद ज्ञापन संख्या–6/सी–1–016/2007 गृ.आ. 6042, 23–07–10 द्वारा उन्हें प्रोन्नति देकर उप निदेशक बना दिया गया. उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त के यहां 2007 में मेंहदिया (अरवल) के राम नरेश सिंह ने परिवाद संख्या 237/07, तत्कालीन विधायक सुनीला देवी ने परिवाद संख्या 35/09 और फतुहा निवासी अधिवक्ता रत्नेश कुमार पाठक ने परिवाद संख्या 227/09 दर्ज कराया था. लोकायुक्त कार्यालय ने इन तीनों मामलों को जांच के लिए गृह (आरक्षी) विभाग के प्रधान सचिव को भेजा था. विधान परिषद की आश्वासन समिति में जदयू के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह द्वारा ध्यानाकर्षण के माध्यम से शिव लखन सिंह एवं सुरेश पासवान पर लगे आरोपों की जांच चल रही है. 30–07–09 को सदन को आश्वस्त किया गया कि मामले की जांच नए पुलिस महानिदेशक आनंद शंकर से कराई जाएगी, लेकिन आश्वासन समिति ने जांच के लिए मामले को पुलिस महानिदेशक के बजाय स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के पास भेज दिया. क्या जांच हुई, पता नहीं? अधिवक्ता रत्नेश कुमार पाठक द्वारा निगरानी में शिव लखन सिंह एवं सुरेश पासवान के विरुद्ध दर्ज परिवाद पर भी जांच चल रही है. हैरत वाली बात यह है कि गृह (आरक्षी) विभाग से शिव लखन सिंह की आग्नेयास्त्र प्रशाखा से उपकरण प्रशाखा में प्रोन्नति से संबंधित विवादित संचिका ग़ायब है.

सुनीला देवी और राम नरेश सिंह के परिवादों की जांच के लिए गृह (आरक्षी) विभाग में खोली गई संचिका–6/विविप्र–01–08–08 में प्रोन्नति से संबंधित संचिका–6/सी–1–21/07 के ग़ायब होने और इसके न मिलने तक कोई निर्णय न लिए जाने का उल्लेख है. जानकारों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि शिव लखन सिंह के अनुचित क्रियाकलापों, ग़लत/अवैध पदस्थापन को रद्द/निरस्त करने संबंधी विधान परिषद (आश्वासन समिति), लोकायुक्त एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में जांच लंबित होने के बावजूद उन्हें प्रोन्नति किस प्रकार दी गई, जबकि उन्हें लोकायुक्त कार्यालय के पत्र संख्या–4/लोक (स्वच्छता) गृ.आ. 02/2002 पार्ट 178 लोक, 15–01–10 और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक–1732 जांशा, 11–12–09 द्वारा स्वच्छता प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया गया. अधिवक्ता पाठक ने इस गोरखधंधे से राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को 15 नवंबर, 2010 और राज्यपाल को 29 नवंबर, 2010 को लिखित रूप से अवगत कराकर कार्रवाई की अपेक्षा की है, लेकिन इस दिशा में कुछ होता नहीं दिख रहा है.

अधिवक्ता पाठक के आवेदन का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग की अवर सचिव आशा सोटा ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को 14 दिसंबर, 2010 को आवश्यक कार्रवाई के लिए एक पत्र भी लिखा है.

कुमुद सिंह
feedback@chauthiduniya.com

गोगोई विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहते हैं कि विरोधी दलों के नेताओं के पास चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे भ्रष्टाचार का झूठा डंका पीट रहे हैं.

असम

विपक्षी एकजुटता ज़रूरी

अरुण कुमार झा

भ्रष्टाचार को लेकर गोगोई सरकार पर विपक्षी हमला बढ़ता जा रहा है. असम गण परिषद और भारतीय जनता पार्टी असम से लेकर दिल्ली तक इस मामले को लेकर आवाज़ बुलंद कर रही हैं. भाजपा ने असम के साथ-साथ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में 63,000 करोड़ रुपये के घोटालों का पर्दाफाश करने का दावा किया है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को एक पत्र सौंपकर इस पूरे घोटाले की निष्पक्ष जांच का अनुरोध किया है. भाजपा का आरोप है कि असम सहित पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में विकास मद की केंद्रीय राशि की लूट मची है. असम के उत्तर कछार ज़िले में ही एक हज़ार करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला उजागर हुआ है और कथित रूप से इसमें राज्य के सात मंत्रियों, एक पूर्व राज्यपाल एवं कुछ सांसदों की संलिप्तता बताई जा रही है. इसके अलावा खाद्यान्न, परिवहन एवं वन विभागों में भी घोटाले सामने आए हैं. एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में असम को देश का सबसे भ्रष्ट राज्य घोषित किया गया है. ऐसे में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ असम में विपक्षी दलों द्वारा चलाई जा रही मुहिम तभी सफल होगी, जब संपूर्ण विपक्ष एकजुट हो. विपक्षी एकजुटता के बग़ैर गोगोई सरकार को उखाड़ फेंकना आसान नहीं होगा. भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद के नेताओं को इस बारे में विचार करना चाहिए.

विधानसभा चुनाव में अगर वोटों का बंटवारा होता है तो इसका सबसे ज़्यादा लाभ कांग्रेस ही उठा सकती है. भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक गुवाहाटी में आयोजित करके यह दर्शाने का प्रयास किया है कि असम एवं पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के हालात को लेकर पार्टी काफ़ी गंभीर है. हाल में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं आडवाणी, गडकरी, सुषमा, जेटली, राजनाथ सिंह एवं कई अन्य नेताओं ने साफ़ कर दिया कि अगर असम में कांग्रेसी शासन का अंत नहीं हुआ तो आने वाले वर्षों में अवैध घुसपैठ के कारण देश की अखंडता पर प्रश्नचिन्ह लग सकता है. भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी पार्टी चुप नहीं बैठेगी, भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेसी मंत्रियों एवं नेताओं के ख़िलाफ़ पार्टी का अभियान जारी रहेगा. इसी के तहत पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने असम के राज्यपाल से मिलकर भ्रष्ट मंत्रियों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामला चलाने की अनुमति भी मांगी है. पार्टी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह असम की सभी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी. इससे साफ़ हो जाता है कि भाजपा चुनावी तालमेल के मूड में नहीं है. उधर असम गण परिषद भी प्रफुल्ल कुमार महंत एवं चंद्रमोहन पटवारी के नेतृत्व में गोगोई सरकार के ख़िलाफ़ ज़ोरदार तरीक़े से हल्ला बोल अभियान चला रही है. कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अगप के नेताओं ने विभिन्न विभागों में हुए वित्तीय घोटालों के लिए मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को भी ज़िम्मेदार ठहराया है. अगप नेताओं का मानना है कि मुख्यमंत्री के ज़िम्मे वित्त मंत्रालय है, इस वजह से सरकारी विभागों में होने वाली किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए वह सीधे तौर पर ज़िम्मेदार हैं. पूर्व मुख्यमंत्री एवं अगप के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल कुमार महंत को विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य के मतदाता गोगोई सरकार को नकार देंगे. अगप के अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने भी आशा जताई है कि पार्टी एकजुट होकर कांग्रेस की असम विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ चुनाव में उतरेगी. अगप के अंदर कितनी एकजुटता है, इसका पर्दाफ़ाश उस समय हो गया, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता सर्वानंद सोनोवाल कई अन्य नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए. चंद्रमोहन पटवारी भले ही सर्वानंद सोनोवाल के जाने से पार्टी पर कोई असर न होने की बात कह रहे हों, लेकिन अगप के अंदर असंतुष्टों की सुगबुगाहट बढ़ने लगी है. पटवारी और महंत अगप की एकजुटता को क़ायम रख पाने में कितने सफल हो पाते हैं, इसका पता तो टिकटों के बंटवारे के बाद ही चल पाएगा. वैसे अगप राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर लड़ने का मन बना चुकी है.

इस बीच कांग्रेस भी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ विपक्षी पार्टियों के हमले को नज़रअंदाज करती हुई चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है. मुख्यमंत्री तरुण गोगोई विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहते हैं कि विरोधी दलों के नेताओं के पास चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे भ्रष्टाचार का झूठा डंका पीट रहे हैं. असम में पिछले दस वर्षों के दौरान विकास की जो आंधी चली है, उससे विपक्षी दलों में खलबली मची हुई है. वे समझ रहे हैं कि आगामी चुनाव में मतदाता उनका साथ नहीं देने वाले हैं, इसी बौखलाहट में वे भ्रष्टाचार जैसा आधारहीन मसला उछाल रहे हैं. गोगोई का कहना है कि कांग्रेस समाज के हर तबक़े के उत्थान के लिए काम करती रहेगी. गोगोई एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी असम का दौरा किया. उन्होंने कहा कि असम एवं पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रति केंद्र सरकार सचेत है. यहां की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए कारगर क़दम उठाए जा रहे हैं. उल्फ़ा के साथ वार्ता शुरू होने पर उन्होंने ख़ुशी जताई और कहा कि निकट भविष्य में इसका समाधान निकल आएगा. उन्होंने कहा कि असम से उनका भावनात्मक लगाव है, क्योंकि संसद में वह यहां का प्रतिनिधित्व करते हैं. यही वजह है कि इस क्षेत्र की समस्याओं पर उनका विशेष ध्यान होता है.

इस प्रकार चुनाव के लिए कांग्रेस, भाजपा एवं अगप ने शंखनाद कर दिया है. उधर उल्फ़ा के परेश बरुवा गुट ने कांग्रेस के ख़िलाफ़ सशस्त्र संघर्ष छेड़ने का ऐलान करके चुनावी माहौल में गर्मी पैदा कर दी है. उल्फ़ा के वार्ता समर्थक गुट पर आरोप लग रहे हैं कि उसका झुकाव कांग्रेस की ओर हो सकता है. ऐसे में चुनाव आयोग के लिए इन गुटों की गतिविधियों पर नज़र रखना अनिवार्य हो जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

किसे कितनी सीटें मिली थीं

विधानसभा चुनाव-2006	लोकसभा चुनाव-2009
कुल सीटें-126	कुल सीटें-14
भाजपा-10	भाजपा-04
कांग्रेस-53	कांग्रेस-07
अगप-28	अगप-01
एयूडीएफ-10	एयूडीएफ-01
	बीपीएफ-01

चुनाव कार्यक्रम : अधिसूचना जारी होने की तारीख़-10 मार्च
मतदान-4 अप्रैल

The Thandaiwalas Since 1924

SINCE 1924
मिश्राम्बु®
Mishrambu®
AN ISO 9001: 2008 CERTIFIED COMPANY

प्रीमियम
ठंडाई

www.mishrambu.com
9792445544 / 9839057755

निजी क्षेत्र में भी 31 बड़ी बिजली परियोजनाएं प्रस्तावित हैं. इनमें भी लगभग दस परियोजनाओं का आवंटन किया जा चुका है और 17 प्रोजेक्टों के आवंटन की प्रक्रिया जारी है.

गंगा मैली हो गई

प्रियंका प्रियम तिवारी

एक तरफ़ सरकार नदियों की सफ़ाई और उनके पुनरुद्धार के लिए अरबों रुपये ख़र्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ़ नदियों को मिटाने वाले तमाम काम भी अंजाम दिए जा रहे हैं. विकास के नाम पर हम प्रकृति के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं. इसके लिए हमने सदियों से अपनी सहायक रहीं नदियों को भी नहीं छोड़ा. बिजली पैदा करने के लिए इन नदियों पर एक साथ कई जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं. इनके साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, उससे इनका अस्तित्व ख़तरे में आ गया है. इन परियोजनाओं द्वारा शायद हम बिजली पा लेंगे, लेकिन जब पानी ही नहीं रहेगा तो कृषि कार्य कैसे करेंगे और जब कृषि नहीं होगी तो खाद्यान्न कहां से आएगा. एक तरफ़ हम पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ़ पानी के सबसे बड़े स्रोत नदियों को मिटा रहे हैं. आने वाले समय में पानी की इतनी किल्लत होगी कि कहा जा रहा है, तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा.

भारत की विभिन्न नदियों पर छोटे–बड़े कई बांध हैं, जिनमें 4,500 बड़े बांध हैं. अब तक उत्तरकाशी और गंगोत्री के बीच सिर्फ़ एक यानी मनेरी भाली–1 परियोजना थी, मगर अब इस 125 किलोमीटर लंबे इलाक़े में पांच बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इन परियोजनाओं को कामयाब बनाने के लिए भागीरथी यानी गंगा को अपना मार्ग बदलना होगा. 125 किलोमीटर तक अधिकांश जगहों पर गंगा को सुरंगों में डाल दिया जाएगा. यहां गंगा एक जगह सुरंग से निकलेगी तो कुछ दूरी पर जाकर दूसरी सुरंग में प्रवेश कर जाएगी. सरकार की योजना के मुताबिक़, 2020 तक प्रदेश की बड़ी नदियों पर बिजली परियोजनाओं की संख्या लगभग 115 तक पहुंच जाएगी, जबकि छोटे प्रोजेक्टों की संख्या इससे अलग है. सरकार की योजना के मुताबिक़, अगर प्रस्तावित परियोजनाएं पूरी कर ली जाती हैं तो अकेले सतलुज नदी पर आधारित परियोजनाओं की कुल संख्या 37 हो जाएगी. इसी तरह व्यास नदी पर आधारित परियोजनाओं की संख्या 32, रावी पर 20, चेनाब पर 9 एवं यमुना पर 14 हो जाएगी. मतलब साफ़ है कि हर नदी पर औसतन आठ किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ी बिजली परियोजना लगेगी. इस समय दर्जनों ऐसी बड़ी परियोजनाएं लाइन में हैं, जिन्हें 12वीं पंचवर्षीय योजना में मंज़ूरी मिल जाएगी. 12वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 35 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं प्रस्तावित हैं. केंद्र के साथ साझेदारी में लगने वाली इन बड़ी बिजली परियोजनाओं में चार बड़े प्रोजेक्ट भी शामिल हैं. इन परियोजनाओं के चलते कई नदियों का अस्तित्व पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा.

निजी क्षेत्र में भी 31 बड़ी बिजली परियोजनाएं प्रस्तावित हैं. इनमें भी लगभग दस परियोजनाओं का आवंटन किया जा चुका है और 17 प्रोजेक्टों के आवंटन की प्रक्रिया जारी है. सतलुज नदी बेसिन पर लगने वाली बिजली परियोजनाओं की संख्या सबसे अधिक है. 15 जल विद्युत परियोजनाएं अकेले सतलुज नदी बेसिन पर ही लग रही हैं, जबकि 9 चेनाब नदी, 7 रावी नदी, 3 व्यास नदी और दो यमुना नदी के बेसिन पर प्रस्तावित हैं. जुलाई 2006 में विद्युत उत्पादन के लिए सबसे पहले गंगा पर टिहरी बांध का निर्माण हुआ था. टिहरी से लगभग 50 किलोमीटर दूर धरासू नामक जगह पर मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना है. जनवरी 2008 से यहां विद्युत उत्पादन हो रहा है. योजनानुसार यहां 304 मेगावॉट बिजली बनाई जाएगी, जिसके लिए पानी टरबाइन पर एक निश्चित ऊंचाई से गिरना ज़रूरी है. इस ऊंचाई को पाने के लिए गंगा को 24 किलोमीटर लंबी एक सुरंग से होकर गुज़ारा जाता है, जिससे 24 किलोमीटर तक उसका अस्तित्व ख़त्म हो चुका है. इस क्षेत्र में इतनी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं कि जहां एक परियोजना ख़त्म होती है, वहीं से दूसरी शुरू हो जाती है. मतलब साफ़ है कि गंगा अब सुरंगों में बहा करेगी.

भारत की विभिन्न नदियों पर छोटे-बड़े कई बांध हैं, जिनमें 4,500 बड़े बांध हैं. अब तक उत्तरकाशी और गंगोत्री के बीच सिर्फ़ एक यानी मनेरी भाली-1 परियोजना थी, मगर अब इस 125 किलोमीटर लंबे इलाक़े में पांच बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इन परियोजनाओं को कामयाब बनाने के लिए भागीरथी यानी गंगा को अपना मार्ग बदलना होगा. 125 किलोमीटर तक अधिकांश जगहों पर गंगा को सुरंगों में डाल दिया जाएगा.

आश्चर्य की बात यह है कि यहां जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से पहले यह जानने की कोशिश भी नहीं की गई कि नदियों का पानी इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त है भी या नहीं. इन परियोजनाओं के चलते नदियों का अस्तित्व ख़त्म हो गया, करोड़ों रुपये ख़र्च हुए सो अलग. उसके बाद भी परिणाम लगभग शून्य है. यही वजह है कि टिहरी और मनेरी भाली प्रथम एवं द्वितीय योजनाएं केवल 30 से 35 प्रतिशत विद्युत का ही उत्पादन कर पा रही हैं. इनकी सभी टरबाइनों को चलाने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है. टिहरी दुनिया का आठवां सबसे ऊंचा बांध है. मार्च 2008 तक इस बांध पर कुल 8,298 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे, जो उस अनुमानित लागत से कहीं ज्यादा है, जो परियोजना के प्रारंभ में तय की गई थी. इसकी प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता 2,400 मेगावाट थी, मगर वर्तमान में यह केवल 1000 मेगावॉट बिजली का उत्पादन कर रहा है, यानी क्षमता के आधे से भी कम. वहीं मनेरी भाली वर्तमान में अपनी निर्धारित क्षमता से काफ़ी कम यानी सिर्फ़ 102 मेगावॉट बिजली का उत्पादन कर रहा है. इलाक़े में स्थित तीनों बांध यानी टिहरी और मनेरी प्रथम एवं द्वितीय कभी भी अपनी निर्धारित क्षमता के बराबर विद्युत उत्पादन नहीं कर पाए, जबकि इन सभी परियोजनाओं को मंज़ूरी ही इस आधार पर दी गई थी कि इनमें क्षमता अनुसार शत प्रतिशत उत्पादन होगा.

आंकड़ों के अनुसार, 208 बांधों में से 89 फ़ीसदी अपनी निर्धारित क्षमता से कम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं. 49 फ़ीसदी में तो कुल क्षमता से आधी से भी कम बिजली बन रही है. इससे साफ़ ज़ाहिर है कि बड़ी संख्या में ऐसी परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है और दी जा रही है, जो बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं हैं. बिना सोचे–समझे मंज़ूरी देने का ही अंजाम है कि करोड़ों रुपये ख़र्च हो गए, जनजीवन अस्त–व्यस्त हो गया, बावजूद इसके परियोजनाएं अपने लक्ष्य से कोसों दूर हैं. नोबेल पुरस्कार विजेता इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के मुताबिक़, 2030 तक गंगोत्री ग्लेशियर के आकार में 80 फ़ीसदी तक की कमी आ जाएगी, जिससे गंगा सदानीरा से एक मौसमी नदी में तब्दील हो जाएगी. इसका मतलब है कि अगले 20 सालों में इतना भी पानी नहीं बचेगा कि इन बांधों की टरबाइनें चलाई जा सकें. यही बात जब दिल्ली स्थित टेरी संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र पचौरी ने अपनी रिपोर्ट में कही थी कि हिमालय के हिमनद 2035 तक समाप्त हो जाएंगे, तब इस पर काफ़ी विवाद हुआ. इसके बाद पचौरी को अपना दावा वापस लेना पड़ा था, लेकिन हालात देखकर तो यही लगता है कि उनकी कही बात सत्य थी. हिमनद काफ़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं. गंगोत्री अब तक अपने स्थान से 17 किलोमीटर पीछे खिसक गई है और अभी भी पीछे जा रही है. हिमनदों से पानी का प्रवाह लगातार कम होता जा रहा है. इसके बावजूद सरकार इन विशाल परियोजनाओं के निर्माण को मंज़ूरी दे रही है.

वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने गंगा को दुनिया की उन 10 बड़ी नदियों में रखा है, जिनके अस्तित्व पर ख़तरा मंडरा रहा है. गंगा के बेसिन में बसने वाले करीब 45 करोड़ लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस पर जीविकोपार्जन के लिए निर्भर हैं. कभी हम कहा करते थे कि गंगा तेरा पानी अमृत अथवा गंगा के पानी में अमृत सा गुण मिलता है. पर्यावरणविद् कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया प्रतिरोधी गुण हैं. यही वजह है कि दुनिया की किसी भी नदी के मुकाबले इसके पानी में आक्सीजन का स्तर 25 फ़ीसदी ज्यादा होता है, लेकिन अब यह बीते ज़माने की बात है, क्योंकि अब गंगा सुरंगों में बहेगी, जहां न ऑक्सीजन होती है और न सूरज की रोशनी. जल विद्युत परियोजनाएं नदी के रास्ते का बुनियादी स्वरूप भी बदल देती हैं, जिससे पानी में जैविक बदलाव आ जाते हैं. अब गंगा के पानी को भरकर नहीं रखा जा सकेगा, क्योंकि अब यह अधिक दिनों तक रखने से सड़ जाएगा. जल विद्युत परियोजनाओं के कारण कृषि कार्यों पर भी काफ़ी विपरीत असर पड़ा है. इन परियोजनाओं ने लगभग एक लाख हेक्टेयर उपजाऊ भूमि को बर्बाद कर दिया है. इनके निर्माण और पावर लाइनों को बिछाने के लिए अब तक आठ लाख से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं. पूर्व में निर्मित भाखड़ा एवं पौंग बांध जैसी बड़ी परियोजनाओं के कारण हज़ारों परिवारों को विस्थापित होना पड़ा. इसके अलावा आठ हजार हेक्टेयर से अधिक जंगल फारेस्ट लैंड डायवर्जन के कारण समाप्त हो चुके हैं. एक लाख हेक्टेयर कृषि भूमि विभिन्न बांधों से बने जलाशयों में समा चुकी है.

feedback@chauthiduniya.com

कुशीनगर के अंबेडकर गांवों में जितना विकास बीते चार वर्षों में नहीं हो सका, उतना एक पखवारे में हो गया. कूड़ेदान एवं शौचालय चमक उठे हैं.

अंबेडकर गांव

कहीं धूप कहीं छांव

सुरेंद्र अग्निहोत्री

बहुजन समाज पार्टी की मुखिया एवं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने 2012 का चुनावी रण जीतने के लिए एक बार फिर कांशीराम आवास योजना का तड़का लगाया है और वह अब तक 72 ज़िलों का दौरा कर चुकी हैं. अनुसूचित जाति और जनजाति बहुल गांवों के अंबेडकर ग्राम के रूप में समग्र विकास की परिकल्पना कितनी हक़ीक़त है, कितना फसाना, यह सामने आने लगा है.

चौथी दुनिया ने जब प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्यमंत्री रतन लाल अहिरवार के गृह जनपद झांसी के ब्लॉक मऊरानीपुर के ग्राम बम्हौरी से अपनी पड़ताल शुरू की तो पता चला कि यह गांव 1997-98 में भी अंबेडकर ग्राम रह चुका है, लेकिन 2010-11 में पुन: अंबेडकर ग्राम के रूप में चयनित होने के बावजूद इसकी हालत जस की तस है. गांव की सबसे समस्याग्रस्त गली पूछने पर जवाब मिला कि प्रधान जी के यहां चले जाओ. मुख्य मार्ग से ग्राम प्रधान के घर तक सीसी रोड में कोई नाली नहीं है. पूरी सड़क कीचड़ से भरी रहती है और पैदल चलना दुश्वार है. गांव के दयाराम बताते हैं, बिना नाली के सड़क निर्माण हुआ है. हैडपंपों के आसपास अक्सर कीचड़ रहता है. प्रधान ने बताया कि गांव में लगभग 70 शौचालय और लगभग 100 महामाया आवास स्वीकृत हैं. वहीं ग्रामवासी इसे फ़र्ज़ीवाड़ा बताते हैं. उन्होंने कहा कि आप ख़ुद शौचालय गिनकर देख लें. गांव की पेयजल व्यवस्था मुख्यत: हैंडपंपों पर निर्भर है. पेयजल टंकी एवं पाइप लाइन है, पर उचित देखभाल के अभाव में वर्षों से बंद हैं. ललितपुर जनपद के महरौनी विकास खंड अंतर्गत वर्ष 2010-11 में चयनित अंबेडकर ग्राम मिदरवाहा इसके पूर्व भी अंबेडकर ग्राम रह चुका है. यहां की कुल आबादी 2289 है. 402 परिवार अनुसूचित जाति के हैं. बीपीएल कार्डधारक 83 और अंत्योदय कार्डधारक 72 है. मिदरवाहा बढ़ई का कुआं, लक्ष्मणपुर एवं अजान यानी तीन मजरों से मिलकर बना है. यहां 5 सरकारी विद्यालय हैं, विद्युतीकरण है, लेकिन मात्र 44 कनेक्शन हैं.

यहां 52 इंदिरा, 33 महामाया सर्वजन और 32 महामाया आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है. स्वच्छ पेयजल हेतु कुछ वर्ष पूर्व एक पानी की टंकी बनाई गई थी, वर्तमान में वह सफ़ेद हाथी साबित हो रही है. प्रधान राम सेवक यादव का कहना है कि जबसे यह गांव अंबेडकर ग्राम के रूप में चयनित हुआ है, तबसे विकास हो रहा है. 2006 में यहां सीसी रोड बनी थी, जो उखड़ चुकी है, उसे फिर बनवाया जाएगा. ग्रामीण जगदीश ने कहा, मेरे पिता के नाम मात्र डेढ़ एकड़ ज़मीन है और हम चार भाई हैं. अभी तक बीपीएल कार्ड नहीं बना, इसलिए राशन नहीं मिलता. उसने बताया कि गांव में 20-25 लोग और हैं, जो पात्र होने के बाद भी बीपीएल श्रेणी में नहीं आ पा रहे हैं. वहीं अरविंद्र का कहना है कि उसके पास बीपीएल कार्ड तो है, लेकिन आज तक राशन नहीं मिला. समाजवादी चिंतक राजेंद्र रजक कहते हैं कि महरौनी तहसील में अंबेडकर ग्राम मज़ाक़ बनकर रह गए हैं.

नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र के अंबेडकर गांवों के दिन अच्छे चल रहे हैं. अफ़सरों को इन गांवों की सुधि आ गई है. चंदौली जनपद में मुख्यमंत्री के आगमन से यहां के उपेक्षित गांवों की क़िस्मत खुल गई है. प्रतिदिन किसी न किसी अंबेडकर गांव में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हो रहा है. इनायतपुर, नौरंगाबाद एवं हेतमपुर सहित दर्जनों गांवों के सफ़ाई कर्मियों की ड्यूटी इन दिनों अंबेडकर गांव दुबौलिया में लगा दी गई है. इसके चलते उक्त गांवों की नालियां बजबजा रही हैं, जगह-जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है. अंबेडकर नगर जनपद में अंबेडकर गांवों की दशा रामनगर एवं जहांगीर गंज विकास खंड में पहले से ही दयनीय है. दोनों विकास खंडों के गत वर्ष में चयनित अंबेडकर गांवों को सभी 11 प्रमुख बिंदुओं पर संतृप्त दिखा दिया गया है, लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त कुछ और है. ख़ास दर्जा पाने वाली ग्राम पंचायतों में भी पंचायत भवन, नाली, शौचालय, खड़ंजा, विद्युतीकरण, विकलांग-वृद्धावस्था-विधवा पेंशन, बीपीएल एवं अंत्योदय कार्ड बनने का काम पूरा नहीं हो पाया है. अन्नापुर, नेवारी दुराजपुर, चकभौरा, कसदहा, अमोला बुज़ुर्ग, संदहा एवं मजगवां आदि अंबेडकर गांवों को देखने से यही लगता है. रोशनपुर एवं घरवासपुर की भी यही स्थिति है. प्रधानों एवं ग्राम विकास अधिकारियों की साठगांठ के कारण आवंटित धनराशि का सदुपयोग नहीं हो पाया है.

कुशीनगर के अंबेडकर गांवों में जितना विकास बीते चार वर्षों में नहीं हो सका, उतना एक पखवारे में हो गया. कूड़ेदान एवं शौचालय चमक उठे हैं. घरों का पानी सड़कों पर नहीं, अब नालियों से होकर बह रहा है. घरों में बिजली जगमगा रही है. पडरौना ब्लॉक के अंबेडकर गांव बंधू छपरा, सेवक छपरा एवं चौरिया हों या रामकोला ब्लॉक का पपऊर, कमोबेश यह स्थिति वर्ष 2008-09 और 2009-10 में चिन्हित सभी अंबेडकर गांवों की है. सेवक छपरा में प्रवेश करते ही अंबेडकर गांव का बोर्ड लगा है और मुख्यमंत्री की तस्वीर वाली होर्डिंग भी. मुख्य सड़क आरसीसी से ढल चुकी है, जल निकासी के लिए 150 मीटर आउटफाल बनाया गया है, दो मीटर चौड़ाई वाली 60 मीटर आरसीसी सड़क भी बन गई है. इसके किनारे 60 मीटर केसी ड्रेन का निर्माण चल रहा है. ग्राम प्रधान मुनिया देवी ने कहा कि गांव में ऐसा एक भी आदमी नहीं है, जिसे उनसे कोई शिकायत हो. पिछले सत्र में रामनगर विकास खंड के आधा दर्जन गांव बतौर अंबेडकर गांव चयनित किए गए थे, जिनमें अन्नापुर, अमोला, कसदहां, नया गांव, मंसूर गंज, नेवारी, दुराजपुर एवं भौरा आदि शामिल थे. इनमें से ज़्यादातर गांवों में सिर्फ़ काग़ज़ी ख़ानापूर्ति करके धनराशि की बंदरबांट हो गई. पत्रकार अनिल त्रिपाठी कहते हैं कि अगर सीएम का उड़न खटोला अचानक किसी मजरे पर उतरे तो इन गांवों के स्याह सच से रूबरू हुआ जा सकता है. वैसे मुख्यमंत्री मायावती प्रदेश भर में दौरे करके अंबेडकर ग्रामों का सच जानने में लगी हैं. उन्होंने आगरा में एत्मादपुर तहसील के अंबेडकर ग्राम गढ़ी बच्ची में विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया. मथुरा भ्रमण के दौरान उन्होंने अंबेडकर ग्राम सेही बॉगर में किए गए विकास कार्य देखे. वह जनपद महामाया नगर के अंबेडकर ग्राम खोकिया भी गईं. अलीगढ़ की तहसील कोल के अंबेडकर ग्राम सलेमपुर माफ़ी में भी उन्होंने विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया. मुख्यमंत्री बुलंदशहर जनपद की तहसील शिकारपुर के अंबेडकर ग्राम बरखेड़ा हसनगढ़ी और जनपद बदायूं के विकास खंड म्याऊ के अंबेडकर ग्राम घड़ा कंचनपुर भी गईं.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व ग्राम्य विकास मंत्री विशंभर प्रसाद निषाद कहते हैं कि अंबेडकर ग्रामों के चयन में परिभाषा बदल दी गई है. पहले विधायक बताते थे, तब ग्रामों का चयन होता था, लेकिन चार बार चयनित हो चुके अंबेडकर ग्रामों का पांचवीं बार चयन आश्चर्यजनक है. प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री बिहारी लाल आर्य कहते हैं कि अंबेडकर ग्रामों के रूप में उन्हीं ग्रामों का पांचवीं बार चयन बताता है कि सब कुछ ठीकठाक नहीं है. यदि इन ग्रामों का पहली बार में ही विकास हो जाता तो उनका दूसरी बार चयन नहीं करना पड़ता.

feedback@chauthiduniya.com

नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र के अंबेडकर गांवों के दिन अच्छे चल रहे हैं. अफ़सरों को इन गांवों की सुधि आ गई है. चंदौली जनपद में मुख्यमंत्री के आगमन से यहां के उपेक्षित गांवों की क़िस्मत खुल गई है. प्रतिदिन किसी न किसी अंबेडकर गांव में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हो रहा है. इनायतपुर, नौरंगाबाद एवं हेतमपुर सहित दर्जनों गांवों के सफ़ाई कर्मियों की ड्यूटी इन दिनों अंबेडकर गांव दुबौलिया में लगा दी गई है. इसके चलते उक्त गांवों की नालियां बजबजा रही हैं, जगह-जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है.

चयन के मापदंड बदले

राज्य सरकार ने अंबेडकर गांवों के चयन के मापदंड बदल दिए हैं और 2001 की जनगणना के आधार पर नए गांवों का चयन करने का निर्णय लिया है. अभी तक अंबेडकर गांवों का चयन 1999 की जनगणना के आधार पर होता था. अब वर्ष 2011-12 के लिए 2501 अंबेडकर गांवों के चयन में उन गांवों को भी शामिल किया जा सकेगा, जिनमें 2001 की जनगणना के हिसाब से अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी पचास फ़ीसदी या इससे अधिक है. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बड़ी संख्या में ऐसे गांव हैं, जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी 50 फ़ीसदी का आंकड़ा पार कर चुकी है. वर्ष 2011-12 में अंबेडकर गांवों की संख्या में क़रीब 300 की बढ़ोतरी की गई है. प्रत्येक जनपद के कम से कम 15 गांवों को अनिवार्य रूप से अंबेडकर गांवों में शामिल किया जाएगा. बागपत को छोड़कर प्रदेश के सभी जनपदों में 15-15 गांव ऐसे हैं, जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी के आंकड़े को पूरा करते हैं. अंबेडकर गांवों के चयन के बारे में ज़िलाधिकारियों को भेजे गए दिशानिर्देश में कहा गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करते हुए अनुपातिक रूप से जनपदों को आवंटित किया जाए. चयनित अंबेडकर गांवों को विकास कार्यों के लिए 50-50 लाख रुपये की धनराशि मिलेगी.

गोधरा कांड के पीछे मुस्लिम आतंकी षड्यंत्र होने के आरोप का जमकर प्रचार किया गया और फिर उसका इस्तेमाल गुजरात में हुए मुसलमानों के क़त्लेआम को उचित ठहराने के लिए किया गया.

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह अपनी ज़िम्मेदारी क़ुबूल करते हैं. बहुतों ने चैन की सांस ली कि कम से कम इस मामले में उन्होंने बस नैतिक ज़िम्मेदारी का नाम नहीं लिया और न गठबंधन धर्म की दुहाई दी.

मेघनाद देसाई

महिलाएं दुर्व्यवहार सहती रही हैं

जिस दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के सौ साल पूरे हो रहे थे, उसी दिन दिल्ली में एक युवती की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई. कुछ समय पहले ख़बर आई कि जोधपुर के एक अस्पताल में सोलह महिलाओं की मौत हो गई. जहां तक मेरी जानकारी है, मैं कह सकता हूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उस अस्पताल का दौरा तक नहीं किया. इसमें कोई शक नहीं है कि इसके लिए उनके पास पर्याप्त बहाना भी था. बहाना इस बात का कि यह राज्य का मामला है और अशोक गहलोत को जाकर सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए.

अपने यहां एक अजीब पहेली इन दिनों देखी जा सकती है. भारतीय राजनीति में हर एक उच्च पद पर महिलाएं आसीन दिख रही हैं, चाहे वह राष्ट्रपति का पद हो या लोकसभा अध्यक्ष या कांग्रेस अध्यक्ष का पद. यहां तक कि लोकसभा में नेता विपक्ष, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और बहुत संभव है कि तमिलनाडु एवं बंगाल में भी संभावित मुख्यमंत्री महिला ही हो. दूसरी ओर महिलाओं की जनसंख्या दिन-प्रतिदिन घटती ही जा रही है. भ्रूण हत्या के रूप में महिलाओं को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जा रहा है. कम उम्र की युवतियों को ज़हर देकर या उनकी उपेक्षा (स्वास्थ्य संबंधी) करके भी उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है. नव विवाहिताओं को इसलिए पीटा जाता है कि वे अपने साथ दहेज में ख़ूब सारा सामान और पैसा क्यों नहीं लाईं. और तो और, खाप पंचायतों के तुग़लकी फ़रमान के बाद उन मासूम लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जो अपनी मर्ज़ी से अपना जीवनसाथी चुनना चाहती हैं. आख़िर हम इस विरोधाभास को कैसे देखें? एक ओर उच्च पदों पर आसीन महिलाएं और दूसरी ओर बाक़ी दुनिया की.

ज़ाहिर है, यह सब एक वर्ग और लिंग का मिश्रण है. उच्च वर्ग और उच्च जातियों की महिलाओं के पास इतने अवसर हैं कि वे आगे बढ़ सकें. साथ ही उन्हें अपने परिवार का समर्थन भी हासिल है. ऐसी महिलाएं जो राजनीति में हैं और अविवाहित हैं या जिन्हें अपने पति का पूरा समर्थन है (जैसे राष्ट्रपति पाटिल), उन्हें सहूलियत होती है. कई पति तो अपनी पत्नियों का करियर आगे बढ़ाने के लिए ख़ूब मेहनत भी करते हैं और समर्थन भी देते हैं. लालू यादव द्वारा राबड़ी देवी को आगे बढ़ाने का उदाहरण सामने है, लेकिन मेरी दृष्टि में महिलाओं की अवहेलना के मामले बढ़ते जा रहे हैं. ऐसा भारतीय संस्कृति में काफ़ी समय से चलता आ रहा है. अगर आप भगवद्गीता पढ़ें तो इसके 700 श्लोकों में महज़ दो जगह महिलाओं का ज़िक्र आता है. पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि यदि उसने अपने भाइयों को मारा तो इससे कुल का नाश हो जाएगा और कुल की महिलाएं पथभ्रष्ट हो जाएंगी. ऐसी स्थिति में वर्ण में मिलावट आ जाएगी. कृष्ण उसकी बातों का जवाब नहीं देते, बल्कि उसे आगे बढ़ने और हत्या करने के लिए कहते हैं.

बाद में कृष्ण यह कहते हुए सुनाई देते हैं कि जो लोग पापायोन्याह यानी नीच उत्पति (महिला, वैश्य और शूद्र) के होते हैं, वे भी भक्ति के रास्ते मेरे क़रीब आ सकते हैं. इन दो अवसरों (दोनों श्लोक महिलाओं के प्रति नकारात्मक) को छोड़कर शेष गीता में सारी बातें पुरुषों से ही संबंधित हैं. एक आम धारणा यह हो सकती है कि संपूर्ण गीता पुरुष-पुरुष संवाद पर आधारित है या मनुष्य-भगवान संवाद है या कर्म योग या ज्ञान योग की बातें हैं, जिनमें महिलाओं के लिए कुछ न होना सामान्य बात है (यहां तक कि वैश्य और शूद्रों के लिए भी). बहुत से पुरुषों ने गीता पर टीकाएं लिखी हैं, लेकिन कितनी महिलाओं ने ऐसी टीका लिखी है? जहां तक मुझे याद है, एनी बेसेंट एक ऐसी अकेली महिला हैं, जिन्होंने गीता पर टीका लिखी. हो सकता है कि कुछ और महिलाओं ने भी लिखा हो, लेकिन कुल मिलाकर गीता अभी भी पुरुषों के ही क़ब्ज़े में है. यह कोई दुर्घटना नहीं है. महिलाओं के लिए गीता एक प्रतिकूल दस्तावेज़ है.

महिलाएं हमेशा से दुर्व्यवहार सहती रही हैं. द्रौपदी को भरी सभा में नंगा किया गया, जहां उसके सारे संबंधी मौजूद थे. सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए ख़ुद की अग्नि परीक्षा देनी पड़ी. अहिल्या को पत्थर बनना पड़ा. लेकिन भारत तभी एक महाशक्ति बन पाएगा, जब यहां की महिलाओं को उनके अंतिम पड़ाव तक एक शालीन जीवनशैली मिले.

feedback@chauthiduniya.com

राम पुनियानी

गोधरा फ़ैसला: छलनी से ज़्यादा छेद

बीती 22 फ़रवरी को सत्र न्यायालय ने गोधरा रेल आगज़नी मामले में अपना फ़ैसला सुनाया. अदालत ने गुजरात सरकार के इस आरोप को सही ठहराया कि स्थानीय मुसलमानों ने साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगाने का षड्यंत्र रचा था. जिन 94 आरोपियों पर मुक़दमा चल रहा था, उनमें से 63 को बरी कर दिया गया और 31 को साज़िश के तहत कारसेवकों को ज़िंदा जलाने का दोषी ठहराया गया. गोधरा कांड को साज़िश बताने वाले पहले व्यक्ति थे गुजरात के तत्कालीन एवं वर्तमान मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी. वह घटना के आधे घंटे के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे. उन्होंने कहा था कि गोधरा कांड के पीछे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन थे, जिन्होंने स्थानीय मुसलमानों की मिलीभगत से इसे अंजाम दिया था. इन मुसलमानों को पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई का सहयोग भी हासिल था. गोधरा की तत्कालीन कलेक्टर जयंती रवि ने घटना के पीछे कोई साज़िश होने की आशंका से इंकार किया था. गोधरा जैसी बड़ी रेल दुर्घटनाओं की रेलवे आवश्यक रूप से आंतरिक जांच कराता है, परंतु तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना की जांच किए जाने के आदेश नहीं दिए. वह उन दिनों भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन सरकार में शामिल थे.

गोधरा कांड के पीछे मुस्लिम आतंकी षड्यंत्र होने के आरोप का जमकर प्रचार किया गया और फिर उसका इस्तेमाल गुजरात में हुए मुसलमानों के क़त्लेआम को उचित ठहराने के लिए किया गया. तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि गुजरात इसलिए हुआ, क्योंकि गोधरा हुआ था. उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने गुजरात में मोदी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया. वह उन दिनों भाजपा के ख़ेमे में थीं. गुजरात क़त्लेआम के बारे में मायावती ने तब कहा, गोधरा भी तो हुआ था! बाद में केंद्र में यूपीए की सरकार बनी और रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव ने गोधरा कांड की जांच के आदेश दिए. रेलवे के लिए यह क़ानूनन ज़रूरी है कि वह हर बड़ी दुर्घटना की जांच कराए. गोधरा के मामले में यह ज़िम्मेदारी वर्षों बाद पूरी की गई. जांच के लिए बनर्जी आयोग बना, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि गोधरा कांड किसी षड्यंत्र का नतीजा नहीं था.

गोधरा कांड को षड्यंत्र साबित करने के लिए गुजरात पुलिस ने कई गवाह ढूंढ निकाले. उन्हें यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया कि उन्होंने 140 लीटर पेट्रोल ख़रीदा, पेट्रोल रेलवे लाइन तक पहुंचाया, एस-6 एवं एस-7 के बीच के वेस्टीब्यूल को काटा, एस-6 में पेट्रोल फैलाया और फिर बाहर से आग के जलते हुए गोले फेंक कर कोच में आग लगा दी. हालिया निर्णय में यह तो स्वीकार किया गया है कि गोधरा के पीछे षड्यंत्र था, परंतु गुजरात सरकार द्वारा मुख्य षड्यंत्रकारी घोषित किए गए हाजी उमर जी को बेक़सूर बताया गया है. अन्य प्रमुख आरोपियों के ख़िलाफ़ भी कोई सुबूत नहीं पाए गए. केवल ये तथ्य ही निर्णय का खोखलापन सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं. गोधरा को षड्यंत्र बताने का मुख्य आधार यह है कि पेट्रोल बेचा-ख़रीदा गया और एस-6 में आग के गोले फेंके गए. इन दोनों घटनाओं का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है. जिन लोगों ने पहले स्वीकार किया कि उन्होंने पेट्रोल बेचा, वे भी अदालत में अपने बयान से मुकर गए और एक ने तो यह कहा कि गवाही के लिए उसे 50 हज़ार रुपये दिए गए थे, उसे यह राशि गुजरात पुलिस के मुख्य जांचकर्ता परमार ने दी थी. ज़ाहिर है, षड्यंत्र की कहानी में छलनी से भी ज़्यादा छेद हैं.

यह आरोप कि मुसलमानों ने बाबरी कांड का बदला लेने के लिए कारसेवकों को ज़िंदा जलाया, कई कारणों से तार्किक नहीं लगता. पहली बात तो यह है कि मुसलमानों को ही नहीं, बल्कि शासन तंत्र को भी पता नहीं था कि साबरमती एक्सप्रेस में कारसेवक यात्रा कर रहे थे. केवल विहिप के नेताओं को जानकारी थी. दूसरे, उस दिन साबरमती एक्सप्रेस पांच घंटे से अधिक देरी से चल रही थी. ट्रेन का गोधरा पहुंचने का सही समय आधी रात के आसपास है. किसी भी षड्यंत्रकारी के लिए अचानक सामने आई ऐसी परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाना कठिन होता है. तीसरे, जिस समय वेस्टीब्यूल काटा जा रहा था, उस समय आरपीएफ और जीआरपी के जवान क्या कर रहे थे? वेस्टीब्यूल को काटना और फिर उसमें घुसना कोई आसान काम नहीं होता. चौथे, ठंड के मौसम में (घटना फरवरी 2002 की है) पौ फटने के पहले कोच के खिड़की-दरवाज़े बंद रहे होंगे. ऐसे में बाहर से आग के गोले अंदर कैसे फेंके गए? पहले प्रचार किया गया था कि ट्रेन मुसलमानों ने रोकी थी. बाद में हुई जांचों में यह सामने आया कि ट्रेन दो बार रुकी, पहली बार कारसेवकों द्वारा चेन खींचे जाने से और दूसरी बार किसी तकनीकी ख़राबी से. यह भी कहा गया कि कारसेवक भाग न सकें, इसलिए कोच के दरवाज़े बाहर से लॉक कर दिए गए थे. यह दावा करने वाले शायद भूल गए कि रेलों के यात्री डिब्बों में बाहर से दरवाजे लॉक करने की कोई व्यवस्था ही नहीं होती.

इस आरोप पर संदेह करने के पर्याप्त आधार हैं कि गोधरा कांड के पीछे मुसलमानों का षड्यंत्र था. गोधरा प्लेटफार्म पर खानपान सामग्री बेचने वाले हिंदू वेंडर अजय बारिया को भी षड्यंत्र में शामिल कर लिया गया. जज पटेल ने अजय के बयान को बहुत महत्व दिया. सवाल यह है कि मुस्लिम षड्यंत्रकारी अंतिम समय में किसी हिंदू को षड्यंत्र में शामिल क्यों करेंगे? वे पेट्रोल ढोने और कोच जलाने में उसकी मदद क्यों लेंगे? अजय की मां ने बताया कि पुलिस ने ज़बरदस्ती उसे गवाह बनने पर मजबूर किया था और पुलिस उस पर लगातार नज़र रखती है. एक पेट्रोल पंप के कर्मचारियों रंजीत सिंह एवं प्रताप सिंह पटेल ने दावा किया था कि 26 फ़रवरी को उन्होंने कुछ मुसलमानों को 140 लीटर पेट्रोल बेचा था. इन दोनों ने पहले पुलिस को यह बताया था कि उन्होंने उस रात किसी को पेट्रोल नहीं बेचा. छह महीने बाद वे अपनी बात से पलट गए. प्रताप ने कहा कि पुलिस अधिकारी परमार ने उन दोनों को बयान बदलने के लिए 50 हज़ार रुपये दिए थे. परमार ने उन्हें यह भी बताया था कि अदालत में उन्हें किन मुसलमानों को पेट्रोल के ख़रीददार के तौर पर पहचानना है.

जबीर बहेरा नामक एक अपराधी ने पहले कहा कि मौलवी उमर जी ने ही एस-6 को निशाना बनाने का निर्णय लिया था, परंतु बाद में वह अपने दावे से पीछे हट गया. एक अन्य मामूली अपराधी सिकंदर सिद्दीक़ी ने कहा कि मौलवी पंजाबी ने भीड़ को उकसाया था, परंतु पंजाबी उस दिन देश में ही नहीं थे.

(लेखक आईआईटी मुंबई के पूर्व प्राध्यापक हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

कांग्रेस और रामदेव

रामदेव द्वारा काले धन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते ही सभी उनके पीछे पड़ गए. अपराधी राजनीति करें तो ठीक, लेकिन एक संत राजनीति को साफ़ करना चाहे तो ग़लत! रामदेव की व्यक्तिगत ज़िंदगी में बाद में झांको, पहले यह देखो कि वह जो कर रहे हैं, वह यहां के ग़रीबों के हित की बात है या नहीं? अगर रामदेव झूठ बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से इस देश में कोई ग़रीब नहीं है. विश्वबंधु गुप्ता अगर झूठ बोल रहे हैं तो उन पर मुक़दमा करो. है हिम्मत? देश तो अब भी लूटा जा रहा है, सिर्फ़ मुखौटे बदले हैं. कोई उन मुखौटों को उतारना चाहता है तो तकलीफ़ हो रही है, क्यों? अरे, आप ख़ुद आगे आओ रामदेव की जगह!

एक भारतीय नागरिक, ई-मेल से

अभी नहीं तो कभी नहीं

दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार एवं काले धन के ख़िलाफ़ हुई रैली और राम जेठमलानी के ख़ुलासे ने पूरे देश को सच्चाई से अवगत करा दिया कि कौन चोर है और कौन गुमराह करके, ग़रीब जनता की गाढ़ी कमाई पर ऐश करके देश को खोखला कर रहा है. वहीं हम चोरों-लुटेरों का गुणगान करके उन्हें सत्ता में बैठाए हुए हैं. यह महापाप है. इसलिए अब रामदेव का साथ देकर चोरों, लुटेरों एवं भ्रष्टाचारियों को समाप्त करना है. अगर यह अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा.

रवींद्र कुमार, ई-मेल से

सर्वश्रेष्ठ पत्र

बजट का सच

आलेख-इसमें ग़रीबों के लिए कुछ नहीं है (14-20 मार्च) एक आईने के समान है, जो इस सच्चाई को बताता है कि देश का बजट आज की तारीख़ में आख़िर है क्या बला? वास्तव में केंद्र और राज्यों में बनने वाले सालाना बजट में ज़रूरतमंदों, ग़रीबों, उपेक्षितों, बच्चों, मज़दूरों और महिलाओं के लिए कोई भी जगह नहीं होती. आंकड़ों की बाज़ीगरी दिखाकर वित्तमंत्री हर साल आंख में धूल झोंक देते हैं और जनता यह समझ बैठती है कि सरकार को उसका बहुत ध्यान है, जबकि सरकार को जनता की ज़रा भी चिंता नहीं है. वह तो केवल इस बात से चिंतित रहती है कि उससे जुड़े कारोबारी, बड़े घराने और सत्ता के इर्द-गिर्द एकत्र लोगों की ख़ुशहाली किसी भी तरह बरक़रार रहे, चाहे इसके लिए बाक़ी जनता को भाड़ में क्यों न झोंकना पड़े!

शैलेंद्र शर्मा, *श्याम नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश*

जनता को क्या मिला

भारत को स्वतंत्र हुए 63 वर्ष हो गए. इस दौरान वर्षों तक केवल कांग्रेस ने शासन किया और क्या मिला जनता को? अरबों-खरबों रुपये काले धन के रूप में विदेशी खातों में जमा हो गए, वहीं दूसरी ओर करोड़ों लोग दो वक़्त की रोटी भी ठीक से नहीं कमा पाते. विश्व के सबसे ज़्यादा टीबी और एड्स के मरीज़ हमारे यहां, करोड़ों बच्चे कुपोषण के शिकार. कहां गया ग़रीबी हटाओ का नारा? कहां है कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ?

अभिषेक वैष्णव, ई-मेल से

देश के अंदर का काला धन

हम भारतीय वही देखते हैं, जो दिखाया जाता है. बाबा रामदेव जैसे लोग हमारी भावनाओं के दम पर अपना खेल खेल जाते हैं और हम ठगे से रह जाते हैं. रही बात काले धन की, तो भारत में ही लोगों ने जो काला धन छुपाकर रखा है, पहले तो उसे ही निकाला जाना चाहिए.

अब्दुल राशिद, ई-मेल से

किसके विरुद्ध लड़ाई

पैसा और प्रसिद्धि पचा पाना आसान नहीं होता. लगता है, रामदेव भी इसी के शिकार हो रहे हैं. पहले यह तय हो कि वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं या कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध. यदि वह कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं तो उन्हें प्रतिकूल टिप्पणियां झेलनी ही पड़ेंगी, क्योंकि तब वह एक पक्ष बन रहे हैं. यदि वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं तो सारा देश उनके पीछे हो जाएगा. वह यदि सचमुच भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव सुधारों पर अपना अभियान केंद्रित करना चाहिए.

विष्णु बैरागी, ई-मेल से

सूचना

राजकमल प्रकाशन
नयी दिल्ली पटना इलाहाबाद

अब चौथी दुनिया में सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की तरफ़ से 700 रुपये की किताबें पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी. पाठक पत्र में अपना पूरा नाम, पता एवं फ़ोन नंबर अवश्य लिखें.

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इस पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

बाबा रामदेव जी, पहले इस देश को तो समझिए

हमने बाबा रामदेव से कई सवाल किए. हमें बाबा रामदेव से कोई शिकायत नहीं है. शिकायत इसलिए नहीं है कि देश में कोई भी आदमी कुछ भी व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वह व्यापार कारों का हो, चाहे वह व्यापार मिठाई बनाने का हो, चाहे वह व्यापार योग सिखाने का हो या चाहे वह व्यापार दवाइयां बनाने का हो. बहुत सारे लोग व्यापार कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने दायरे को छोड़कर बाहर निकलते हैं और मुल्क के दायरे में आते हैं तो फिर आपको उन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिन सवालों का रिश्ता देश के भविष्य से है. यह देश वैसे ही बहुत सारे नेताओं के भ्रामक भाषणों, भ्रामक सपनों और भ्रामक वायदों की वजह से परेशानी में है. यह देश एक तरीक़े से समस्याओं के ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है. ज्वालामुखी फटने के लिए तैयार है, क्योंकि इस देश में न तो किसान सुखी हैं और न नौजवान सुखी हैं, न दलित सुखी हैं, न अल्पसंख्यक सुखी हैं, न उच्च मध्यम वर्ग के लोग ख़ुश हैं और न मध्यम वर्ग के लोग ख़ुश हैं.

अगर अमीर ख़ुश होते, तब भी माना जाता, लेकिन दुर्भाग्य तो यही है कि इस देश में अमीर भी सुखी नहीं हैं, क्योंकि अमीरों के बीच में जिस तरह की बाज़ार की प्रतियोगिता इस सरकार ने शुरू कर दी है, वह कुछ अमीरों को छोड़कर बाक़ी सबके ख़िलाफ़ है. समान अवसर वहां भी नहीं हैं. इसलिए अब जब कोई भी ऐसा आदमी आता है, जो कहता है कि हम देश के बारे में बात करते हैं, हम देश का स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं, देश को समस्याओं के जाल से निकालना चाहते हैं तो वह सवालों का अधिकारी हो जाता है. उसे यह नहीं मानना चाहिए कि कोई भी उससे सवाल नहीं पूछ सकता है. आप ख़रीद सकते हैं लोगों को, चाहे वे टेलीविज़न के लोग हों या प्रिंट के, जो आपसे सवाल नहीं पूछेंगे. आप ऐसे चैनलों के संपादकों को ख़रीद सकते हैं, जो वही सवाल पूछें, जो सवाल आप पुछवाना चाहते हैं. वे वैसे सवाल पूछ सकते हैं आपसे, जिनसे आपकी पर्सनैलिटी बड़ी हो. लेकिन जो देश से ज़रा भी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ऐसे लोग आपसे सवाल करेंगे और ये लोग उनको रिप्रजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इस देश में सरकार बनाते हैं. इसलिए बाबा रामदेव से हमने सवाल किए और उन सवालों का जवाब अभी तक बाबा रामदेव से नहीं आया है.

हम एक बात और साफ़ करें. जब देश की बात कोई करता है तो उसे सबसे पहले इस देश को समझना होगा. देश को समझने का मतलब, देश की समस्याओं को समझना होगा और समस्याओं को समझने का मतलब है कि आज जो भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, चाहे वह आतंकवाद हो, चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे शिक्षा का ध्वस्त हुआ ताना-बाना हो, चाहे बर्बाद हुआ स्वास्थ्य का नेटवर्क हो, इन सबके कारणों को समझने वाला आदमी ही इस देश के बारे में बात करने का अधिकारी है. इन सवालों को समझने वाला आदमी अगर ये सवाल ही न समझ पाए तो वह इनका हल क्या निकालेगा. इसलिए सबसे पहला सवाल उस व्यक्ति से होता है, जो देश के बारे में बात करता है कि क्या आप इन सवालों को समझते हैं. क्या आप समाज के विकास और समाज के अंतर्विरोध को समझते हैं. क्या आप समाज के विभिन्न वर्गों में पैदा हुए तनावों को समझते हैं. अगर समझते हैं तो इनका हल क्या है. क्योंकि यह मुल्क समस्याओं के ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है. अब कोई भी बेवकूफी इस मुल्क को तबाही और टूटने की तरफ़ ले जाएगी, क्योंकि हम सेचुरेशन प्वाइंट पर पहुंच गए हैं. इसलिए बाबा रामदेव जब सारे देश में घूमकर कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हैं, हम इस देश में जो सरकारें चल रही हैं उनके ख़िलाफ़ हैं और हम देश का स्वास्थ्य ठीक करेंगे तो बाबा से सवाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. हम अख़बार हैं, हम कोई भी स्टोरी या रिपोर्ट लिखने से पहले जब आपसे संपर्क करते हैं और आपके यहां से जवाब ऐसा आता है और आपके लोग जानते हैं कि उन्होंने क्यों ऐसा जवाब दिया है और यह जवाब किसी और को नहीं दिया है, हमें दिया है, चौथी दुनिया को दिया है. उन्होंने सवालों को अनदेखा किया है. उन्होंने कहा कि आप कर क्या लेंगे. आप नक्कारखाने में तूती हैं. सारे अख़बार वालों को हमने ख़रीद रखा है, सारे टेलीविज़न चैनलों को हमने ख़रीद रखा है. उन पर हम कूदते-फांदते हैं, पेट फुलाते हैं, उसका पैसा देते हैं. कौन हमारे ख़िलाफ़ स्टोरी करेगा. नहीं, लोग हैं, जो आपसे इसलिए सवाल करेंगे, क्योंकि वे इस देश से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इस देश को और बर्बाद होते नहीं देखना चाहते. इसलिए बाबा रामदेव का यह फ़र्ज़ है कि देश से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं, वह उनका जवाब दें.

बाबा रामदेव का एक महत्व है, एक स्थान है. उन्होंने इस देश में बड़ा काम किया. उन्होंने योग के प्रति लोगों की आस्था जाग्रत की. ऐसी आस्था जाग्रत की कि जितने भी बीमार क़िस्म के लोग थे, वे सभी बाबा रामदेव के भक्त हो गए, क्योंकि बाबा रामदेव ने उन्हें मोटिवेट किया कि वे टहलें और थोड़ी एक्सरसाइज़ करें. कुछ दवाइयां भी उनकी काम में आईं. हालांकि वृंदा करात ने उनके ऊपर आरोप लगाए, कई और लोग भी आरोप लगा रहे हैं, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता. मेरा कहना है कि वह काम ठीक है. आपने भरोसा अर्जित किया योग सिखा करके सारी दुनिया में, आपने उस योग को सिखाने की भी एक मार्केटिंग की है और सफल मार्केटिंग की, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केटिंग अब तक दुनिया में जितने भी योग सिखाने वाले हिंदुस्तान के लोग गए, उन्होंने नहीं की. उन्होंने दुनिया में तो लोगों को योग सिखा करके पैसा कमाया, पर आपने दुनिया के साथ-साथ पूरे हिंदुस्तान में भी इसकी चेतना जाग्रत करके 60 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का साम्राज्य खड़ा कर लिया. कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यह आपके योग के प्रति लोगों के पागलपन और आकर्षण का प्रमाण है. जो लोग आपके साथ शामिल हुए शायद 60 हज़ार करोड़ की संपत्ति इकट्ठा करने में, जिन लोगों ने भी अपना हाथ बढ़ाया हाथ मिलाया बाबा रामदेव के साथ, वे सारे लोग इस देश के किसान नहीं हैं, इस देश के मज़दूर नहीं हैं, इस देश के बेरोज़गार नहीं हैं, इस देश के दलित नहीं हैं, इस देश के अल्पसंख्यक नहीं हैं. वे लोग उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं. रामलीला मैदान में जितने लोग आए थे बाबा रामदेव की रैली में, वे सारे लोग भविष्य के सांसद थे. वह संख्या अस्सी हज़ार या एक लाख थी या पांच लाख, मैं इस बहस में नहीं जाता, लेकिन जितने भी लोग थे, भविष्य के प्रधानमंत्री को छोड़ करके क्योंकि उसके लिए बाबा रामदेव का नाम लिखा हुआ है, बाकी सारे पद इन्हीं लोगों के बीच में थे. ये सब वे हैं, जिनके ऊपर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स लागू होता है. इनका पैसा विदेश में भले ही न हो, लेकिन जिनका विदेश में पैसा है, उनके साथ इनमें से अधिकांश का रिश्ता है.

बाबा रामदेव कहते हैं कि वह बर्मा से लेकर अफ़ग़ानिस्तान तक एक हिंदुस्तान बनाएंगे. यह सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी यही कहता है और बाबा रामदेव भी यही कहते हैं. लेकिन क्या बर्मा से लेकर अफ़ग़ानिस्तान तक एक हिंदुस्तान बन सकता है? ये ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब चाहिए. आप अगर देश की बात नहीं करते, हम फिर दोहराते हैं, हम कोई सवाल आपसे नहीं पूछते. लेकिन चूंकि आप देश की बात करते हैं, इसलिए सवालों का जवाब देना आपका कर्तव्य है.

मैं सिर्फ़ बाबा रामदेव से यह पूछना चाहता हूं कि बाबा रामदेव, आप अगर कोई आर्थिक नीति बनाते हैं तो जो लोग आपके साथ हैं, इनको ले करके आप उनका पालन कैसे कर पाएंगे. यह इमोशनल इश्यू है विदेश से काला धन वापस लाने का. लेकिन उस काले धन से सौ गुना धन तो यहां पर है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में उसका चलन है. वह पैसा तो वहां दबा हुआ है, जिसको ला करके यहां का काम होगा, लेकिन जिस पैसे का यहां चलन है और जिसको चलाने वाले आपके दाएं-बाएं-आसपास देखे जा रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ क्यों नहीं कहते. यह सवाल हम सिर्फ़ इसलिए पूछ रहे हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद की ओर देख रहे हैं. आप कहेंगे कि आप प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते तो जो कोई भी होशियार आदमी होगा, यही कहेगा. आपके लोग तो कह रहे हैं कि बाबा प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं. और सवाल प्रधानमंत्री पद का भी नहीं है, सवाल है इस देश में उन नीतियों के लागू होने का, जिनका सीधा फ़ायदा देश के 80 प्रतिशत लोगों को हो.

बाबा रामदेव कहते हैं कि वह बर्मा से लेकर अफ़ग़ानिस्तान तक एक हिंदुस्तान बनाएंगे. यह सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी यही कहता है और बाबा रामदेव भी यही कहते हैं. लेकिन क्या बर्मा से लेकर अफ़ग़ानिस्तान तक एक हिंदुस्तान बन सकता है? ये ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब चाहिए. आप अगर देश की बात नहीं करते, हम फिर दोहराते हैं, हम कोई सवाल आपसे नहीं पूछते. लेकिन चूंकि आप देश की बात करते हैं, इसलिए सवालों का जवाब देना आपका कर्तव्य है. आप जवाब न दें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन हम सवाल आपसे पूछते रहेंगे. एक बात आख़िर में बता दें कि जो जिस चीज़ को जानता है, उसे वही काम करना चाहिए. उदाहरण के लिए, अगर हम घोषणा कर दें कि दारा सिंह कथक नृत्य करेंगे. बड़ी भीड़ होगी, लोग ताली बजाएंगे, दारा सिंह भी लटकते-मटकते थोड़ा कुछ शरीर को हिलाएंगे-डुलाएंगे और होगा कि ओह यह कथक नृत्य है, इस तरह का कथक नृत्य है, लेकिन वह कथक नृत्य नहीं होगा. उसी तरीक़े से अगर हम बिरजू महाराज को कहें कि आप दारा सिंह से कुश्ती लड़िए तो लोग बहुत आएंगे देखने के लिए, लेकिन वह कुश्ती कुश्ती होगी क्या? दारा सिंह डांस नहीं कर सकते और बिरजू महाराज कुश्ती नहीं लड़ सकते. बाबा रामदेव क्या कर सकते हैं, वह बाबा जी तय करें. लेकिन कहावतें हज़ारों साल के अनुभव से बनती हैं. ऐसी ही एक कहावत है, बिच्छू का मंत्र न जाने, सांप के बिल में हाथ डाले.

सांप के बिल में हाथ ज़रूर डालिए, लेकिन सांप का मंत्र जान लीजिए. इस मुल्क को बनाने में आप अगर कोई रोल प्ले करना चाहते हैं तो पहले इस मुल्क को एक बार समझ लीजिए. यह हमारी हर उस आदमी से विनम्र अपील है, जो इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहता है. 60 साल से ज़्यादा आज़ादी को आए हो चुका है. 60 साल की उम्र छोटी उम्र नहीं होती. अब लोग बहुत कुछ समझने लगे हैं. इसलिए किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए और जो भ्रम में रहता है, उसका हश्र बहुत बुरा होता है. हम हर उस आदमी से, बाबा रामदेव से भी अनुरोध करेंगे कि सवालों का जवाब दें और सवालों का जवाब देने के साथ-साथ इस देश को समझने का (समझाने का नहीं), यहां की समस्याओं की जड़ जानने का प्रयास अवश्य करें.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

एस पी शुक्ला

नैतिक, रचनात्मक और राजनीतिक ज़िम्मेदारी

प्रजातंत्र में कोई भी सरकार तब तक प्रजातांत्रिक नहीं मानी जा सकती, जब तक वह अपने देश के नागरिकों के प्रति उत्तरदायी न हो, क्योंकि वह उन्हीं के लिए और उन्हीं के नाम पर राज्य करती है. एक संसदीय व्यवस्था में वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है. चलिए, बात शुरू से करते हैं. जब 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले की बात चल रही थी तो बहुत ही दोमुंही बातें सुनने को मिलीं. पहली यह कि प्रधानमंत्री को इस बात की हवा तक नहीं थी कि आख़िर दूरसंचार मंत्रालय में चल क्या रहा था. इस बात पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ. तब बात आई कि प्रधानमंत्री ने तो अपने मंत्री को अपने विचार बता दिए थे कि वह उनसे सहमत नहीं थे, लेकिन मंत्री ने उनकी बात की अनदेखी कर दी और अपने मन से सारा काम किया.

ख़ानापूर्ति तब चालू हुई, जब देश के सर्वोच्च लेखा अधिकारी की रिपोर्ट जनता के सामने आ गई. इस ख़ानापूर्ति के दो पहलू थे. पहला तो यह कि दूरसंचार नीति में कोई ख़राबी नहीं है, बस इस नीति के क्रियान्वयन में ही सारी हेराफेरी की गई थी. दूसरी यानी राजनीतिक पटल पर यह कहा गया कि प्रधानमंत्री इस घोटाले की नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हैं, लेकिन इस ज़िम्मेदारी में से सारे ज़िम्मेदाराना पहलू कमज़ोर कर दिए गए. प्रधानमंत्री ने अपनी कमज़ोरी गठबंधन धर्म के नाम पर जनता के सामने पेश कर दी, लेकिन यह सारी बातें उस समय धरी की धरी रह गईं, जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच में कई गड़े मुर्दे उठ खड़े हुए. इसके बाद बारी आई अंतरिक्ष विभाग की और धांधली के रुपहले परदे पर आई एंट्रिक्स-देवास डील. शुरू से ही किसी और मंत्रालय पर इसका दारोमदार डालने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी, इसलिए उत्तरदायित्व और ज़िम्मेदारी के प्रश्न को ही ख़त्म करते हुए इस डील को रद्द कर दिया गया. इसे रद्द करने से उठने वाले न्यायिक बवंडर को सत्ता के हथियार से दबा दिया गया, लेकिन अब भी सब ख़त्म नहीं हुआ है. असली ड्रामा तो तब शुरू होगा, जब दूसरा पक्ष भारत सरकार को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जाएगा. मंत्रालय के स्तर पर तो ज़िम्मेदारी का प्रश्न दबा दिया गया, लेकिन वहां पर देश की ज़िम्मेदारी को दरकिनार करना मुश्किल होगा.

अब बात करते हैं इन सबसे ज़्यादा पेचीदे सवाल की. यह सवाल है चीफ विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति का. यह एक ऐसा निर्णय था, जिसे स्वयं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उस कमेटी ने लिया था, जिसमें उनके गृहमंत्री भी थे और देश के विपक्ष की नेता भी. एक ऐसे भूतपूर्व दूरसंचार सचिव की नियुक्ति की गई, जिसके नाम पर विपक्ष की नेता ने उंगली उठाई थी. यह नियुक्ति तब की गई थी, जब 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला भले ही जनता के सामने नहीं आया था, लेकिन इसके बारे में सुगबुगाहट तेज़ थी. इस मामले में प्रधानमंत्री न तो अपने किसी मंत्री पर दायित्व टाल सकते हैं और न सिर्फ़ नैतिक ज़िम्मेदारी लेकर भाग सकते हैं. यह भी नहीं कहा जा सकता है कि इस बात से देश को कोई हानि नहीं पहुंची, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने साफ़ कह दिया है कि यह नियुक्ति और इसके पीछे का निर्णय ग़ैर क़ानूनी है. इसकी वजह से जनता की नज़रों में सीवीसी जैसे उच्च संवैधानिक पद की गरिमा का हनन हुआ.

ख़ानापूर्ति तब चालू हुई, जब देश के सर्वोच्च लेखा अधिकारी की रिपोर्ट जनता के सामने आ गई. इस ख़ानापूर्ति के दो पहलू थे. पहला तो यह कि दूरसंचार नीति में कोई ख़राबी नहीं है, बस इस नीति के क्रियान्वयन में ही सारी हेराफेरी की गई थी. दूसरी यानी राजनीतिक पटल पर यह कहा गया कि प्रधानमंत्री इस घोटाले की नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हैं, लेकिन इस ज़िम्मेदारी में से सारे ज़िम्मेदाराना पहलू कमज़ोर कर दिए गए.

इस बात पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह अपनी ज़िम्मेदारी क़ुबूल करते हैं. बहुतों ने चैन की सांस ली कि कम से कम इस मामले में उन्होंने बस नैतिक ज़िम्मेदारी का नाम नहीं लिया और न गठबंधन धर्म की दुहाई दी. इसलिए यह बात तो साफ़ है कि सीवीसी की नियुक्ति में हुए घोटाले की ज़िम्मेदारी प्रधानमंत्री के सिर पर है. जो गड़बड़ हुई और उसकी वजह से जो नुक़सान हुआ, वह सब सभी के सामने है. अब ऐसा है तो प्रधानमंत्री की नीयत पर साफ़-साफ़ शक होता है. भारत का गौरवशाली इतिहास इस बात का गवाह है कि एक रेल मंत्री ने एक रेल चालक की लापरवाही से हुई दुर्घटना की नैतिक ज़िम्मेदारी ली थी. उन्होंने बिना कोई सफ़ाई दिए तुरंत पद छोड़ दिया था. दशकों बाद आज यह स्थिति है कि सत्ताधारियों और शासन द्वारा लिए गए निर्णय पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप बनकर रह गए हैं, जिनमें पब्लिक बहुत कम है और प्राइवेट बहुत अधिक. आज हम व्यक्तिगत गोपनीयता के नाम पर घोटाले होते देख रहे हैं.

समय वास्तव में बदल गया है, लेकिन आज भी संसदीय प्रजातंत्र चल रहा है और इस नाते यह बिल्कुल नाक़ाबिले बर्दाश्त है कि किसी बहुत बड़ी राजनीतिक ग़लती पर सिर्फ़ एक ज़िम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति अपनी ग़लती स्वीकार कर ले. असल में अगला सही क़दम होना चाहिए उस ज़िम्मेदार व्यक्ति का इस्तीफ़ा. आज अगर विपक्ष प्रधानमंत्री से इस्तीफ़ा लेने में नाकामयाब रहा तो उसके सिर पर भी देश के प्रजातंत्र की हत्या का इल्ज़ाम रहेगा. यह मुद्दा सिर्फ़ विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी के बीच का मामला नहीं है, यह संसद में मीठे शब्दों के आदान-प्रदान से आपसी भाईचारे को बनाए रखने का मामला नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि विपक्ष द्वारा इस्तीफ़ा मांगने पर कांग्रेस के भीतर प्रधानमंत्री के विरोध को भुलाकर पार्टी उनके साथ खड़ी नज़र आएगी. पार्टियां तो अपना काम वैसे ही करती रहेंगी, जैसे आज तक करती आई हैं, लेकिन मुद्दा है विपक्ष के इम्तिहान का. अगर विरोधी पक्ष भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा से अलग अन्य कारणों पर ध्यान देगा तो यह तय है कि विपक्ष भी सत्ता पक्ष की तरह दोमुंहा दिखाई पड़ेगा.

(लेखक भारत के वाणिज्य एवं वित्त सचिव रह चुके हैं)

feedback@chauthiduniya.com

ब्रिटेन स्थित कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की डॉक्टर जोआना ओवेंस कहती हैं कि ऐसा कोई सीधा सबूत नहीं मिला है, जिससे कहा जा सके कि मोमबत्ती के रोज़ इस्तेमाल से कैंसर जैसी बीमारियां होने का ख़तरा हो सकता है.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

सच के सिपाही को धमकी

सवाल पूछना जनता का अधिकार है और यह अधिकार संविधान देता है, लेकिन सवाल पूछना कभी-कभी कितना तकलीफदेह हो सकता है, यह पिछले साल हुईं आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्याओं से साफ पता चलता है. कार्यकर्ताओं की हत्या, परेशान करने और धमकी देने के मामले तो लगभग हर महीने सामने आते रहते हैं. इस कॉलम में आज एक ऐसे ही आरटीआई कार्यकर्ता की बात करते हैं, जिनके आरटीआई आवेदनों की वजह से दिल्ली के संजय नगर (गुलाबी बाग) इलाके में अवैध रूप से गोदाम, हेवी ट्रकों के रिपेयर वर्कशॉप और अन्य गतिविधियां चलाने वालों का न सिर्फ पर्दाफाश हुआ, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हुई. यही बात इन माफियाओं को नागवार गुजरी. नतीजतन, उन्होंने इस आरटीआई आवेदक को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से धमकाना शुरू किया. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहुत पहले ही इन वर्कशॉप, गोदामों एवं फैक्ट्रियों को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर और बवाना में जमीनें दी जा चुकी हैं. बावजूद इसके आवासीय इलाके से इन अवैध गतिविधियों को हटाया नहीं जा सका है. सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि अवैध रूप से चलाए जा रहे गोदामों, वर्कशॉप और फैक्ट्रियों के बिजली-पानी के कनेक्शन काटे जाएं.

दरअसल, संजय नगर (गुलाबी बाग) निवासी सतीश शर्मा ने अपने क्षेत्र में देखा कि वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए आवासीय इलाके में अवैध रूप से गोदाम बने हुए हैं, हेवी ट्रकों के वर्कशॉप चल रहे हैं. इस पर उन्होंने इस सबके बारे में पहले दिल्ली नगर निगम, उसके लाइसेंसिंग विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उद्योग विभाग में शिकायत की. शिकायत दर्ज कराने के कुछ दिनों बाद सतीश शर्मा ने सूचना कानून के तहत आवेदन देकर इस संबंध में सूचना मांगी. लगभग सारे विभाग पहले सूचना देने में आनाकानी करते रहे, लेकिन सतीश शर्मा इस

सतीश शर्मा, आरटीआई कार्यकर्ता.

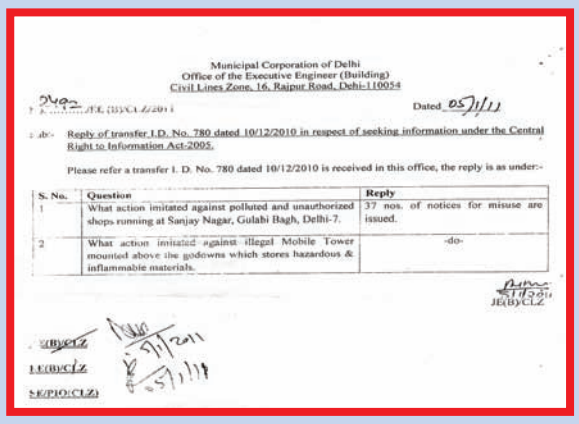

Municipal Corporation of Delhi
Office of the Executive Engineer (Building)
Civil Lines Zone, 16, Rajpur Road, Dehi-110054

2492/E.E.(B)/CLZ/2011 Dated 05/1/11

Sub:- Reply of transfer I.D. No. 780 dated 10/12/2010 in respect of seeking information under the Central Right to Information Act-2005.

Please refer a transfer I. D. No. 780 dated 10/12/2010 is received in this office, the reply is as under:-

S. No.	Question	Reply
1	What action imitated against polluted and unauthorized shops running at Sanjay Nagar, Gulabi Bagh, Delhi-7.	37 nos. of notices for misuse are issued.
2	What action imitated against illegal Mobile Tower mounted above the godowns which stores hazardous & inflammable materials.	-do-

JE(B)CLZ

E(B)CLZ
EE(B)CLZ
SE/PIO(CLZ)

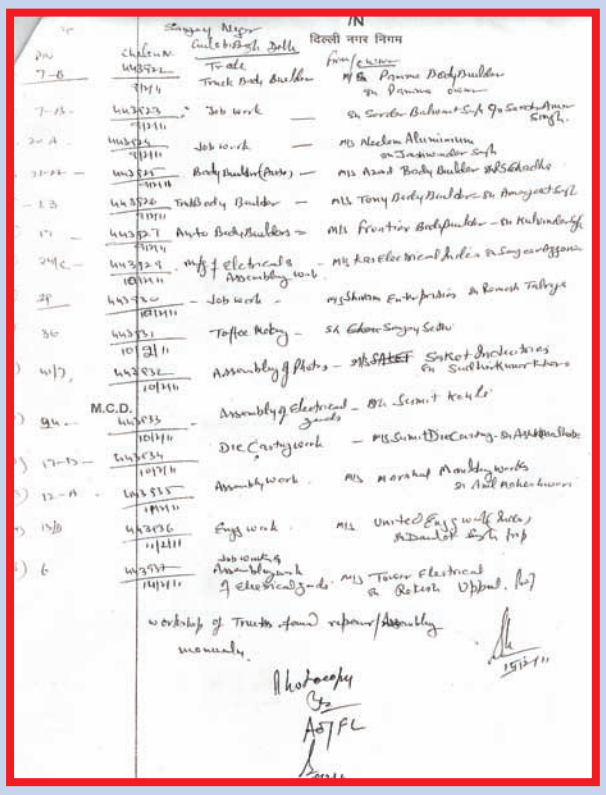

लड़ाई को आगे ले जाते रहे. अपील में जाने के बाद उन्हें कुछ सूचनाएं मिलनी शुरू हुईं. पता चला कि 37 नोटिस जारी किए जा चुके हैं और चालान काटे जा रहे हैं. संबंधित विभाग सक्रिय हुए. लाइसेंसिंग विभाग के लोग इलाके में पहुंच कर चालान काटने लगे. इस सबसे अवैध गतिविधियां चलाने वाले माफियाओं ने आरटीआई कार्यकर्ता सतीश शर्मा को सबक सिखाने की ठान ली और उन्हें धमकी भरे फोन आने लगे. आस-पड़ोस के लोगों से सतीश शर्मा को संदेश भिजवाया जा रहा है कि वह चुपचाप बैठ जाएं और इस मामले को यहीं खत्म कर दें, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे.

चौथी दुनिया से बातचीत करते हुए सतीश शर्मा कहते हैं कि आवासीय इलाके में चल रही इन अवैध गतिविधियों की वजह से प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है, साथ ही यहां के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और आम लोगों को भी कई तकलीफें उठानी पड़ रही हैं. यही सब देखते हुए मैंने इनके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए आरटीआई का सहारा लिया. इसमें सफल भी हुआ, लेकिन अब लोग मुझे धमकी दे और दिलवा रहे हैं. मुझे आशंका है कि ये लोग कोई ऐसी चाल चलेंगे, जिससे ये मुझे फंसा सकें. जाहिर है, ये माफिया ऐसे लोग हैं, जिनके पास न तो पैसे की कमी है और न ही पहुंच की. बहुत संभव है कि ऐसे में सतीश शर्मा के साथ भी कुछ वैसा ही हो जाए, जो पिछले कुछ महीनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में आरटीआई कार्यकर्ताओं के साथ हो चुका है.

बहरहाल, जब संविधान ने जनता को सवाल पूछने का अधिकार दिया है तो पुलिस-प्रशासन में बैठे अधिकारियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे सच के इन सिपाहियों को सुरक्षा प्रदान करें और धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

कैंडल लाइट डिनर पर मत जाना

अब तक रोमांस के लिए कैंडल लाइट डिनर को सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है. किसी शांत जगह में अपनी महिला मित्र के साथ कैंडल लाइट डिनर यानी मोमबत्ती की दूधिया रोशनी में भोजन करना भला किसे पसंद नहीं होगा, लेकिन अब कुछ लोग इसे ख़तरनाक बता रहे हैं. शोधकर्ताओं ने आगाह किया है कि ऐसे रूमानी भोज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं. साउथ कैरोलाइना स्टेट यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने मोमबत्तियों से निकलने वाले धुएं का परीक्षण किया है. उन्होंने पाया कि पैराफ़ीन की मोमबत्तियों से निकलने वाले हानिकारक धुएं का संबंध फेफड़े के कैंसर और दमा जैसी बीमारियों से है. हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी माना कि मोमबत्ती से निकलने वाले धुएं का स्वास्थ्य पर हानिकारक असर पड़ने में कई वर्ष लग सकते हैं. ब्रिटेन के विशेषज्ञों का कहना है कि धूम्रपान, मोटापे और शराब सेवन से कैंसर होने का ख़तरा ज़्यादा है. विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि मोमबत्तियों के कभी-कभी इस्तेमाल से लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. मुख्य शोधकर्ता आमिर हमीदी का कहना है कि जो लोग पैराफ़ीन मोमबत्तियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वे ख़तरे के दायरे में हैं. आमिर ने वाशिंगटन स्थित अमेरिकन केमिकल सोसाइटी को बताया कि कभी-कभी मोमबत्तियों के इस्तेमाल और उनसे निकलने वाले धुएं से ज़्यादा असर नहीं होगा. उनका कहना था, यदि कोई व्यक्ति कई वर्षों तक हर रोज़ पैराफ़ीन मोमबत्तियां जलाता है, ख़ासकर ऐसे कमरे में, जहां हवा आने-जाने का प्रावधान नहीं है, तब समस्या हो सकती है. जांच-पड़ताल के लिए शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में कई तरह की मोमबत्तियां जलाईं और उनसे निकलने वाले पदार्थ एकत्र किए. पैराफ़ीन आधारित मोमबत्तियों से निकलने वाले धुएं के परीक्षण से पता चला कि उनके जलने से पैदा होने वाला ताप इतना तेज़ नहीं होता, जिससे ख़तरनाक कण जैसे टॉल्युइन और बेंज़ीन पूरी तरह से जल पाएं. वैज्ञानिकों का कहना है कि मधुमक्खी के छत्ते से निकले मोम या सॉया से बनने वाली मोमबत्तियां जब जलती हैं तो उनसे इतनी ज़्यादा मात्रा में रसायन नहीं निकलता. वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि ऐसी ही मोमबत्तियों का इस्तेमाल किया जाए.

ब्रिटेन स्थित कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की डॉक्टर जोआना ओवेंस कहती हैं कि ऐसा कोई सीधा सबूत नहीं मिला है, जिससे कहा जा सके कि मोमबत्ती के रोज़ इस्तेमाल से कैंसर जैसी बीमारियां होने का ख़तरा हो सकता है. ओवेंस कहती हैं कि बंद कमरे में अगर सिगरेट पी जाए तो उससे प्रदूषण बढ़ता है और यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है. जब हम कैंसर की बात करते हैं तो हमें पक्के सबूतों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. सिगरेट, शराब, मोटापा और खाने-पीने की ग़लत आदतों से कैंसर होने की आशंका ज़्यादा होती है. ब्रिटिश लंग फ़ाउंडेशन की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर नोएमी आइज़र कहती हैं कि पैराफ़ीन मोमबत्तियों के कभी-कभी इस्तेमाल से फेफड़ों को ख़तरा नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों को मोमबत्ती जलाते वक़्त कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे कि मोमबत्तियां खुले हवादार कमरों में जलाई जाएं. अगर आप भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कैंडल लाइट डिनर पर जा रहे हैं तो एक बार ज़रूर सोचिएगा.

एक साथ 12 बच्चे!

अभी आप जो पढ़ेंगे, वह निश्चित तौर पर आपको चौंका देगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है. ट्यूनीशिया की एक महिला एक साथ 12 बच्चों को जन्म देकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है. गल्फ न्यूज़ वेबसाइट में प्रकाशित ख़बर के मुताबिक़ , इस 30 वर्षीय महिला का इससे पहले दो बार गर्भपात हो चुका है. दक्षिण-पश्चिम ट्यूनीशिया के गाफसा की मूल निवासी यह महिला अरबी भाषा की अध्यापिका है. हालांकि इस काम को इतने हल्के में नहीं लिया जा रहा है. डॉक्टरों ने उसे इससे होने वाले ख़तरों से चेताया और कहा कि इनमें से किसी भी शिशु के जीवित रहने की संभावना न के बराबर है. महिला का कहना है कि वह स्वाभाविक तरीक़े से छह बच्चों और छह बच्चियों को जन्म देना चाहती है, लेकिन चिकित्सकों का कहना है कि ऐसी स्थिति में उसके जीवन को ख़तरा उत्पन्न हो सकता है. वेबसाइट पर महिला के पति की ओर से लिखा गया है कि शुरू में हमने सोचा था, मेरी पत्नी को जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, लेकिन बाद में कई सारे भ्रूणों के बारे में पता चला. भ्रूणों की संख्या बढ़ने के साथ ही हमारी ख़ुशी बढ़ती गई.

फ़िलहाल 10 या उनसे अधिक शिशुओं के एक साथ जन्म लेने के बाद उनके जीवित बचने का कोई उदाहरण नहीं है. अब देखते हैं, उक्त शिक्षिका इस ख़तरे का सामना किस तरह करती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष 21 मार्च से 20 अप्रैल
किसी रचनात्मक कार्य के लिए सप्ताह का पहला दिन अच्छा रहेगा. हो सकता है कि आपका मन कहीं बाहर चलकर लंच या डिनर करने का कर रहा हो, परंतु उसके बाद का समय आप पूरी तरह रखरखाव और साजसज्जा के काम में लगाएं.

वृष 21 अप्रैल से 20 मई
सप्ताह के मध्य में घर के सदस्यों के सहयोग के कारण ज़रूरी कामों से राहत मिलेगी. शाम को बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए घर से कहीं दूर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. यात्रा के समय सावधानी बरतें.

मिथुन 21 मई से 20 जून
यह सप्ताह किसी भी काम को शुरू करने के लिए अच्छा है. पूजा-पाठ या मंदिर आदि जाने से आपकी मन:स्थिति सुधर सकती है. कुछ कर दिखाने का आत्मविश्वास अगर पक्का है तो निश्चित सफलता मिल सकती है. सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य लाभ होगा.

कर्क 21 जून से 20 जुलाई
सप्ताह का पहला दिन काफी व्यस्त रहेगा. दोपहर तक आपको अपने कार्यस्थल या व्यवसाय में ज़रूरी बैठकें करनी होंगी. सबको हिदायत देनी होगी और आपूर्तिकर्ताओं या व्यवसाइयों से बातचीत करनी होगी.

सिंह 21 जुलाई से 20 अगस्त
इस सप्ताह अपने व्यवसाय में आपका योगदान सबसे अच्छा रहेगा. यदि किसी रिटायर होने वाले व्यक्ति का फेयरवेल आयोजित करना है तो आपसे बेहतर ऑर्गनाइज़र और कौन हो सकता है, लेकिन यह काम आप टाल सकते हैं.

कन्या 21 अगस्त से 20 सितंबर
इस सप्ताह आपको बहुत इत्मीनान और शांति से अपने विवाद ख़त्म करने हैं. सप्ताह के मध्य में जीवनसाथी या मित्र का साथ देना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि लगभग सभी मामलों में आपको उन्हीं से मदद मिलती है.

तुला 21 सितंबर से 20 अक्टूबर
इस सप्ताह किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति से मिलने का अच्छा मौक़ा है. अगर आपको बिना सूचित किए किसी से मिलने जाना हो तो ज़रा संभल कर ही आगे बढ़ें, क्योंकि शाम के समय की गई यात्रा व्यर्थ जा सकती है.

वृश्चिक 21 अक्टूबर से 20 नवंबर
इस सप्ताह जुगाड़बाज़ी के तौर तरीक़े अपनाकर आप अपने किसी तकनीकी फॉल्ट को दुरुस्त करने में कामयाब हो सकते हैं. किसी कारण से रुके हुए कार्य अचानक बनने लगेंगे.

धनु 21 नवंबर से 20 दिसंबर
रोज़गार या नौकरी के मामले में यदि आप परेशान हैं तो चिंता न करें. इस सप्ताह कोई ऐसा मौक़ा आएगा, जिससे आपकी बेकारी की समस्या का हल निकल सकता है, बशर्ते आप प्रतिष्ठा का सवाल न बनाएं.

मकर 21 दिसंबर से 20 जनवरी
इस सप्ताह आपको तरह-तरह के संकल्प करने पड़ेंगे, लेकिन सप्ताह के मध्य तक इनसे मुक्ति मिलेगी. व्यवसाय या कार्यस्थल पर जो समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, वह अचानक हल होती नज़र आएगी. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

कुंभ 21 जनवरी से 20 फरवरी
इस सप्ताह यदि आप अपने मान-सम्मान पर कोई दाग़ लगते नहीं देखना चाहते तो उन लोगों का हिसाब-किताब चुकता कर दें, जिन्हें आपने काफी लंबे समय से लटका रखा है. अगर किसी से वसूली करनी हो तो उसके लिए भी समय अच्छा है.

मीन 21 फरवरी से 20 मार्च
इस सप्ताह आपको कुछ ज़्यादा ही भाग-दौड़ करनी पड़ सकती है. व्यवसाय के कामों में आपकी मौजूदगी ज़रूरी होगी. सप्ताह के अंत में परिवार के छोटे सदस्यों के स्कूल-कॉलेज में एडमिशन या फिर रोज़गार की समस्या परेशान कर सकती है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

लीबिया के मुद्दे पर विश्व अब दो धड़ों में बंट रहा है. अमेरिका विरोधी देश धीरे-धीरे गद्दाफ़ी के पक्ष में आ रहे हैं या फिर चुप हैं. वहीं बेला रूस भी लीबिया के समर्थन में आ गया है.

लीबिया

सेना मुग्ध, जनता क्षुब्ध

राजीव रंजन तिवारी

पहले ट्यूनीशिया, फिर मिस्र के बाद लीबिया में मोअम्मर गद्दाफ़ी के तानाशाही शासन के विरुद्ध जन विद्रोह भड़का तो लगा कि अब गद्दाफ़ी का हश्र भी ट्यूनीशिया और मिस्र के शासकों की तरह होगा, लेकिन यहां की कहानी लगातार बदलती जा रही है. लगता है, गद्दाफ़ी सद्दाम हुसैन को अपना रोल मॉडल मान रहे हैं. तमाम जन विद्रोह के बावजूद सेना गद्दाफ़ी के साथ है. गद्दाफ़ी की एक आवाज़ पर सैनिक नागरिकों को जीव-जंतुओं की तरह मार रहे हैं और बूटों से कुचल रहे हैं. यह भी कह सकते हैं कि गद्दाफ़ी को अपने सैनिकों पर न सिर्फ़ भरोसा है, बल्कि उनकी पकड़ भी अन्य शासकों से अलग है. यही वजह है कि लीबियाई सैनिकों के मन में वहां की जनता के प्रति कोई संवेदना नहीं है, वे सिर्फ़ अपने कर्नल यानी गद्दाफ़ी की आवाज़ सुन रहे हैं, जबकि दुनिया के कुछ ख़ास देशों यानी अमेरिका, ब्रिटेन एवं फ्रांस ने गद्दाफ़ी के विरुद्ध खुले संघर्ष का ऐलान कर दिया है, फिर भी उस पर कोई असर नहीं है. इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति से अमेरिका ने लीबिया को नो फ्लाइंग जोन की श्रेणी में रख दिया है, बावजूद इसके गद्दाफ़ी झुकने के लिए तैयार नहीं हैं.

दरअसल होता यह है कि शासकों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न की सीमा जब पार हो जाती है तो नागरिकों के सब्र का बांध भी टूट जाता है. जैसा ट्यूनीशिया एवं मिस्र में हुआ और अब लीबिया में हो रहा है. उन दोनों देशों के तानाशाह शासकों को तो गद्दी तक छोड़कर भागना पड़ा था, लेकिन गद्दाफ़ी तमाम ज़लालत झेलते हुए भी कुर्सी से चिपके हुए हैं. लगता है, वह सद्दाम हुसैन को रोल मॉडल मानते हुए दूसरा हिटलर बनने का ख्वाब पाले हुए हैं. लीबियाई जनता पर ढाए जा रहे ज़ुल्म से संयुक्त राष्ट्र महासभा भी बेहद नाराज़ है. ब्रिटेन और अमेरिका ने तो खुलेआम यह घोषणा कर रखी है कि गद्दाफ़ी को ज़िंदा या मुर्दा गिरफ्तार कराने वाले को 10 मिलियन डॉलर का ईनाम दिया जाएगा. मौजूदा हालात ये हैं कि लीबिया के कई शहरों में गद्दाफ़ी समर्थकों और विरोधियों के बीच जंग जारी है. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि गद्दाफ़ी देश में अपनी वैधता खो चुके हैं, इसलिए उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए.

दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र के संक्षिप्त प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया है कि लीबिया में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है. संयुक्त राष्ट्र महासभा की मानवाधिकार परिषद में लीबिया के बने रहने के अधिकार को ख़त्म करने का निर्णय भी लिया गया. बताते हैं कि गद्दाफ़ी के वफ़ादार सैनिकों द्वारा सैकड़ों लोगों की हत्या और पश्चिमी लीबिया में मानवीय सहायता रोकने के कारण 1,40,000 से ज़्यादा लोग वहां से मिस्र और ट्यूनीशिया चले गए हैं. इस पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ की शरणार्थी एजेंसी गंभीर है. उधर इंटरपोल ने गद्दाफ़ी और उनके 15 परिवारीजनों एवं सहयोगियों के ख़िलाफ़ अलर्ट जारी कर दिया है. 20 वर्ष पहले अमेरिकी बमबारी में क्षतिग्रस्त हुई एक इमारत से देश को संबोधित करते हुए लीबियाई नेता गद्दाफ़ी ने कहा था कि उनके पास कोई पद नहीं है, इसलिए उनके इस्तीफ़ा देने का कोई सवाल नहीं पैदा होता. अब जहां एक ओर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कई लीबियाई राजनयिक और नेता लामबंद हो गए हैं तथा गृहमंत्री अब्देल फ़ताह यूनेस ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, वहीं गद्दाफ़ी ने चेतावनी दी है कि लीबिया के ख़िलाफ़ जो हथियार उठाएगा, उसे जान से मार दिया जाएगा. गद्दाफ़ी वर्ष 1969 से सत्ता में हैं. लीबिया की जनसंख्या 65 लाख है, साक्षरता दर 88 प्रतिशत है. जनसंख्या की औसत उम्र 24.2 साल है. प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय 12 हज़ार डॉलर है. 1969 में तख्ता पलट के ज़रिए सत्ता हासिल करने वाले गद्दाफ़ी के ख़िलाफ़ शुरू हुई बग़ावत को वहां की सेना कुचल रही है.

संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने कर्नल गद्दाफ़ी की सेना की ओर से हुई कथित ज़्यादतियों की जांच शुरू कर दी है. गद्दाफ़ी समर्थक सेना ने दावा किया है कि राजधानी त्रिपोली से 50 किलोमीटर दूर ज़ाविया पर सरकार का 95 फ़ीसदी क़ब्ज़ा हो गया है. उधर गद्दाफ़ी के आचरण से तंग आकर संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया को नो फ्लाइंग जोन की श्रेणी में लाने का निर्णय लिया है. इस पर टिप्पणी करते हुए गद्दाफ़ी का कहना है कि अगर संयुक्त राष्ट्र की ओर से लीबिया को नो फ्लाइंग जोन बनाया जाता है तो उनके लोग हथियार उठा लेंगे. नो फ्लाइंग ज़ोन बनाए जाने का मतलब है कि पश्चिमी देश लीबिया के संसाधनों पर क़ब्ज़ा करना चाहते हैं. 1991 में हुए पहले खाड़ी युद्ध में इराक़ और 1994-95 में बोस्निया को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया था. खाड़ी के देशों ने लीबिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने का समर्थन किया है.

बक़ौल गद्दाफ़ी, यूरोपीय देशों की सरकारें और अलक़ायदा जैसे संगठन लीबिया को बांटना चाहते हैं. बावजूद इसके गद्दाफ़ी के विरोधी उनके सत्ता छोड़ने और व्यापक राजनीतिक सुधारों की मांग कर रहे हैं. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद विद्रोहियों के क़ब्ज़े वाले पूर्वी लीबिया के इलाक़ों में हथियार पहुंचाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि लीबिया के संदर्भ में नो फ्लाइंग जोन जैसा फ़ैसला अमेरिका को नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र को ही लेना चाहिए.

यूरोपीय संसद के सदस्यों ने गद्दाफ़ी विरोधियों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश के तहत एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें यूरोपीय देशों के नेताओं से अनुरोध किया गया है कि लीबिया में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए वहां की राष्ट्रीय अंतरिम परिषद से संवाद स्थापित किया जाए. राष्ट्रीय अंतरिम परिषद विद्रोहियों के नेताओं की परिषद है. उधर गद्दाफ़ी का कहना है कि उनकी सेना जल्द ही पूरे देश को विद्रोहियों के नियंत्रण से बाहर निकाल लेगी. गद्दाफ़ी समर्थक वायु सेना द्वारा प्रदर्शनकारियों पर किए जा रहे हमलों को देखते हुए पश्चिमी देश लीबिया को जल्द से जल्द नो फ्लाइंग जोन घोषित करना चाहते हैं, लेकिन गद्दाफ़ी ने साफ़ कर दिया है कि यदि इस तरह का कोई प्रयास किया गया तो इसका जवाब हथियार से ही दिया जाएगा. गद्दाफ़ी ने प्रमुख विरोधी नेता अब्दुल जलील पर 4,00,000 डॉलर (यानी क़रीब 1.8 करोड़ रुपये) का ईनाम रखा है. लेकिन अमेरिका के इस निर्णय का अर्थ गृह युद्ध से जूझ रहे एक देश में फ़ौजी हस्तक्षेप करना होगा, जो अरब देशों ख़ासकर ईरान को क़तई मंज़ूर नहीं है.

लीबिया के मुद्दे पर विश्व अब दो धड़ों में बंट रहा है. अमेरिका विरोधी देश धीरे-धीरे गद्दाफ़ी के पक्ष में आ रहे हैं या फिर चुप हैं. वहीं बेला रूस भी लीबिया के समर्थन में आ गया है. दोनों देशों के बीच कई विमानों को उड़ान भरते देखा गया है. यही नहीं, हथियारों से लैस कई पोत बेला रूस से लीबिया पहुंच चुके हैं. पहले दो विश्व युद्धों की तरह की स्थितियां इस बार भी बन रही हैं. अमेरिका की निगाहें तेल निर्यातक देशों पर हैं. इसी के चलते उसने रासायनिक हथियारों की जांच की आड़ में इराक़ पर हमला करके सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया. अब मिस्र और लीबिया में भी वह हस्तक्षेप कर रहा है. मध्य-पूर्व के देश अमेरिका के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं. फ्रांस लीबिया में गद्दाफ़ी का विरोध कर रही नेशनल लीबियन काउंसिल (एनएलसी) को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है. उसने कहा है कि एनएलसी ही लीबिया के लोगों का वैध प्रतिनिधित्व करती है.

feedback@chauthiduniya.com

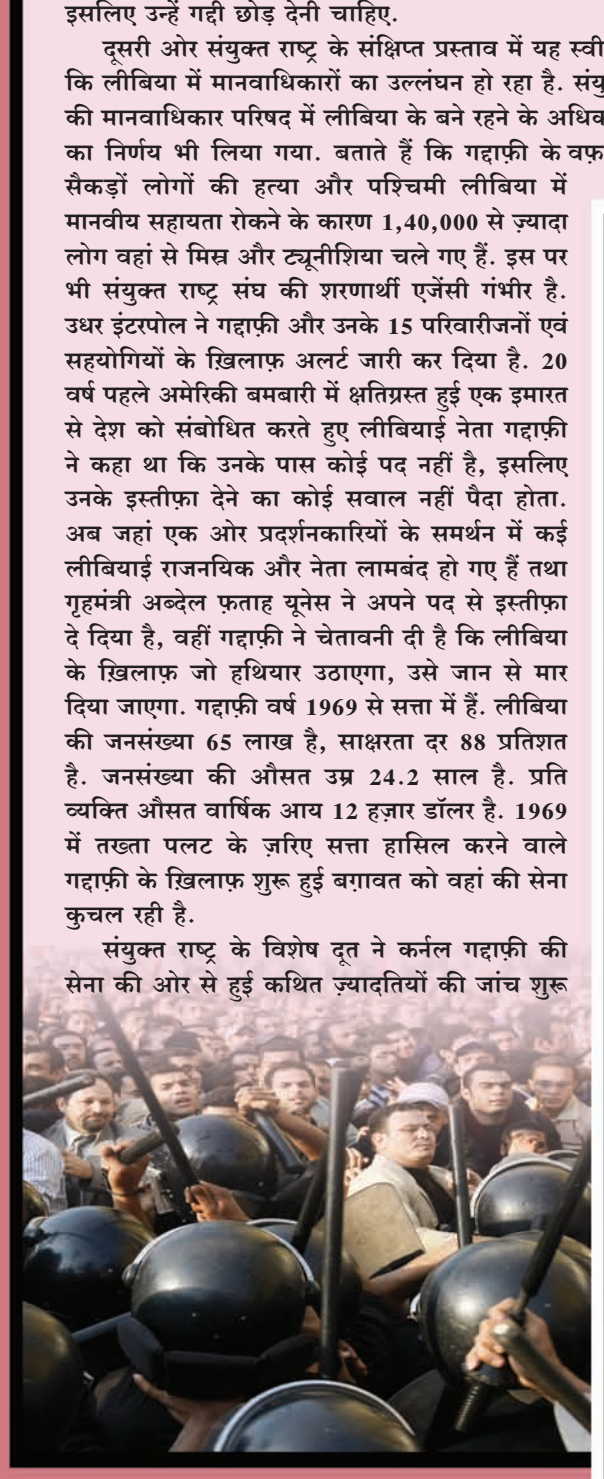

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

सृष्टि चक्र में हम उस मोड़ पर हैं, जब सिर्फ़ उसके प्रति सजग होने की आवश्यकता है, उसके होने का अनुभव स्वतः ही होने लगेगा.

ईश्वरीय सेवा के निमित्त

ऑसिम खेत्रपाल

क भी आपने सोचा कि कोई व्यक्ति महात्मा, साधु-संत क्यों बनता है और कोई गृहस्थ व्यापारी, चोर, डाकू, वैज्ञानिक, डॉक्टर या भिखारी क्यों बनता है? कितनी बार साधु-संतों के बारे में सोचता हूं तो मन में आता है कि ये कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं, जो प्रभु भजन में ही लीन हैं, परमात्मा की याद में ही मग्न रहती हैं, परमात्मा की ही बात करती हैं, उसके काम में लगी हैं, लेकिन ज़रा सोचें कि वे ऐसे क्यों और हम ऐसे क्यों? जवाब आता है क़िस्मत की बात, पिछले कर्मों का फल. पिछले जन्म में हम क्या थे, कौन थे, कैसे थे, कोई नहीं जानता. पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी पक्का सबूत नहीं होता, लेकिन आज हम जो हैं, जैसे हैं, जहां हैं, क्या वह भी पूरी तरह जान पाते हैं? क्या हमें अपनी संपूर्ण क्षमता का ज्ञान है? हम किस हद तक अच्छे या बुरे कर्म करने की क्षमता रखते हैं, क्या इसका ज्ञान है हमें? समझना यह है कि अच्छा और बुरा क्या? आज जिस स्टेज पर समाज का चरित्र खड़ा है, हमें स्वयं ही असमंजस है कि सही या ग़लत क्या? नानी, दादी, बड़े-बूढ़ों की सीख थी कि मन की आवाज़ सुनो. अंदर की आवाज़ सही रास्ते का फ़ैसला कर देगी, लेकिन आज की इस बाहरी शोर से भरी ज़िंदगी में अंदर की आवाज़ आनी भी तो बंद हो गई है. फिर कभी-कभी वह आवाज़ गुहार लगाती है तो हम उसे बहला- फुसला कर, डांट-डपट कर, मजबूरियों की दुहाई देकर, समय की मांग कहकर हर बार बंद कर देते हैं, तभी तो कर्मों का बोझ उठाए थके-हारे-चिड़चिड़े से इस ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं.

मन तो करता है कि इस भंवर से बाहर निकल जाएं, ज़िंदगी की इस किताब को एक नए सिरे से शुरू कर पाएं, लेकिन कुछ भी करने से पहले डर लगता है कि अपनी बनी-बनाई ज़िंदगी को बदलना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा. पर अगर सब कुछ जैसा चल रहा, वैसा ही चलता रहे और जो बदलना है, वह आपके अंदर ही बदले, तब क्या होगा. ऐसा ही होता है, जब परमात्मा की शक्ति का अनुभव आप जीवन में करते हैं. सृष्टि चक्र में हम उस मोड़ पर हैं, जब सिर्फ़ उसके प्रति सजग होने की आवश्यकता है, उसके होने का अनुभव स्वतः ही होने लगेगा. वह आपके जीवन के हर पल का साथी बन जाएगा, जब आप उसे पुकार कर साथी बनाएंगे. अब वह आपके जीवन के हर मुद्दे का साथी होगा तो आप भी तो उसके जीवन में शामिल होंगे. ज़रूरत इस बात की है कि हम यह देखें कि उसका कार्य, उसका परिवार कौन सा है. यह पूरा संसार उसका परिवार और हर आत्मा को प्रेम, शांति, उमंग, उल्लास एवं शक्ति का एहसास दिलाना उसका काम. अब सोचें कि परमात्मा के कार्य का हिस्सा बनने में कितना समय लगेगा और क्या जीवन का बाक़ी कुछ छूटेगा? नहीं न, तो आज ही इस जागरूकता के साथ परमात्मा के कार्य के निमित्त बनें, आपके काम स्वयं होते जाएंगे.

ओम साई राम.

feedback@chauthiduniya.com

पहेली का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साई सच्चरित्र का पाठ करें. सात दिन के अंदर इसका संपूर्ण पाठ करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी.

इस बार का प्रश्न है-साई बाबा ने अपने भक्त से एक बार दक्षिणा में कितने पैसे मांगे थे? सही जवाब भेजने वाले तीन विजेता पाठकों को फाउंडेशन की ओर से आकर्षक ईनाम मिलेंगे. आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं इस पते पर

शिरडी साई बाबा फाउंडेशन
एच 252, कैलाश प्लाजा, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश
नई दिल्ली- 110065
आप अपने जवाब info@ssbf.in भी पर भी भेज सकते हैं.
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें.
011-46567351, 46567352

ग्यारह वचन

१. जो शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा।
२. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर। पैर तले दुःख की पीढ़ी पर।
३. त्याग शरीर चला जाऊँगा। भक्त हेतु दौडा आऊँगा।
४. मन में रखना दृढ़ विश्वास। करे समाधी पूरी आस।
५. मुझे सदा जीवित ही जानो। अनुभव करो सत्य पहचानो।
६. मेरी शरण आ खाली जाए। हो कोई तो मुझे बताए।
७. जैसा भाव रहा जिस मन का। वैसा रूप हुआ मेरे मन का।
८. भार तुम्हारा मुझ पर होगा। वचन न मेरा झूठा होगा।
९. आ सहायता लो भरपूर। जो माँगा वह नही है दूर।
१०. मुझ में लीन वचन मन काया। उसका ऋण न कभी चुकाया।
११. धन्य धन्य व भक्त अनन्य। मेरी शरण तज जिसे न अन्य।

संपर्क करें:
शिरडी साई बाबा फाउन्डेशन
252-H, LGF कैलाश प्लाज़ा, सन्तनगर, ईस्ट अफ् कैलाश, मेन रोड, नई दिल्ली-110065.
Tel./Fax: 91-11-46567351/52
web: www.ssbf.in

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

Giriraj Sai Hills

Sai Vihar Township
Spiritual home... away from home

- Fully Furnished and Spacious studio Apartments.
- One Bedroom Apartments.
- Two bedroom Apartments.
- Fully Furnished Villas.

STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*

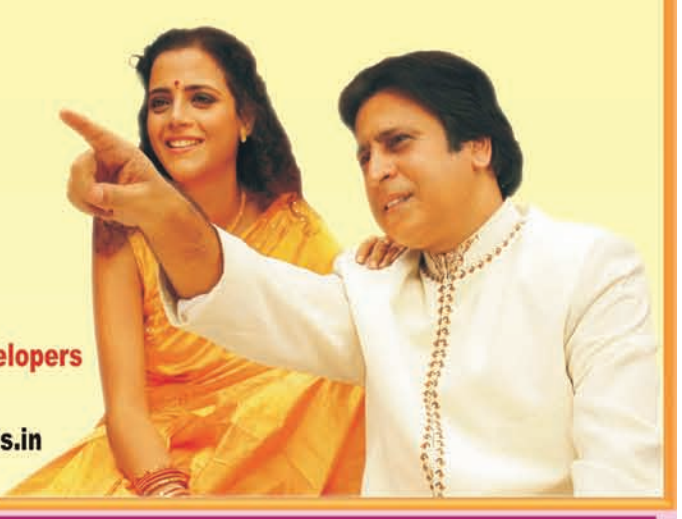

AUM Infrastructure & Developers
Aum Infrastructure & Developers
Email: info@ssbf.in
Website: www.girirajsaihills.in

श्री साई महिमा

श्री साई राम परम सत्य, प्रकाश रूप, परम पावन शिरडी निवासी, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, प्रज्ञा प्रदाता, सच्चिदानंद स्वरूप, परम पुरूष योगीराज, दयालु देवाधिदेव हैं, उनको बार बार नमस्कार.

ज्ञानोदय

असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरे प्रयास नहीं किए गए. *स्व. मालती कपूर*

मां होने के कारण नारी का स्थान भगवान से भी ऊंचा है. *प्रेमचंद*

विचारों को दबाया नहीं जा सकता. एक दिन विचार कंदरा फोड़ कर संसार पर छा जाते हैं. *स्व. तारा चंद्र मेहरोत्रा*

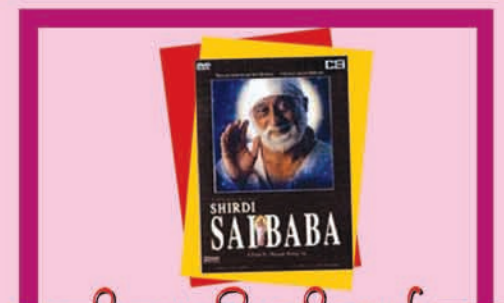

पहली बार शिरडी साई बाबा फीचर फिल्म अब कॉमिक्स के रूप में

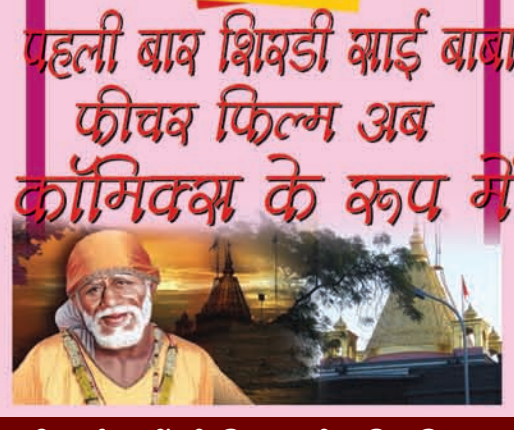

सभी साई भक्तों को विनम्रता से सूचित किया जाता है कि आप अपने साई अनुभव, साई उत्सवों आदि की विस्तृत सूचना, फाउंडेशन में सदस्यता के लिए info@ssbf.in पर मेल या 011-46567351/52 पर संपर्क कर सकते हैं.

परमानंद पांडेय को इस सदी का सर्वश्रेष्ठ भाषा वैज्ञानिक मानकर उनकी उपलब्धियों पर आज गर्व किया जा रहा ह

पत्रकारिता के अभिमन्यु!

ब्लॉग पर जिस तरह से व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए ऊलजुलूल बातें लिखी जा रही हैं, वह बेहद निराशाजनक है. कई ब्लॉग तो ऐसे हैं, जहां पहले किसी फर्जी नाम से कोई लेख लिखा जाता है, फिर बेनामी टिप्पणियां छापकर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता है. कुछ कमज़ोर लोग इस तरह की ब्लैकमेलिंग के शिकार हो जाते हैं और कुछ ले-देकर अपना पल्ला छुड़ाते हैं.

अनंत विजय

पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजी डीएवी कॉलेज में हिंदी पत्रकारिता और ग्लोबल समस्याएं विषय पर एक सेमिनार आयोजित था. कॉलेज के उत्साही शिक्षक डॉ. हरीश अरोड़ा ने बेहद श्रमपूर्वक दो दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की थी. इस संगोष्ठी के अंतिम दिन और अंतिम सत्र में मुझे भी बोलना था. मेरे साथ वक्ता थीं आउटलुक साप्ताहिक की सहायक संपादक गीताश्री और हमारे सत्र के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के के एएम मुंशी इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी स्टडीज के प्रोफेसर हरिमोहन. दो विद्वान वक्ताओं के बीच में मुझे ही सबसे पहले बोलना था. गीता जी मुझसे वरिष्ठ हैं और नब्बे के शुरुआती दशक में जब मैं दिल्ली आया था और काम और पहचान की तलाश में जूझ रहा था तो गीता जी ने ही मुझे पहला असाइनमेंट दिया था. उस वक़्त वह स्वतंत्र भारत अख़बार के आईएनएस दफ्तर में बैठती थीं. इस अवांतर प्रसंग की चर्चा इस वजह से कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दोनों से पहले बोलना था और मेरी हालात ख़राब हो रही थी.

जब मैं वहां पहुंचा तो सभागार लगभग भरा हुआ था, लेकिन यह जानकर आश्चर्य हुआ कि श्रोताओं में दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों के पत्रकारिता विभाग से जुड़े शिक्षक मौजूद थे. पहले मुझे यह अंदाज़ था कि कॉलेज के पत्रकारिता विभाग के छात्र होंगे, जिनसे बातचीत करनी होगी. ख़ैर समारोह शुरू हुआ और मंच संचालन कर रहे सज्जन ने पत्रकारिता के गिरते स्तर पर चिंता जताते हुए पिछले दिन और पूर्वान्ह के सत्र में हुई बातचीत का संक्षिप्त ब्योरा दिया. पहली बात उन्होंने कही कि पूर्ववर्ती वक्ताओं ने मीडिया, ख़ासकर न्यूज़ चैनलों के गिरते स्तर पर चिंता जताई. उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यूज़ चैनलों में काम करने वाले पत्रकारों ने ख़ुद को अभिमन्यु बताया और कहा कि वे पत्रकारिता के चक्रव्यूह में फंस गए हैं और उससे निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लिहाज़ा वहीं नौकरी करने को अभिशप्त हैं. दूसरी बात, उन्होंने ब्लॉग के माध्यम से हो रही पत्रकारिता को प्रमुखता से रेखांकित किया. इस भूमिका के बाद उन्होंने मुझे मंच पर आमंत्रित कर लिया.

मैंने सबसे पहले ख़बरिया चैनलों के अभिमन्युओं को पत्रकारिता के चक्रव्यूह में फंसे होने पर दुःख प्रकट किया. मेरा साफ़ तौर पर मानना है कि न्यूज़ चैनलों में कुछ ऐसे पत्रकारों की जमात है, जो न्यूज़ चैनल के मंच का, उसके ग्लैमर का, उसकी पहुंच का इस्तेमाल कर अपनी छवि भी चमकाते हैं और जब भी जहां भी सार्वजनिक तौर पर बोलने का मौक़ा मिलता है, वहां न्यूज़ चैनलों को गरियाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते. उनका यह रूप और चरित्र मुझे हमेशा से परेशान करता है. मेरा मानना है कि यह अपने पेशे से एक तरह का छलात्कार है, जो क्षणिक तो मजा देता है, लेकिन पत्रकारिता का बड़ा नुक़सान कर डालता है. ख़ुद की छवि को चमकाने के लिए पत्रकारिता पर सवाल खड़े करने वाले इन पत्रकारों की वजह से दूसरे लोगों को आलोचना का मौक़ा और मंच दोनों मिल जाता है. मेरा मीडिया के उन अभिमन्युओं से नम्र निवेदन है कि वे अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसकर दम तोड़ने के बजाय युद्ध का मैदान छोड़ दें. अगर न्यूज़ चैनलों में उनका दम घुटता है तो वे वहां से तत्काल आज़ाद होकर अपना विरोध प्रकट करें, लेकिन जिसकी खाते हैं, उसको ही गरियाना कहां तक उचित है, यह मेरी समझ से बाहर है. मैं कई न्यूज़ चैनलों के अभिमन्युओं से वाक़िफ़ हूं और मेरे जानते अब तक ऐसा कोई वाकया सामने नहीं आया, जहां इस तरह के पत्रकार बंधुओं ने व्यवस्था का विरोध किया हो. विरोध करना तो दूर की बात, कभी अपनी नाख़ुशी भी जताई हो. मालिकों के सामने भीगी बिल्ली बने रहने वाले इन पत्रकारों को सार्वजनिक विलाप से बचना चाहिए, यह उनके भी हित में है और पत्रकारिता के हित में भी. किसी भी चीज की स्वस्थ आलोचना हमेशा से स्वागत योग्य है, लेकिन व्यक्तिगत छवि चमकाने के लिए की गई आलोचना निंदनीय है. दूसरी बात बताई गई कि हिंदी में ब्लॉग के माध्यम से बड़ा काम हो रहा है. यह बिल्कुल सही बात है कि ब्लॉग और नेट के माध्यम से हिंदी के लिए बड़ा काम हो रहा है, लेकिन कुछ ब्लॉगर और वेबसाइट जिस तरह से बेलगाम होते जा रहे हैं, वह हिंदी भाषा के लिए चिंता की बात है. ब्लॉग पर जिस तरह से व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए ऊलजुलूल बातें लिखी जा रही हैं, वह बेहद निराशाजनक है. कई ब्लॉग तो ऐसे हैं, जहां पहले किसी फर्जी नाम से कोई लेख लिखा जाता है, फिर बेनामी टिप्पणियां छापकर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता है. कुछ कमज़ोर लोग इस तरह की ब्लैकमेलिंग के शिकार हो जाते हैं और कुछ ले-देकर अपना पल्ला छुड़ाते हैं. लेकिन जिस तरह से ब्लॉग को ब्लैकमेलिंग और चरित्र हनन का हथियार बनाया जा रहा है, उससे ब्लॉग की आज़ादी और उसके भविष्य को लेकर ख़ासी चिंता होती है. बेलगाम होते ब्लॉग और वेबसाइट पर अगर समय रहते लगाम नहीं लगाई गई तो सरकार को इस दिशा में सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा. ब्लॉग एक सशक्त माध्यम है, गाली गलौच और बे सिर-पैर की बातें लिखकर अपने मन की भड़ास निकालने का मंच नहीं . इस बात पर हिंदी के झंडाबरदारों को गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है. मैंने विनम्रतापूर्वक ब्लॉग पर चल रहे इस घटिया खेल पर विरोध जताया और हॉल में फैले सन्नाटे से मुझे लगा कि वहां मौजूद लोग मेरी बातों से सहमत हैं.

चूंकि उक्त सेमिनार में दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्रकारिता पढ़ाने वाले शिक्षक उपस्थित थे और वैश्विक समस्या पर मुझे बोलना था. मुझे लगा कि पत्रकारिता की फैक्ट्री में काम करने वाले लोग वहां मौजूद हैं, इस वजह से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के सामने मुझे उनसे जुड़ी बात ही रखनी चाहिए. वैश्विक समस्या पर तो बाद में चर्चा हुई, लेकिन सबसे पहले मैंने पत्रकारिता के पाठ्यक्रम के बाबा आदम जमाने के होने की बात उठाई. कुछ दिनों पहले मैं देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक के पत्रकारिता के छात्रों से मिला था, जहां मैंने उनके सिलेबस पर बात की थी. प्रथम वर्ष में एक पेपर था–लेटर प्रेस और मुद्रण की विधियां. जब मैंने यह विषय देखा तो अपना सिर पीट लिया, क्योंकि अख़बार भी अब इनसे आगे निकल चुके थे. अब तो सारा कुछ कंप्यूटराइज़्ड होता है. वह दिन लदे भी अब सालों हो गए, जब लेटर प्रेस पर अख़बार छपा करते थे, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता के छात्रों को अब भी लेटर प्रेस और मुद्रण की विधियां पढ़ाई जा रही हैं. इसके अलावा भी अगर पत्रकारिता के पाठ्यक्रम को देखें तो उसे समय के हिसाब से बिल्कुल नहीं बदला गया है. पता नहीं, सालों पहले जब उसको बनाया गया था, उसके बाद किसी ने भी उसको अद्यतन करने की ज़रूरत समझी या नहीं.

अगर हम न्यूज़ चैनलों की कार्य पद्धति की बात करें तो उसमें तकनीक ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है और हर रोज कोई न कोई अपडेट हो रहा है, जिसकी छात्रों को तो दूर, विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी जानकारी नहीं. तो पत्रकारिता की फैक्ट्री में, जहां से देश के होनहार पत्रकार निकलते हैं, वहां यह आधारभूत दोष अब भी क़ायम है और इसको दूर करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जाना अफसोसनाक है. अपनी इस चिंता को मैंने सेमिनार में ज़ाहिर किया, जिस पर बाद में कई शिक्षकों ने कड़ी आपत्ति जताई कि उनके ज्ञान पर सरेआम सवाल कैसे खड़ा किया जा रहा है, लेकिन बातचीत के बाद उन्होंने माना कि तकनीक के अपडेशन के बारे में उनकी जानकारी नहीं के बराबर है. छात्रों को कैमरा पढ़ाने वाले शिक्षक ने शायद ही कभी कैमरा देखा-छुआ हो, यह ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन कम से कम कैमरा तकनीक में हुए आधुनिकीकरण के बारे में तो उसे जानकारी होनी ही चाहिए, न्यूज़ रूम सिस्टम के बारे में तो पता होना ही चाहिए.

सवाल सिर्फ़ पत्रकारिता के सिलेबस का नहीं है, सवाल अन्य विषयों का भी है, जिनके सिलेबस में समय के साथ बदलाव नहीं किया गया. शिक्षा के तमाम कर्ताधर्ताओं को भी कभी इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई. अब वक़्त आ गया है कि सरकार को इस ओर तत्काल ध्यान देकर इन खामियों को दूर करना होगा, ताकि देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके और कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा का उपयोग नौकरी में हो सके.

(लेखक आईबीएन-7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

परमानंद पांडेय

अंगिका भाषा के जनक

जादुई व्यक्तित्व, निश्छल एवं अलौकिक मुस्कराहट वाले डॉ. परमानंद पांडेय ने अंगिका को वैसे तराशा, जैसे कोई जौहरी किसी बेडौल-बेजान पत्थर को तराशता है. वह एक संवेदनशील कवि हैं. उनके रचनात्मक व्यक्तित्व ने साहित्य सर्जकों, पाठकों एवं प्रशंसकों को काफी अभिभूत किया है. अंगिका व्याकरण, अंगिका भाषा, अंगिका वर्तनी, अंगिकांजलि, अंगिका और भोजपुरी भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन, हिंदी और अंगिका का अंतर्संबंध आदि अपनी श्रेष्ठ कृतियों से डॉ. पांडेय ने अंगिका का भंडार समृद्ध कर दिया. परमानंद पांडेय को इस सदी का सर्वश्रेष्ठ भाषा वैज्ञानिक मानकर उनकी उपलब्धियों पर आज गर्व किया जा रहा है. आज अंगिका भाषा-भाषी क्षेत्रों का जो मानचित्र जहां-तहां पत्र-पत्रिकाओं में छप रहा है, वह भी डॉ. पांडेय का ही बनाया हुआ है, जो उन्होंने अपनी डी. लिट की थीसिस-अंगिका का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन में बनाकर भागलपुर विश्वविद्यालय को दिया था. भागलपुर में आकाशवाणी केंद्र भी डॉ. पांडेय की देन है. पांडेय ने भागलपुर विश्वविद्यालय में अंगिका की पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए 1963, 1969 और 1970 में पहल की थी. यही वजह है कि लोग उन्हें अंगिका का जनक कहते हैं.

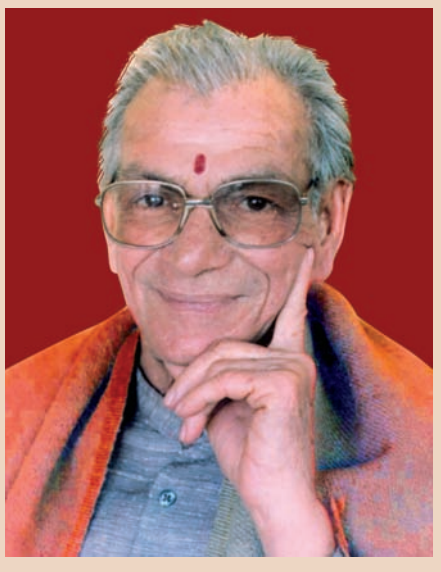

सम्राट मायाराम के वंशज सम्राट सूर्यमौलि के सुपुत्र राजा दामोदर पांडेय एवं महारानी मैना देवी के पौत्र और क्रांतिकारी महर्षि चुनचुन पांडेय एवं सीता देवी के पुत्र होने के कारण उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अंग्रेज सरकार विरोधी थी. परिणामस्वरूप डॉ. पांडेय भी अपने अग्रज प्राचार्य सच्चिदानंद की तरह फरार होकर 1942 के ब्रिटिश सरकार विरोधी आंदोलन में कूद पड़े. इसलिए चाहकर भी वह उस समय अंगिका के प्रचार को परवान नहीं चढ़ा पाए. बाद में इस कमी को उन्होंने अपनी कृति पछिया बयार से पूरा किया. पछिया बयार की भाषा से भ्रम का पर्दा हटना शुरू होने लगा और धीरे-धीरे अंग अंचल के लोगों में भी अपनी भाषा के प्रति अभिमान जगने लगा. यूं तो उन्होंने 14 जनवरी, 1940 को ही अंगिका में चानन नामक एक हस्तलिखित पत्रिका निकाल कर लोगों को चौंका दिया था. अंगिका भाषा में उनकी कविताएं आरंग नामक पत्रिका के अप्रैल एवं अगस्त 1945 के अंकों में निहोरा एवं गांधी जी के ऐलै जमाना शीर्षक से प्रकाशित हुईं. देशप्रेम सर्वोपरि था, इसलिए बहुत से भाषा संबंधी कार्य बीच-बीच में बाधित भी होते रहे.

डॉ. पांडेय के दिल में अंगिका का ऐसा जुनून समाया कि उन्होंने आजादी के बाद कहलगांव के सुकुमारी पहाड़ के पहड़ बंगले पर, जहां वह संन्यासी के रूप में रहते थे, ब्रजभाषा की तर्ज पर अंग बोली को अंगभाषा नाम देकर केंद्रीय अंगभाषा परिषद के गठन का ऐलान किया, जिसकी नींव उन्होंने अंग बोली प्रचारिणी सभा के रूप में 5 जनवरी, 1945 को ही रख दी थी. डॉ. पांडेय ने केंद्रीय अंगभाषा परिषद की विधिवत स्थापना 1953-54 में की. 15 अगस्त, 1947 को कहलगांव की शारदा पाठशाला में एक कार्यक्रम का आयोजन करके उन्होंने जयप्रकाश नारायण को एक खूबसूरत थैली में ग्यारह सौ रुपये भेंट किए. आजादी के बाद किसी को थैली प्रदान करने का यह पहला उदाहरण था.यदि डॉ. पांडेय ने अंगिका आंदोलन न चलाया होता तो बिहार बहुत पहले ही बंट गया होता. वर्तमान में बिहार और झारखंड के लगभग अट्ठारह-बीस जिलों यानी समस्त अंग अंचल के चार-पांच करोड़ लोगों की भाषा अंगिका है. आज जो भी लोग अंगिका में लिख-बोल रहे हैं, उसका रास्ता डॉ. पांडेय का बनाया हुआ है. इसी कारण उन्हें सदी का सर्वश्रेष्ठ भाषा वैज्ञानिक कहा जाता है.

डॉ. सुनीता सुवर्णा
feedback@chauthiduniya.com

यह फोन देखने में बेहद सुंदर होगा. इंटरनेट कनेक्टिविटी इस फोन की विशेष ख़ूबी है.

बजाज की नई डिस्कवर और बॉक्सर

बॉक्सर का नया मॉडल 150 सीसी इंजन क्षमता का होगा. कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि इसकी क़ीमत तक़रीबन 45,000 रुपये के आसपास हो सकती है. कंपनी इसे यूटीलिटी श्रेणी में लांच करना चाहती है, जिसमें इंजन क्षमता प्रतिस्पर्धी कंपनियों के मुक़ाबले बेहतर हो और क़ीमत तक़रीबन उनके बराबर.

देश की दूसरी सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो लिमिटेड जल्द ही डिस्कवर का नया मॉडल बाज़ार में पेश करने जा रही है. इसके अलावा कंपनी अपने बंद हो चुके मॉडल बॉक्सर को फिर से बाज़ार में लांच करने की तैयारी में है. उसने 2004 में बॉक्सर का उत्पादन बंद कर दिया था. उम्मीद है कि अप्रैल 2011 में डिस्कवर और जून-जुलाई तक बॉक्सर का नया मॉडल बाज़ार में लांच किया जाएगा. बॉक्सर का

नया मॉडल 150 सीसी इंजन क्षमता का होगा. कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि इसकी क़ीमत तक़रीबन 45,000 रुपये के आसपास हो सकती है. कंपनी इसे यूटीलिटी श्रेणी में लांच करना चाहती है, जिसमें इंजन क्षमता प्रतिस्पर्धी कंपनियों के मुक़ाबले बेहतर हो और क़ीमत तक़रीबन उनके बराबर. ऐसे में उम्मीद है कि लांच होने के बाद बॉक्सर कंपनी के लिए तीसरा प्रमुख ब्रांड बन सकती है. कंपनी अभी स्पोर्ट्स श्रेणी में पल्सर और कम्यूटर श्रेणी में डिस्कवर को बेच रही है. उक्त अधिकारी ने बताया कि कंपनी को उम्मीद है कि अप्रैल में डिस्कवर के लांच होने के बाद वह हर महीने तक़रीबन 3.5 लाख मोटरसाइकिलें बेचने लगेगी. कंपनी ने फरवरी 2011 में 2,86,657 दोपहिया वाहन बेचे हैं, जिसमें पल्सर और डिस्कवर ब्रांड की हिस्सेदारी 67 फ़ीसदी है. बजाज ऑटो के दोपहिया वाहनों की बिक्री पिछले साल के मुक़ाबले 22 फ़ीसदी बढ़ी है.

फोटो- सुनील मल्होत्रा

गैस्ट्रोइंटेराइटिस से बचाव के लिए तैयार किया रोटावायरस वैक्सीन भारत में लांच हुआ.

नोकिया के नए फोन

यह मॉडल नोकिया के एन-900 का उत्तराधिकारी होगा और कंपनी इसके लिए मीगो और सिंबियन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगी.

ब्लैक बेरी और एप्पल को टक्कर देने के उद्देश्य से प्रमुख मोबाइल फोन कंपनी नोकिया कई नए हैंडसेट ला रही है, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद जल्द ही बाज़ार में उतरेगा. कंपनी को उम्मीद है कि वह इससे काफी कुछ हासिल कर सकेगी. नोकिया द्वारा माइक्रोसॉफ्ट से समझौते के बाद यह माना जा रहा था कि फिनलैंड की यह कंपनी अब नए फोन अपनी टेक्नोलॉजी के बूते नहीं ला सकेगी, लेकिन नोकिया अपना नया फोन एन-950 बाज़ार में उतारने की तैयारी में है. यह मॉडल नोकिया के एन-900 का उत्तराधिकारी होगा और कंपनी इसके लिए मीगो और सिंबियन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगी. नोकिया के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रिच ग्रीन ने कहा कि कंपनी एन-950 पर ज़ोर-शोर से काम कर रही है. इसके लिए वह कुछ नए तरह के हार्डवेयर तैयार कर रही है. यह फोन देखने में बेहद सुंदर होगा. इंटरनेट कनेक्टिविटी इस फोन की विशेष ख़ूबी है. नोकिया द्वारा पिछले काफ़ी दिनों से कोई नया फोन बाज़ार में न उतारने से लोगों में काफी बेचैनी थी, लेकिन इस ख़बर के बाद बाज़ार में काफ़ी सुगबुगाहट है. मालूम हो कि नोकिया ने अपना पिछला फोन एन-9 रद्द करके बाज़ार में अपनी हालत ख़राब कर ली थी.

देशी बाज़ार में लग्जरी कार

इटली की लग्जरी स्पोर्ट्स कार फेरारी बहुत जल्द आधिकारिक तौर पर भारतीय बाज़ार में दस्तक दे देगी. इसकी शुरुआत कैलिफोनया, 458 इटैलिया, 599 जीटीबी फियोरानो एवं नवीनतम एफएफ जैसे मॉडलों से होगी, लेकिन इन वाहनों को भारतीय सड़कों पर दौड़ाने के ख्वाहिशमंदों को कम से कम 2.2 करोड़ रुपये ढीले करने पड़ सकते हैं. भारतीय बाज़ार में फेरारी की कोई गाड़ी इससे कम क़ीमत की नहीं होगी. हाल में कंपनी ने श्रेयांस ग्रुप को भारतीय बाज़ार में फेरारी का अधिकृत इंपोर्टर घोषित किया है. भारत में फेरारी द्वारा बेचे जाने वाले कैलिफोनया मॉडल की क़ीमत 2.2 करोड़ होगी. वहीं इटैलिया की क़ीमत 3.56 करोड़ रखी गई है. फेरारी 599 जीटीबी फियोरानो के शौकीनों को 3.37 करोड़ रुपये चुकाने होंगे. कंपनी के मुताबिक़ भारतीय बाज़ार में उसके द्वारा लांच किए जाने वाले वाहनों में एफएफ का नाम भी शामिल है. भारत में कंपनी की डीलरशिप शाखाएं खुल जाने के बाद इन वाहनों की बुकिंग शुरू हो जाएगी. इसकी पहली डीलरशिप शाखा जल्द ही दिल्ली में शुरू होगी. वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान मुंबई में फेरारी की अधिकृत डीलरशिप शाखा खोलने का इरादा है. श्रेयांस ग्रुप भारतीय बाज़ार में लग्जरी गुड्स रिटेलिंग के कारोबार में पहले से ही स्थापित है. यह ग्रुप वाच, सुपर बाइक, ज्वैलरी एवं फैशन से जुड़ी अन्य वस्तुओं का कारोबार कर रहा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

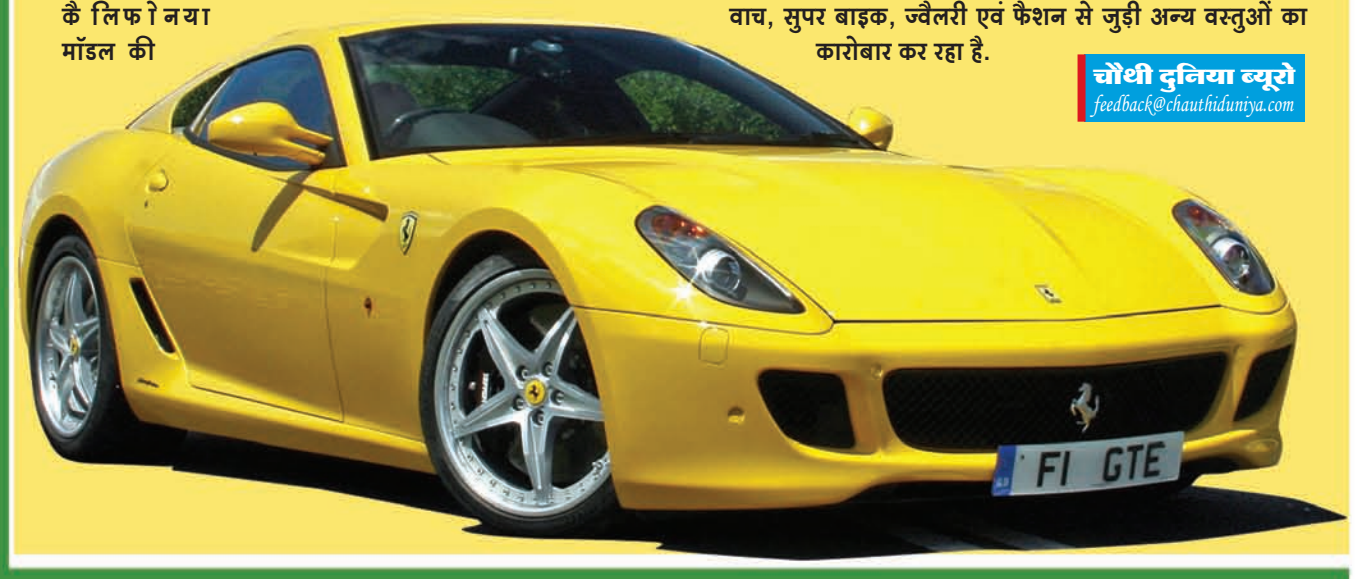

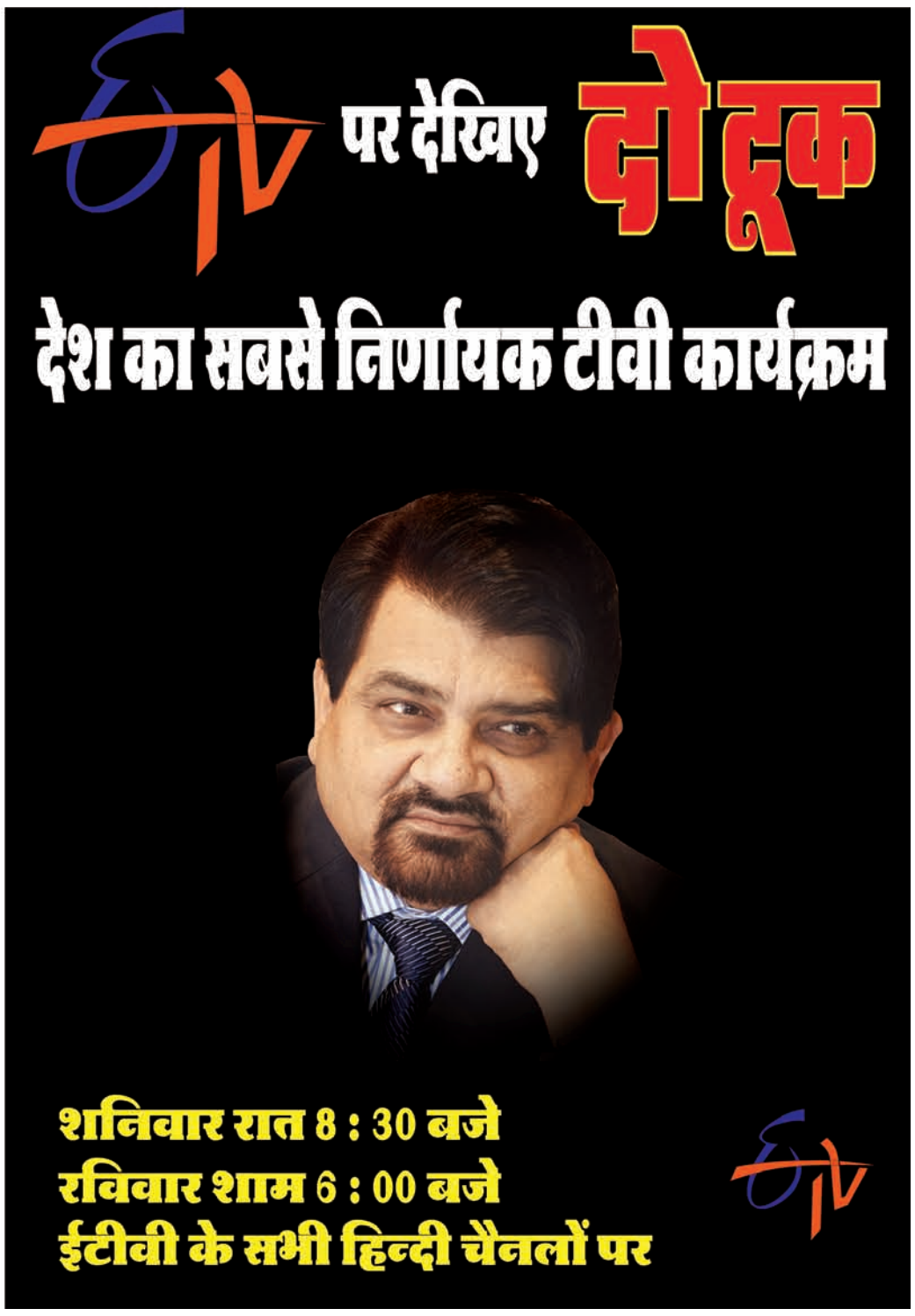

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

खेल प्रेमियों के लिए वह दिन मातम का होगा, जब सचिन क्रिकेट को अलविदा कहेंगे. विश्वकप 2011 सचिन का आखिरी विश्वकप होगा.

ICC Cricket World Cup 2011

जिनके लिए यह आख़िरी मौक़ा है

राजेश एस कुमार

भारत में क्रिकेट अगर धर्म है तो विश्वकप भी महाकुंभ के आयोजन से कम नहीं होता. यह बात सिर्फ़ भारत में ही नहीं, दुनिया के लगभग हर देश पर लागू होती है. यही वजह है कि हर चार साल बाद जब विश्वकप का आयोजन होता है तो उसकी मेजबानी को लेकर देशों में और टीम में जगह पक्की करने के लिए खिलाड़ियों में उत्साह देखते ही बनता है. कुछ खिलाड़ियों की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि उन्हें न सिर्फ विश्वकप में खेलने का मौका मिलता है, बल्कि वे विश्वकप विजेता टीम का हिस्सा भी बनते हैं. वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड जैसी टीम भी है, जो आज तक विश्वकप ट्राफी से वंचित है. इन सबके बीच एक चीज जो आम है, वह यह कि हर खिलाड़ी का सपना होता है कि उसे अपने पूरे करियर के दौरान कम से कम एक बार विश्वकप में खेलने का मौका अवश्य मिले. लेकिन इस अंक में हम उन खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, जिनके लिए विश्वकप 2011 उनका आखिरी विश्वकप होगा. उन पर दोहरा दबाव है, विश्वकप जीतने का और अपने आखिरी मौके को अच्छी तरह भुनाने का, क्योंकि पता नहीं, इसके बाद हो सकता है कि उनका करियर रिकॉर्ड यहीं पर थम जाए.

शुरुआत मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से ही करते हैं. खेल प्रेमियों के लिए वह दिन मातम का होगा, जब सचिन क्रिकेट को अलविदा कहेंगे. विश्वकप 2011 सचिन का आखिरी विश्वकप होगा. इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि सचिन की मौजूदगी में भारत ने अभी तक कोई विश्वकप नहीं जीता है. हालांकि इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है कि सचिन अपने समय के हर तरह से सबसे पूर्ण क्रिकेटर हैं और क्रिकेट इतिहास के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. सचिन निस्संदेह दुनिया के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर हैं. बल्लेबाज़ी का शायद ही कोई ऐसा रिकॉर्ड हो, जो उनकी क्षमता से बाहर हो. धैर्य, संयम, आक्रमण, सही गेंद का चुनाव, गेंद का प्लेसमेंट, गैप निकालना और सबसे बढ़कर क्रिकेट के प्रति समर्पण उन्हें एक बेमिसाल खिलाड़ी बनाता है. उनका लंबा अनुभव और किसी भी परिस्थिति से निपटने का हौसला भारत के लिए एक वरदान है. उनके पास वनडे और टेस्ट, दोनों में सबसे ज़्यादा शतक हैं, सबसे ज़्यादा रन हैं. दुनिया का कोई भी गेंदबाज़ उनका विकेट लेने की ख्वाहिश रखता है. दो विश्वकपों में वह सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. वर्ष 2000 में वह पहले ऐसे खिलाड़ी बने, जिसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50 शतक लगाए हों और इस विश्वकप में उनसे यह उम्मीद की जा रही है कि वह अपना 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक लगाएंगे. तेंदुलकर आईपीएल में मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं, लेकिन उन्होंने भारत की ओर से टी–20 न खेलने का फ़ैसला किया है. जब तक सचिन खेल रहे हैं, तब तक आप किसी भी करिश्मे की उम्मीद कर सकते हैं. उसके बाद क्या होगा, कोई नहीं जानता.

सचिन के अलावा भारत की ओर से आशीष नेहरा भी ऐसे खिलाड़ी होंगे, जिनका यह आखिरी विश्वकप है. गौरतलब है कि आशीष नेहरा ने अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में 2000–01 में क़दम रखा था और उसके साथ यह भी बता दिया कि उनमें बाएं हाथ के क्लासिक तेज़ गेंदबाज़ की सारी विशेषताएं मौजूद हैं. नेहरा ने 1999 में अपना पहला टेस्ट खेला था. नेहरा को उनकी चोट ने काफ़ी परेशान किया और जब वह अपने चरम पर थे, तभी परेशानियों ने आ घेरा और फिर गति एवं दिशा पर उनका नियंत्रण जाता रहा. नेहरा ने ज़िम्बॉब्वे के ख़िलाफ़ ही अपनी पहली पूरी सीरीज़ खेली थी और 2005 में उन्हें ज़िम्बॉब्वे के दौरे को बीच में ही छोड़ना पड़ा था. टेस्ट में उन्हें दोबारा तो नहीं बुलाया जा सका, लेकिन आईपीएल के दूसरे संस्करण में अच्छा प्रदर्शन करने के नतीजे में उन्हें वेस्टइंडीज़ के विरुद्ध 2009 में वनडे टीम में वापस बुलाया गया. नेहरा ने पाकिस्तान और इंग्लैंड के विरुद्ध ख़ास तौर से अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्होंने वनडे में इंग्लैंड के विरुद्ध अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया, जब उन्होंने 23 रन देकर छह विकेट झटके. कुल मिलाकर इस विश्वकप के बाद आशीष नेहरा को क्रिकेट की और क्रिकेट प्रेमियों को नेहरा की कमी जरूर खलेगी.

अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की, जिसने अभी से ही अपने संन्यास की घोषणा कर दी है. कभी अपने प्रदर्शन तो कभी विवादों से लोगों को अक्सर चौंकाने वाले पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का यह आखिरी मौका है. अधिकतर समय विवादों से घिरे रहने वाले और रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब की सनसनाती गेंदों से बल्लेबाजों के होश फाख्ता हो जाते थे. ब्रायन लारा ने जब पहली बार शोएब की सनसनाती गेंदों का सामना किया था तो वह काफी असहज नजर आए थे. शोएब के नाम सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड 100.2 मील (161.3 किमी) प्रति घंटा है, जो उन्होंने 2003 के विश्वकप में इंग्लैंड के विरुद्ध दर्ज कराया था. इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी की तेज रफ्तार और आक्रामकता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी निकली. चोट और अपने गुस्सैल व्यवहार की वजह से अत्यंत प्रतिभाशाली होते हुए भी उन्हें टीम में कभी स्थायी जगह मिली ही नहीं. जानकार आज भी मानते हैं कि अगर थोड़ा सा धैर्य और अनुशासन शोएब में होता तो इस खिलाड़ी को महानतम बनने से कोई नहीं रोक सकता था. 2006 में शोएब को डोपिंग का दोषी पाया गया था. वर्ष 2007 में मोहम्मद आसिफ से मारपीट के कारण उन पर 13 वनडे मैचों की पाबंदी लगाई गई थी. 2008 में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की आलोचना करने पर उन पर 18 महीने का प्रतिबंध और 70 लाख रुपये का जुर्माना हुआ था. अब शोएब का शबाब उतार पर है और उनकी गेंदों में वह तेजी भी नहीं रही, जिससे दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज भी खौफ खाते थे. फिर भी उनकी अपनी शैली की वजह से रावलपिंडी एक्सप्रेस को हमेशा याद रखा जाएगा. मालूम हो कि शोएब अख्तर ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत वर्ष 1997 में की थी और उन्होंने 46 टेस्ट मैचों में 178 विकेट लिए. उन्होंने अपना आख़िरी टेस्ट मैच वर्ष 2007 में भारत के ख़िलाफ़ बंगलुरू में खेला था. अभी तक शोएब 163 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं और उन्होंने 247 विकेट भी लिए.

शोएब की छवि के ठीक विपरीत जैक्स कालिस भी उन खिलाड़ियों में से हैं, जो आखिरी बार विश्वकप में हिस्सा ले रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका टीम के सर्वश्रेष्ठ हरफनमौला खिलाड़ी जैक्स कालिस टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शुमार हैं. कालिस बल्लेबाजी में अपनी क्लास के लिए जाने जाते हैं. जबरदस्त बल्लेबाज होने के साथ–साथ वह मध्यम–तेज गेंदबाजी भी करते हैं. 1995–96 में इंग्लैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का सफर शुरू किया. कालिस की ख़ासियत है कि वह क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं. 1998 से 2002 के बीच कालिस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हरफनमौला खिलाड़ी के तौर पर उभरे. 1998 में चैंपियंस ट्राफी में दक्षिण अफ्रीका को खिताब दिलाने में उनकी अहम भूमिका थी. कालिस इस टूर्नामेंट में दो बार मैन ऑफ द मैच, जबकि पूरी सीरीज के लिए मैन ऑफ द सीरीज भी चुने गए. टेस्ट इतिहास के कालिस मात्र चौथे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने लगातार पांच मैचों में शतक जड़ा हो. चोटों से जूझने के बाद भी इस खिलाड़ी ने जीवट खेल दिखाया है. 2011 में भारत के ख़िलाफ़ निर्णायक टेस्ट मैच में कमर में बहुत दर्द के बाद भी कालिस मैदान पर डटे रहे और शतक जड़कर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को हार से बचाया. इसके अलावा वह 2005 में आईसीसी द्वारा प्लेयर आफ द ईयर चुने जा चुके हैं. उनके शानदार करियर ग्राफ में एक नगीना लगना अभी बाकी है. क्रिकेट जगत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाधि यानी आईसीसी क्रिकेट विश्वकप को जीतना.

वैसे तो कई बड़े खिलाड़ी हैं, जो अगले विश्वकप में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन शायद सभी के नाम उतने यादगार नहीं रहेंगे, जितना आस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग का रहेगा. जानकार आज भी मानते हैं कि सचिन का रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ सकता है तो वह पोंटिंग ही हैं. आस्ट्रेलिया की कई सालों तक कप्तानी करने वाले रिकी पोंटिंग ने एलन बोर्डर का रिकार्ड तोड़कर आस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट मैचों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. वह अब टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले शीर्ष तीन बल्लेबाजों में शामिल हैं. पोंटिंग के नाम अब 134 टेस्ट मैचों की 225 पारियों में 11,188 रन दर्ज हैं, जिसमें 38 शतक और 46 अर्धशतक शामिल हैं. टेस्ट क्रिकेट में पोंटिंग से अधिक रन भारत के सचिन तेंदुलकर और वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा ने बनाए हैं. अगर सब कुछ ठीक रहा तो कोई आश्चर्य नहीं कि रिकी जाते–जाते कोई नया करिश्मा कर जाएं. हालांकि उनके लिए आखिरी विश्वकप का मलाल इसलिए नहीं होगा, क्योंकि वह इससे पहले अपनी टीम को विश्वकप जिता चुके हैं. फिर भी आस्ट्रेलियाई टीम के लिए उनके जैसे कप्तान और खिलाड़ी की जगह भरना आसान नहीं होगा.

अब जब उम्र के इस पड़ाव पर आकर इन खिलाड़ियों के सामने क्रिकेट को अलविदा कहने का मौका करीब आ गया है तो फिर इन्हें जाते–जाते क्रिकेट और क्रिकेट प्रेमियों को ऐसा तोहफा जरूर देना होगा, जिससे इनकी विदाई शानदार मानी जाए.

rajeshsy@chauthiduniya.com

आशीष नेहरा

मुथैया मुरलीधरन

जैक कालिस

शोएब अख्तर

Now, mixing business with pleasure makes perfect business sense.

FORTUNE Inn Grazia BY WELCOMGROUP Noida

Welcome to Fortune Inn Grazia, Noida - an elegant, upscale, full-service business hotel. It is strategically located in the heart of the city and in close proximity to Sector 18, the commercial and shopping hub of Noida. The hotel offers everything from contemporary accommodation and exciting dining options to, of course, comprehensive facilities for business and leisure. All to meet the growing needs of the new-age business traveller.

Block-I, Plot No. 1A, Sector-27, Noida - 201301, Uttar Pradesh, India. Tel: 0120-3988444, Fax: 0120-3380144, E-mail: grazia@fortunehotels.in, Website: www.fortunehotels.in

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 28 मार्च-03 अप्रैल 2011

कंगना ने कहा कि आप लोग इस बात का दूसरा मतलब न निकालें कि मैंने अपने आपको मधुबाला बताया. बस मेरी दिली इच्छा है कि मैं मधुबाला की तरह अनारकली बनकर अमर होना चाहती हूं.

कमेंटेटर मंदिरा

मंदिरा बेदी क्रिकेट से जुड़े शो की लोकप्रिय होस्ट हैं. शुरुआत में भले ही वह ग्लैमर की वजह से चर्चा में रहीं, लेकिन आज उन्हें क्रिकेट का एक्सपर्ट माना जाता है. उनकी ही तर्ज़ पर इंडस्ट्री की महिलाएं अब क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो करने लगी हैं. ख़ासतौर पर आईपीएल और क्रिकेट वर्ल्डकप के दौरान तो क्रिकेट महिलाओं के सिर चढ़कर बोलने लगा है. मंदिरा कहती हैं कि नए जमाने की लड़कियां इस मामले में लड़कों से पीछे नहीं रहना चाहतीं, हालांकि इसमें पुरुषों की बराबरी वाली कोई बात नहीं है. अगर महिलाओं को पुरुषों की बराबरी ही करनी होती तो आज हमारे देश की महिला क्रिकेट टीम भी पुरुषों जितनी ही लोकप्रिय होती. क्या सोचकर टीवी पर क्रिकेट शोज में हिस्सा लेना शुरू किया था मंदिरा ने? वह बताती हैं कि जब मुझे यह ऑफर मिला तो मैंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया. हालांकि शुरुआत में यह सब बेहद मुश्किल था. मेरे साथ सारे क्रिकेट विशेषज्ञ पुरुष होते थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और आज क्रिकेट पर मेरी काफ़ी कमांड है. क्रिकेट की दुनिया में कुछ भी होने पर मेरे घर पर चैनलों की ओबी वैन की लाइन लग जाती हैं. अभी भी मैं एक टॉप इंग्लिश न्यूज़ चैनल पर क्रिकेट शो प्रजेंट कर रही हूं. क्या उन्हें नहीं लगता कि क्रिकेट शोज में महिलाओं को सिर्फ़ ग्लैमर के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इस पर वह कहती हैं कि जब मुझे 2003 में पहली बार साउथ अफ्रीका में आयोजित वर्ल्डकप के दौरान क्रिकेट शो में हिस्सा लेने का अवसर मिला था तो चैनल ने मेरे जाने-पहचाने चेहरे की वजह से ऐसा किया था. आम तौर पर मैच के पहले या बाद के शो में काफ़ी सीरियस डिस्कशन होते हैं, लेकिन मैं वहां आम लोगों के सवाल पूछती थी. मुझे कभी किसी ने सवाल बनाकर नहीं दिए. मैंने हमेशा अपनी मर्जी के सवाल पूछे, जो आम लोगों ने भी पसंद किए. ऐसे में ग्लैमर की बात ही नहीं आती. मंदिरा एड फिल्म मेकिंग में जाना चाहती थीं, पर भाग्य ने उन्हें अभिनेत्री बना दिया. अभिनय के सफ़र की शुरुआत तो टेलीविज़न सीरियल शांति से हुई, पर फिर मिली फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो छोटे परदे की मंदिरा बड़े परदे की सह नायिका बन गईं. उसके बाद क्रिकेट कमेंटेटर बनकर उन्होंने एक नया इतिहास रच डाला. पिछले दिनों अमेरिका के शहर न्यूजर्सी में मंदिरा बेदी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस परेड में ग्रैंड मार्शल के लिए भी आमंत्रित किया गया था.

कंगना का सपना

बहुत कम फिल्मों में काम करने के बावजूद लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली अभिनेत्री कंगना रानावत का जादू आज सबके सिर चढ़कर बोल रहा है. हाल में आई उनकी फिल्म तनु वेड्स मनु में भी लोगों को उनका रूप भा रहा है, लेकिन ख़ुद कंगना को अभी भी उस रोल का इंतज़ार है, जो दर्शकों की तरह उनके दिल में उतर जाए. पिछले दिनों कंगना ने अपने दिल के कई राज़ खोले. उन्होंने कहा कि वह हिंदी सिनेमा की माइल स्टोन मुग़ल-ए-आजम जैसी कोई यादगार फिल्म करना चाहती हैं, ताकि उनके जाने के बाद लोग उन्हें मधुबाला की तरह याद रखें. हालांकि उन्होंने ख़ुद की तुलना मधुबाला से न करने की बात कही. कंगना ने कहा कि आप लोग इस बात का दूसरा मतलब न निकालें कि मैंने अपने आपको मधुबाला बताया. बस मेरी दिली इच्छा है कि मैं मधुबाला की तरह अनारकली बनकर अमर होना चाहती हूं. हाल में आई वंस अपॉन टाइम इन मुंबई और तनु वेड्स मनु आदि फिल्मों में उनके काम और सुंदरता की काफ़ी तारीफ़ हो रही है. इससे पहले भी कंगना ने गैंगस्टर, वो लम्हे और फैशन में अपनी छाप छोड़ी थी. दर्शकों ने उन्हें कूल कैरेक्टर की जगह हाइपर रोल्स में ज़्यादा अपनाया है. हालांकि तनु वेड्स मनु में वह लोगों को पसंद आईं, पर उतनी नहीं, जितनी दूसरी फिल्मों में स्क्रिप्ट अच्छी होने की वजह से उन्हें अपने आप दर्शकों के दिलों में जगह मिल गई. वह कहती हैं, मैं भी कब तक एक ही तरह के किरदार निभाऊंगी. मेरे पास रोज़ाना ऐसे रोल्स के ऑफर आते हैं, लेकिन मैं इनसे ऊब चुकी हूं. यह सोचकर डिप्रेशन होता है कि मुझे किसी और तरह के रोल क्यों ऑफर नहीं किए जाते. आख़िर मेरे पास भी अलग तरह के रोल निभाने लायक़ टैलंट है. लेकिन उस तरह के रोल्स अक्सर उन्हीं हीरोइनों को दिए जाते हैं, जिनके ब्वॉयफ्रेंड्स हैं या जिनके पास सही कॉन्टैक्ट्स हैं. वैसे यह मेरी प्रॉब्लम है कि मैं आसानी से दोस्त नहीं बना पाती. मैं अकेली थी और मुझे रिकमेंड करने वाला कोई नहीं था.

चर्चा है कि आप बड़े अभिनेताओं के नाम का इस्तेमाल अपनी ब्रैंड वैल्यू बढ़ाने के लिए करती हैं? जैसे सवाल पर कंगना कहती हैं कि इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने अपने दम पर कई अवॉर्ड्स जीते हैं. तक़रीबन 20 अवॉर्ड्स मेरे घर पर रखे हैं और इन्हें मैंने किसी का नाम यूज किए बिना जीता. अब आप बताएं कि मैं अचानक किसी के नाम का सहारा क्यों लेने लगूंगी? और वह भी उस वक़्त, जब मैं अपने लिए सही ट्रैक ढूंढ चुकी हूं. मुझे ऐसे कई लोगों के बारे में पता है, जो सामने आने पर बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं. आने वाली फिल्म रास्कल्स में कंगना फ्लर्टी गर्ल का रोल प्ले कर रही हैं और धमाल-2 में वह संजय दत्त की सेक्रेटरी के रोल में.

कैलेंडर में कश्मीरा

बॉलीवुड की बालाएं दिनोंदिन कुछ ज़्यादा ही बोल्ड होती जा रही हैं. पहले बिपाशा बसु, फिर मंदिरा बेदी और अब कश्मीरा शाह टॉपलेस हो गईं. यस बॉस, पप्पू पास हो गया, जंगल और सिटी ऑफ गोल्ड जैसी फिल्मों से लोगों के बीच जगह बनाने वाली कश्मीरा बॉलीवुड में बी ग्रेड अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती हैं. वह कुछ फिल्मों में छोटे-मोटे रोल या आइटम डांस करने के बाद रियलिटी शो के ज़रिए लोकप्रियता हासिल करना चाहती थीं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका. उनके आइटम डांस से भी लोग एक समय के बाद ऊब गए. सो सनसनी फैलाने के लिए उन्होंने एक कैलेंडर के लिए फोटो शूट कराया है. कैश्सेंसुअल नामक इस कैलेंडर को थर्ड रॉक इंटरटेनमेंट कंपनी ने प्रोड्यूस किया है. इसमें उन्होंने अपने जिस्म का जमकर जलवा दिखाया है. अपने इस टॉपलेस कैलेंडर फोटो शूट को लेकर कश्मीरा ख़ासी उत्साहित हैं. उनका कहना है कि मेरे फोटो देखकर लोग चौंक जाएंगे. मैं हमेशा कुछ हटकर काम करने में विश्वास करती हूं. कश्मीरा कहती हैं कि उनके फोटो इस क़द्र हॉट आए हैं कि पुरुष इस कैलेंडर को अपने बाथरूम में ज़रूर लगाना चाहेंगे, लेकिन कश्मीरा द्वारा लोकप्रिय होने का यह स्टंट उनके लिव इन ब्वॉयफ्रेंड कृष्णा को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिन्हें बहुत रो-गाकर कश्मीरा ने वेलेंटाइन डे पर मनाया था. कैलेंडर के लांच पर पहुंची कश्मीरा ने बेयर बैक ड्रेस पहन रखी थी. वहां मौजूद लोगों ने पाया कि कश्मीरा की असल बॉडी और कैलेंडर में दिखाई गई उनकी बॉडी में काफ़ी अंतर है. यानी कश्मीरा वैसी स्लम सेक्सी फिगर वाली नहीं हैं. भला हो कंप्यूटर के ड्राइंग सॉफ्टवेयर का, जिससे ख़राब शेप की बॉडी भी आसानी से सही बनाई जा सकती है. बहरहाल जो भी हो, यह देखना दिलचस्प होगा कि इस सनसनी फैलाने वाले स्टंट से कश्मीरा इंडस्ट्री में ख़ुद के लिए कितनी जगह बना पाती हैं.

समीरा की धमाकेदार वापसी

फिल्म रेड एलर्ट को सफलता न मिल पाने के बाद समीरा रेड्डी क्षेत्रीय फिल्मों में व्यस्त हो गई थीं, लेकिन अब वह जल्द ही प्रियदर्शन की फिल्म तेज और शाहरुख़ ख़ान की फिल्म डॉन-2 से बॉलीवुड में धमाकेदार अंदाज़ में वापसी कर रही हैं. समीरा कहती हैं कि इन दोनों ही फिल्मों में मेरा अहम रोल है, लेकिन इन्हें दर्शक मेरी फिल्में नहीं कह सकते. अगर आप जब किसी मेगा बजट और मल्टी स्टारर फिल्म का हिस्सा बनते हैं तो उसकी कामयाबी का कुछ असर आपके करियर पर भी पड़ता है. ऐसे में उम्मीद है कि इन फिल्मों में मेरे प्रशंसक मुझे ज़रूर नोटिस करेंगे. हालांकि इन फिल्मों में भी लीड रोल के बजाय छोटे किरदारों में सिमट गई हैं समीरा. इस पर वह कहती हैं कि आजकल बॉलीवुड में मल्टी स्टारर फिल्में ही ज़्यादा बन रही हैं. इन फिल्मों में एक हीरो के साथ 3-4 हीरोइनें नज़र आती हैं. वह भी अब इस तरह की फिल्मों का हिस्सा बन गई हैं. फ़िलहाल वह प्रियदर्शन की फिल्म तेज के अलावा साउथ की दो फिल्मों में भी व्यस्त हैं.

समीरा ने इंडस्ट्री में ख़ुद को स्थापित करने के लिए आर्ट और कमर्शियल दोनों तरह की फिल्मों में काम किया और इसमें उन्हें कोई फ़र्क़ महसूस नहीं हुआ. वह मानती हैं कि कोई भी फिल्म अच्छी या बुरी हो सकती है. कई बेहतरीन निर्देशकों की अच्छी फिल्में बनकर सिर्फ़ इसलिए रिलीज़ नहीं हो पातीं, क्योंकि उनके साथ आर्ट फिल्म का टैग लग जाता है. हालांकि अगर फिल्म अच्छी हो तो वह ज़रूर चलती है. सच्चाई यह है कि दर्शकों को आर्ट या कमर्शियल से कुछ लेना-देना नहीं होता. निजी तौर पर समीरा अब्बास-मस्तान और नागेश कूकनूर की फिल्मों में कोई फ़र्क़ महसूस नहीं करतीं. उनका मानना है कि ऑफ बीट फिल्म करके हर उस एक्टर को सुकून मिलता है जो अच्छा काम करना चाहता है. इन दिनों समीरा बॉलीवुड से ज़्यादा साउथ में व्यस्त हैं. कहीं इसकी वजह बॉलीवुड में काम की कमी तो नहीं? इस सवाल पर वह कहती हैं कि बॉलीवुड से ज़्यादा पावरफुल रोल और अच्छी प्राइस साउथ में मिल रही है, इसलिए मैंने वहीं फोकस किया. वैसे मैंने साउथ के अलावा बांग्ला फिल्में भी की हैं. समीरा रेड्डी को लोग हॉट इमेज के लिए जानते हैं, लेकिन आजकल वह सिंपल लुक में नज़र आने लगी हैं, क्यों? इस सवाल के जवाब में समीरा कहती हैं कि किसी भी कलाकार को अपने रोल की मांग के मुताबिक़ काम करना होता है. मुझे भी जिस तरह के रोल मिलते हैं, उन्हें ही करती हूं. इसमें पसंद-नापसंद का सवाल नहीं उठता. वह कहती हैं कि मेरी अगली फिल्मों को देखने के बाद प्रशंसकों को यह शिकायत नहीं रहेगी. वैसे मैं अपनी सेक्सी इमेज से ख़ुश हूं और इसे एंजॉय करती हूं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

समीरा ने इंडस्ट्री में ख़ुद को स्थापित करने के लिए आर्ट और कमर्शियल दोनों तरह की फिल्मों में काम किया और इसमें उन्हें कोई फ़र्क़ महसूस नहीं हुआ. वह मानती हैं कि कोई भी फिल्म अच्छी या बुरी हो सकती है. कई बेहतरीन निर्देशकों की अच्छी फिल्में बनकर सिर्फ़ इसलिए रिलीज़ नहीं हो पातीं, क्योंकि उनके साथ आर्ट फिल्म का टैग लग जाता है.

प्रीव्यू

फ़ालतू

फिल्म फ़ालतू आज की युवा पीढ़ी की कहानी है. इस फिल्म में युवा कोई अलग रास्ता नहीं चुनते, बल्कि अलग रास्ता बना लेते हैं. फ़ालतू ऐसे दोस्तों के समूह की कहानी है, जिन्हें बिल्कुल नकारा और बेकार जाना जाता है. इसलिए कोई उनकी क़द्र नहीं करता. फिर वे अपने टशन में रहते हैं. वे केक पर चेरी के समान हैं, जिन्हें अपने आप पर गर्व है. शायद ही कभी उन्हें काम करते पाया गया हो. युवाओं का यह समूह शहर के क्लबों में तो भीड़ बढ़ाता देखा जा सकता है, लेकिन कॉलेज और क्लास में जाना इसे पसंद नहीं है. एक दिन इन युवाओं की ज़िंदगी में भी बदलाव आता है और परिस्थितियां इन्हें ज़िंदगी की कई कड़वी सच्चाइयों से रूबरू करा देती हैं. पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी के बेटे अंगद बेदी फिल्म फ़ालतू से बॉलीवुड में अपना पहला क़दम रखने जा रहे हैं. उनके अलावा इस फिल्म में अरशद वारसी और रितेश देशमुख भी होंगे. 2003 में आई अपनी पहली फिल्म तुझे मेरी क़सम से लेकर फ़ालतू तक रितेश ने कई विविधतापूर्ण चरित्रों में रंग भरने की पूरी कोशिश की है. पहले कोरियोग्राफर रहे और अब निर्देशन में हाथ आज़मा रहे रेमो डिसूजा की वासु भगनानी निर्मित फिल्म फ़ालतू में रितेश मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में उनका किरदार प्रिंसिपल बाजीराव का है. यह प्रिंसिपल अपने छात्रों से उम्र में केवल चार-पांच साल बड़ा है और अपनी गरिमा बनाए रखने वाला शख़्स है, थोड़ा कड़क भी. फिल्म काफ़ी मनोरंजक होगी और इसमें आमिर ख़ान की तरह इडियट शब्द की तर्ज़ पर फिल्म के नाम फ़ालतू को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने का काम किया गया है. रितेश कहते हैं कि फिल्म देखने के बाद हर कोई अपने आपको फ़ालतू कहना पसंद करेगा. वर्ष 2007 में मिस इंडिया यूनिवर्स का ख़िताब जीतने वाली पूजा गुप्ता फिल्म फ़ालतू से बतौर अभिनेत्री अपना करियर शुरू कर रही हैं उन्होंने फिल्म में पूजा नाम की ही लड़की का किरदार निभाया है. वह टॉम ब्वॉय टाइप की है. तीन लड़कों के साथ पूजा बड़ी हुई है. उसके पापा चाहते हैं कि वह शादी करके अपना घर बसा ले, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहती. वह लाइफ को अपने अंदाज़ में जीना चाहती है. पूजा के अनुसार, फिल्म फ़ालतू भारत की शिक्षा व्यवस्था पर कटाक्ष करती है. वह कहती हैं, कॉलेज में अस्सी-नब्बे प्रतिशत अंक पाने वाले छात्रों को ही एडमिशन मिलता है, बाक़ी को नहीं. फिल्म में पूजा और उसके दोस्तों रितेश, नंदू एवं विष्णु को लोग फालतू कहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि वे फ़ालतू नहीं हैं. यह फिल्म आगामी एक अप्रैल को रिलीज़ होगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 28 मार्च-03 अप्रैल 2011

www.chauthiduniya.com

Acres of priceless lifestyles for the matchless few!

Swimming Pool | Gym | Spa | Club House | Play School | Modern Shopping Complex | Hospital | Auditorium

SAIL CITY

A GIFT TO RANCHI

Behind DPS / Opp. Vidhan Sabha

Club House with Garden

Grand Entrance

TOTAL 1719 UNITS

Project approved by SBI, AXIS, UCO ,LIC, HDFC, IDBI

Model Flat & Club House Ready

2/3 BEDROOM FLATS

Kashish Developers ISO : 9001 COMPANY

KASHISH DEVELOPERS LIMITED

Corporate Office : 87, Old A.G. Colony, Kadru, Ranchi - 834002, Jharkhand
Tel : 0651-2341269 - (5 Lines) Fax : 0651-2341273
Patna Office : 12A, Patliputra Colony, PATNA-13
Ph : 0612-2260220 (2 Lines), Tel Fax : 0612-2260223
E-mail : info@kashishgroup.com : www.kashishgroup.com

For Booking : 8873002015/16/17/18/19, 9470520015/16/17/18/19

नीतीश विरोधियों पर

अनुशासन का डंडा

ललन सिंह

महाबली सिंह

मोनाजिर हसन

मीना सिंह

अर्जुन रॉय

मंगनी लाल मंडल

पूर्णमासी राम

बैद्यनाथ महतो

कल तक नीतीश कुमार के बेहद क़रीबी रहे प्रेमकुमार मणि को चौथी दुनिया में उनके ख़िलाफ़ ज़बान खोलना काफ़ी भारी पड़ गया. नतीजतन उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया. उनके साथ पार्टी के कई अन्य नेताओं को भी निकाल दिया गया. देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश के विरोधी उनके इस डंडे से कैसे बचते हैं.

सरोज सिंह

जैसी आशंका थी ठीक वैसा ही हुआ. जदयू में अनुशासन का डंडा ज़ोर से चला और पार्टी के 11 सांसदों पर तलवार लटक गई. पार्टी के विधान पार्षद प्रेमकुमार मणि को निलंबित कर दिया गया. इसके अलावा पार्टी विरोधी कामों के लिए जदयू के 41 नेताओं को छह साल के लिए और 73 और अन्य नेताओं को तीन साल के लिए निलंबित कर दिया गया है. कार्रवाई यहीं नहीं रुकी, 73 अन्य नेताओं को तीन साल के लिए पद से वंचित कर दिया गया और 174 नेताओं को आगे ग़लती न करने की चेतावनी दी गई. कुछ पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व विधान पार्षदों का जांच प्रतिवेदन अभी और जांच के लिए लंबित रखा गया है. सांसदों का मामला केंद्रीय अनुशासन समिति को सौंप दिया गया है.

इतने बड़े स्तर पर अपने ही नेताओं पर कार्रवाई कर जदयू नेतृत्व ने यह साफ़ कर दिया कि पार्टी उनकी ही मर्ज़ी से चलेगी. जिन्हें रहना है रहें या फिर दूसरा विकल्प देखें. ज़ाहिर है जितना बड़ा जनादेश नीतीश कुमार को मिला है, उसने इस तरह के फ़ैसले का रास्ता साफ़ कर दिया है. इतने बड़े स्तर पर पार्टी नेताओं पर कार्रवाई कोई मामूली बात नहीं थी. जनता से मिली ताक़त के बूते ही यह संभव था और सही समय पर यह कर दिया गया, लेकिन एक कहानी बस यहीं से शुरू हो गई है. कार्रवाई के घेरे में आए नेताओं की गोलबंदी बताती है कि अभी बहुत सारा घूम धड़ाका बाक़ी है. चुनाव नतीजों के बाद जो सिलसिला बंद हो गया था, उसे इस कार्रवाई ने आगे बढ़ा दिया. सासंद उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि यह अनुशासन लाने का नहीं बल्कि कुछ लोगों को अपमानित करने की कार्रवाई है. इतने बड़े स्तर पर नेताओं को फ़रमान सुनाया गया है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पार्टी में लोकतंत्र मर गया है. उन्होंने कहा कि जनता पार्टी के साथ थी इसलिए दल के लोगों को ही चुनाव में मौक़ा मिलता तो इससे भी बेहतर परिणाम आते, लेकिन दूसरे दलों से लोगों को बुलाकर टिकट से नवाज़ा गया. यही वजह रही कि दल के समर्पित कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज़ बुलंद की और अब इन्हीं लोगों पर अनुशासन का डंडा चलाया जा रहा है. कुशवाहा मानते हैं कि यह क़दम दल के लिए आत्मघाती है. ललन सिंह ने जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह को ही अनुशासनहीन बतला दिया. उन्होंने कहा कि जब समता पार्टी का जदयू में विलय हो रहा था तब वशिष्ठ बाबू ने समता पार्टी में ही रहने का फ़ैसला किया था. ललन सिंह ने अनुशासन समिति के काम करने के तरीक़े पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मंत्री नरेंद्र सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई. उनके लड़के ने तो जेएमएम से चुनाव लड़ा था. कई और सांसद हैं जो पार्टी के अगले क़दम का इंतज़ार कर रहे हैं. अगर फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ गया तो वे खुलकर गोलबंदी शुरू कर देंगे. इसी वजह से माना जा रहा है कि केवल चार सासंदों पर ही अनुशासन की गाज गिरेगी, बाक़ी को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा. इन सांसदों में उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह, सुशील कुमार सिंह व मगनीलाल मंडल का नाम शामिल बताया जाता है. अनुशासन समिति के प्रमुख ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू इसका संकेत दे चुके हैं. उन्होंने कहा कि यह ज़रूरी नहीं कि सभी 11 सासंदों पर कार्रवाई हो. यही वजह रही कि अभी पूरे मामले को केंद्रीय अनुशासन समिति के हवाले कर दिया गया है. बहरहाल स्थिति यह है कि पंचायत चुनाव के बाद ही शह व मात का खेल ज़ोर पकड़ेगा तब तक सभी नेता अपने-अपने होमवर्क में लगे रहेंगे.

feedback@chauthiduniya.com

मणि मानसिक दिवालियापन के चरम पर हैं : उपेन्द्र चौहान

प्रेम कुमार मणि

उपेन्द्र चौहान

साहित्य के विकास के लिए कुछ नहीं किया

कमेटी से बाहर होने का ग़ुस्सा है मणि को

नैतिकता है तो इस्तीफ़ा देकर आलोचना करें

अनूपलाल व रेणू पर विशेषांक क्यों नहीं निकाला

चौथी दुनिया में प्रेम कुमार मणि का आलेख इंदिरा की राह पर चले नीतीश पढ़कर ताज्जुब हुआ. ताज्जुब इसलिए नहीं कि वह आलेख बिहार के मुख्यमंत्री के प्रति अतिशय गुस्से की परिणति था, अपितु इसलिए कि कल तक जो मणि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में पंडित नेहरू की छवि देख रहे थे और बिहार के सबसे ईमानदार व्यक्ति के बतौर स्थापित करने में अपनी लेखकीय मेधा की जुगाली कर रहे थे, आख़िर ऐसा क्या हुआ कि एक वर्ष के अंतराल में ही यह धारणा परस्पर विरोधी हो उठी? सच पूछिए तो मुझे यह प्रतिक्रिया कुंठित ईर्ष्यालोलुप और अंतर्विरोधी ज्यादा लगी. कहीं यह पार्टी के एक बाग़ी सदस्य की प्रतिक्रिया तो नहीं है या जिस कोटे से वह बिहार विधान परिषद के सदस्य बने उसकी प्रतिक्रिया है? अगर जदयू के सदस्य की प्रतिक्रिया के बतौर उनकी टिप्पणी है तो बिहार के जानकार अच्छी तरह जानते हैं कि मणि कभी भी जेनुयन कार्यकर्ता नहीं रहे. यह नीतीश कुमार की भलमनसाहत थी कि उन्होंने उनके जैसे सामान्य आदमी को इतने बड़े गौरवशाली पद पर बिठाया. बिहार की जनता यह ज़रूर जानना चाहेगी कि सहित्य के जिस कोटे से मणि परिषद के सदस्य बने उन्होंने उसके लिए क्या किया? अपने 5 वर्षों के काल में उन्होंने साहित्य संस्कृति विषयक मुद्दों को लेकर न तो परिषद में कोई चर्चा की और न ही अपने विकास निधि से ही कोई ठोस काम किया. पुस्तक ख़रीद के नाम पर एक जगह अपना फंड दिया भी तो अपने ही परिचित श्याम जी को, जो उनके प्रकाशक रहे हैं. शेष पूरी की पूरी राशि उन्होंने एक विधान पार्षद के साले को बेच दी. उनके इस क़दम पर तब ख़बर भी छपी. नीतीश कुमार की नज़रों में तब से मणि का सारा माणिक्य उड़न छू हो गया. नीतीश कुमार बड़े धैर्यवान और ठोस आदमी हैं. उन्होंने बिहार विकास में ही अपनी पूरी शक्ति लगाई है.

शेष पृष्ठ 19 पर

चौथी दुनिया में लेख लिखना महंगा पड़ा

चौथी दुनिया

20

इंदिरा की राह पर चले नीतीश

प्रेम कुमार मणि समझौता न करने वाले शख्स के तौर पर जाने जाते हैं. उन्होंने कई मौक़ों पर अपने तर्कों व बयानों से नीतीश सरकार को कठघरे में खड़ा किया है. यही वजह रही कि पार्टी ने उन पर कार्रवाई की पृष्ठभूमि तैयार की. उन्हें नोटिस भी जारी किया, पर वह अनुशासन समिति के सामने पेश नहीं हुए. इसी बीच उन्होंने चौथी दुनिया में इंदिरा की राह पर चले नीतीश नाम से एक लेख लिखा. पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र और नीतीश कुमार की तानाशाही पर केंद्रित यह लेख सत्ता के गलियारों में काफ़ी चर्चा में रहा. विपक्ष के अलावा जदयू के कई नेताओं ने भी मणि जी को उनके बेबाक लेखन के लिए बधाई दी. अख़बार के पाठकों से भी मणि जी को इस लेख के लिए दाद मिली. बस यही बात जदयू के नीति निर्धारकों को खटक गई. सूत्रों पर भरोसा करें तो उन्होंने अख़बार में छपे लेख को मणि के पार्टी विरोधी कामों का साक्ष्य माना. इस ठोस सबूत ने मणि को पार्टी से निलंबित करने का काम काफ़ी आसान कर दिया. प्रेम कुमार मणि कहते हैं कि मैं अपने निलंबन के लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूं. पार्टी ने जो चुनौती दी है, उसे मैं स्वीकार करता हूं. मैं पूरे बिहार की जनता को बताऊंगा कि बिहार के विकास का सच क्या है. विकास का दावा करना और सही मायनों में विकास करना दोनों अलग-अलग बातें हैं. बिहार की जनता को सच जानने का पूरा अधिकार है.

नीतीश के मुक़ाबले उपेंद्र कुशवाहा को लाने की तैयारी

उपेंद्र कुशवाहा

नीतीश से ख़फ़ा नेता यह बात अब धीरे-धीरे समझने लगे हैं कि नीतीश का विकल्प नीतीश के लोग ही बन सकते हैं. लालू, पासवान या फिर कांग्रेस को जनता स्वीकार नहीं करेगी. इसलिए इन लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश के विकल्प के तौर पर तैयार करने का मन बना लिया है. आठ फ़ीसदी कुशवाहा वोटों की ताक़त समेटे कुशवाहा को पंचायत चुनाव के बाद नेता के तौर पर मैदान में उतारने की तैयारी पटना से लेकर दिल्ली तक चल रही है. उपेंद्र कुशवाहा युवा हैं और कई मौक़ों पर उन्होंने अपने संगठन व नेतृत्व की क्षमता साबित की है. अपनी संपत्ति की घोषणा ख़ुद कर उन्होंने एक मिसाल क़ायम की है. इस गोलबंदी में अरुण कुमार, रामबिहारी सिंह, शंभू श्रीवास्तव, ललन पासवान, नागमणि, प्रभुनाथ सिंह, महेश्वर सिंह, रामानुज यादव, आदि शामिल बताए जाते हैं. सूत्रों के अनुसार और कई दलों के नेता उनके संपर्क में हैं. बताया जाता है कि उचित समय का इंतज़ार किया जा रहा है. मुमिकन है वह समय पंचायत चुनाव के बाद का हो.

जॉर्ज ऑरवेल की इस जन्म स्थली पर मनमोहक सुंदर व विशाल भवन बनाया जाएगा, जिसका नक्शा तैयार किया जा रहा है.

परिवहन विभाग ने सड़कों पर अवर प्रवर्तन निरीक्षकों को नियम के प्रतिकूल चलने वाले ट्रकों, गाड़ियों से अधिक से अधिक राजस्व वसूली के लिए बहाल किया है.

एक नज़र

सीतामढ़ी के अस्पताल बदहाल हैं

अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उपकेंद्रों पर र्डी की कमी, दवाओं का अभाव तथा चिकित्सीय उपकरणों की अनुपलब्धता अब भी बरक़रार है. आउटडोर सेवा में मरीज़ों की भीड़ देख चिकित्सक रोगी की बारीकी से जांच किए बग़ैर एक मिनट में पर्ची पर दवा लिख देते हैं. साथ ही एक ही चिकित्सक को रात में भी ड्यूटी करनी पड़ती है.

विदाई समारोह आयोजित

अररिया मुख्यालय स्थित गर्ल्स गाइड एकेडमी आज़ाद नगर की दसवीं की छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया गया. वर्ग नवीं एवं जूनियर वर्ग की छात्राओं ने सीनियर को विदाई दी. इस मौक़े पर विद्यालय के निदेशक प्रो. रक़ीब अहमद ने कहा कि आज अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राएं भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहरा रही हैं. इस मौक़े पर कुलसुम, असमत, आरा, रज़िया परवीन, ज़ीनत जहां एवं पारसा नग़मा ने भी विचार प्रकट किए.

नियोजन कार्यालय जर्जर हुआ

ज़िला मुख्यालय स्थित डीआरडीए परिसर में चल रहा जिला नियोजन कार्यालय अपने हाल पर रो रहा है. कार्यालय में बरसात के दिनों में पानी भरा रहता है. जर्जर कार्यालय के एक कोने में विभागीय कंप्यूटर व अन्य उपकरण बेकार पड़े हैं. ज़िला नियोजन पदाधिकारी का पद वर्षों से ख़ाली पड़ा है. यहां नियोजन कार्यालय में एक प्रधान सहायक, दो लिपिक, एक अनुदेशक कार्यरत हैं.

सरपंच का निर्विरोध चुना जाना तय

जमुई के सोनो प्रखंड की 19 पंचायतों में से चुरहेत ही एक मात्र ऐसी पंचायत है जिसके सरपंच का निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता अब पूरी तरह साफ़ हो गया है. अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस पंचायत के मुखिया का पद अब एक बार पुन: निवर्तमान मुखिया गेना मांझी के लिए सुरक्षित घोषित हो गया है. इसी तरह सरपंच पद पर निवर्तमान सरपंच चंद्रदेव पासवान भी निर्वाचन के तहत आगामी पांच वर्षों तक अपने पद पर बने रहेंगे. बिहार पंचायत राज नियमावली 2006 के नियम 51 के अध्यधीन निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-13 में मुखिया गेना मांझी व सरपंच चन्द्रदेव पासवान को सम्यक रूप से निर्विरोध निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा.

फोरलेन का रास्ता साफ़

एनएच 77 पर निर्माणाधीन मुजफ्फ़रपुर-हाजीपुर फोरलेन के निर्माण में आ रही भू-अर्जन संबंधी बाधा ख़त्म हो गई है. डीएम संतोष कुमार मल्ल ने एनएचएआई के परियोजना निदेशक, गैमन इंडिया के प्रोजेक्ट मैनेजर सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में ज़िले में होने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा हुई. भू-अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि एनएच 77 निर्माणधीन मार्ग पर कुल 36 गांव पड़ते हैं. इसके मुआवज़ा भुगतान के संबंध में कमेटी ने प्रतिवेदन दे दिया है.

बाल विवाह रोकने का अभियान जारी

बाल संरक्षण अधिकार आयोग की सदस्य अर्पणा सिंह ने सहरसा में कहा कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को धरातल पर उतारने व बाल विवाह रोकने के लिए समाज और सरकार को मिलजुल कर काम करना होगा. श्रीमती सिंह ने कहा कि शिक्षा व बाल विवाह रोकने के नाम पर छल कर रही संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई होगी. वहीं इसे बेहतर तरीक़े से लागू करने वाले स्कूल सम्मानित होंगे.

मानवाधिकार पर सेमिनार

पूर्णिया के ओटोनोमस बीएमटी विधि महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मानवाधिकार के लिए शिक्षा का विकास विषय पर दो दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एसएनझा, बीएनएमयू के कुलपति डॉ. अरुण कुमार, रजिस्ट्रार केपी सिंह, जामिया मिलीया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के प्रोफेसर डॉ. इक़बाल हुसैन, बीएनएमयू के अंग्रेज़ी विभागाध्यक्ष ललितेश मिश्रा ने भाग लिया. इस अवसर पर लॉ कॉलेज के प्राचार्य बिरेन्द्र मोहन ठाकुर ने आगंतुक अतिथि का स्वागत किया. विधि महाविद्यालय के सचिव अनंत भारती ने कहा कि मानवाधिकार मूलत: मानव के अस्तित्व से जुड़ा है.

-चौथी दुनिया ब्यूरो

संजीवनी बिल्डकॉन कैंसर के प्रति जागरूक करेगा

रांची में संजीवनी बिल्डकॉन के सौजन्य से सीएमई का आयोजन किया जाएगा. इसमें 100 से ज़्यादा चिकित्सकों को कैंसर संबंधित नई रिसर्च एवं विधियों की जानकारी दी जाएगी. अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कैंसर विशेषज्ञ पद्मश्री डॉ. एस. एच. आडवाणी दो दिनों के लिए रांची आएंगे. डॉ. आडवाणी मुंबई के रहेजा सुश्रुत अस्पताल के ऑकालोजी विभाग के डायरेक्टर हैं. डॉ. आडवाणी कैंसर के रोगियों का इलाज करेंगे व सलाह देंगे. रांची कैंसर सेंटर, लाह कोठी, रातु रोड के डॉ. भोला प्रसाद, कैंसर विशेषज्ञों के अनुरोध पर डॉ. आडवाणी झारखंड के मरीज़ों को अपनी सेवा देने आ रहे हैं.

-अनुमेहा झा

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT

- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, which is Govt. of India registered, Regd. No. 03-09284 of 2000-2001.
- ISO 9001:2000 certified, Regd. No. CCPL/QMS/C1487
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where Practicals are conducted.
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where one full paper of 100 marks on petroleum is taught.
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where students of Industrial Safety Management Course of Patna University & Magadh University get Practical Training.

FREE Demo-Classes in the Morning & Evening from Monday to Friday

Excellent Placement with Handsome Salary

Website : www.psfsm.com

410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001

Ph : 0612-6455019, Mob. : 9334107607, 9835042835, 9234729075

प्रत्याशियों की ढपली और चुनावी राग

समस्तीपुर : पंचायत चुनाव

विकास कुमार

समस्तीपुर ज़िले में पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है. कल तक अपने काम से मतलब रखने वाला आज विकास की बातें कर रहा है. मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए प्रत्याशियों एवं समर्थकों द्वारा तरह-तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं. कोई एपीएल और बीपीएल का मतलब समझा रहा है तो कोई जीतने पर सोलर लाईट और चापाकल देने की चर्चा कर रहे हैं. वैसे आरोपित जनप्रतिनिधियों को मन मसोसकर चुनाव मैदान से बाहर रहना पड़ रहा है. सर्वाधिक मारामारी मुखिया पद के लिए है. मुखिया बनने की होड़ में धनबली, बाहुबली, दबंग, शिक्षाविद् और पत्रकार भी शामिल हैं. नामांकन के दौरान कुछ प्रखंडों में प्रत्याशियों द्वारा आचार संहिता का भी खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन ऐसी ग़लती करने वालों की संख्या अधिक होने के कारण प्रशासन भी कार्रवाई के बजाए मूकदर्शक बने रहना बेहतर समझता है. मुखिया एवं पंचायत समिति के उम्मीदवारों को मात्र 25 हज़ार की राशि के अंदर चुनाव लड़ना है लेकिन नामांकन के दिन ही इससे कहीं अधिक राशि ख़र्च की जा रही है.

ज़िले के शाहपुर पटोरी में नामांकन वापसी की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद कुल 1294 उम्मीदवार विभिन्न पदों के लिए मैदान में रह गए हैं. ज़िला परिषद के लिए नामांकन वापसी के अंतिम दिन दो प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया, वहीं पटोरी प्रखंड में मुखिया के लिए 5, पंचायत समिति के लिए 2, वॉर्ड सदस्य के लिए 3, पंच के लिए 5 तथा सरपंच के लिए 1 कुल 16 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लेकर कइयों के समीकरणों को बना-बिगाड़ दिया है. यहां से अब ज़िला परिषद के लिए कुल 89 उम्मीदवार मैदान में हैं.

पंचायत चुनाव को लेकर वारिसनगर प्रखंड के चौक-चौराहों एवं चौपालों में नामांकन करने को लेकर रणनीति बनने लगी है. 20 पंचायतों वाले इस प्रखंड में मुखिया के 20, सरपंच के 20, ज़िला परिषद के 3, पंचायत समिति के 27, वार्ड सदस्य के 274 एवं पंच के 274 पद हैं. बता दें कि यहां 1 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी. मोरबा प्रखंड में चुनाव को लेकर प्रखंड मुख्यालय में 6 कोशांगों का गठन किया गया है. सरायरंजन प्रखंड में पंचायत चुनाव नौवें चरण में होना है, लेकिन क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी रेस पकड़ने लगी है. यहां 15 मई को कुल 736 पदों के लिए चुनाव होने हैं. इस प्रखंड में कुल 327 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इसी तरह शिवाजीनगर प्रखंड में भी चुनावी चहल-पहल दिख रही है. यहां पत्रकार भी चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं और कहीं सास-बहू में चुनावी जंग छिड़ी है. यहां के 17 पंचायतों में मुखिया पद के कुल 149 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें सर्वाधिक जमघट शंकरपुर पंचायत में है तथा सबसे कम उम्मीदवार बल्लीपुर पंचायत में हैं. इस बार के चुनाव में कुछ ऐसे निवर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने पंचायत चुनाव से मुंह मोड़ लिया है. ज़िला परिषद क्षेत्र सं. 43 के निवर्तमान पार्षद सावित्री देवी, क्षेत्र सं. 44 के पार्षद डॉ. शिवशंकर मंडल, बल्लीपुर की मुखिया उर्वशी चौधरी, करियन की मुखिया अनीता देवी, डुमरामोहन के मुखिया जवाहर मंडल, शंकरपुर के मुखिया तपेश्वर प्रसाद सिंह, बंधार पंचायत के पंचायत समिति सदस्य नंद कुमार चौधरी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. वहीं कुछ ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें इस बार बदलाव की ज़रूरत महसूस हो रही है. डुमरा मोहन पंचायत की सरपंच रिंकी सिंह, दहियार रन्ना के सरपंच किशोर मुखिया, शंकरपुर के सरपंच गोपाल पासवान आदि इस बार मुखिया पद के लिए एड़ी-चोटी एक किए हुए हैं. इसके अलावा मुखिया पद से खड़े होने वाले अन्य प्रमुख लोगों में रानीपरती पंचायत से पत्रकार प्रभात कुमार सिंह, भटौरा पंचायत से जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हीरालाल सिंह, डुमरा मोहन पंचायत से लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष रामप्रसाद सिंह, युवा जदयू के प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार सिन्हा की पत्नी अनीता देवी रजौड़ रामभद्रपुर पंचायत से एवं राजद के प्रखंड अध्यक्ष वैद्यनाथ पोद्दार की पत्नी डुमरा मोहन पंचायत से शामिल हैं. शंकरपुर पंचायत के मुखिया तपेश्वर सिंह पदच्युत हो चुके हैं और उन्होंने इस बार अपनी पत्नी रामकाशी देवी को मुखिया पद का उम्मीदवार बनाया है, लेकिन उनका मुक़ाबला करने उनकी पुत्रवधू राजकुमारी देवी पूरे दम-ख़म के साथ मैदान में कूद पड़ी हैं.

रोसड़ा प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद मुखिया के 16 पद के लिए 67 उम्मीदवार सामने आए हैं. इसके अलावा पंचायत समिति के लिए 81, वॉर्ड सदस्य के लिए 280 एवं पंच के लिए 134 उम्मीदवारों ने नामज़दगी के परचे भरे हैं. इस प्रखंड से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में निवर्तमान मुखिया वीणा देवी, राजेंद्र शर्मा, तारा देवी, अशर्फ़ी दास, देवनारायण राय, अरुण कुमार सिंह, तारा देवी, पिंकी देवी शामिल हैं. इसके अलावा सोनूपुर उत्तर से सुनील कुमार झा, रामस्वार्थ यादव, ठाहर बसढ़िया से दिनकर चौधरी, भरवारी पंचायत के निवर्तमान मुखिया पवन कुमार यादव की उम्मीदवारी की विशेष चर्चा होती है. पंचायत समिति के लिए प्रखंड प्रमुख गायत्री देवी एक बार फिर से चुनाव लड़ रही है. इसके अलावा इशरत ख़ातून, चंद्रकला देवी, रिंकी देवी, राजेंद्र पासवान, शिवशंकर शर्मा, रामउचित चौधरी, शैल देवी, उमेशचंद्र मिश्र भी भाग्य आज़मा रहे हैं. पंचायत समिति सदस्य के लिए चकथात पश्चिम पंचायत से पिंकी सिंह, रहुआ पंचायत से सरोज कुमार झा जीत का जज्बा दिखा रहे हैं. पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर ज़ोर-शोर से तैयारी की जा रही है. मतदान केंद्रों के निर्धारण को अंतिम रूप दे दिया गया है. ज़िले में कुल 5212 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी सह ज़िलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि ज़िले में कुल 106 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखकर यह केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें विभूतिपुर के 24, हसनपुर के 11, पटोरी के 11, पूसा का 1, समस्तीपुर के 9, कल्याणपुर के 3, मोहनपुर के 10, बिथान के 6, सरायरंजन के 1, शिवाजीनगर के 25 एवं सिंघिया के 5 चलंत मतदान केंद्र शामिल हैं.

पुष्पलता देवी, गायत्री देवी, पिंकी देवी, घुरन यादव, राजेन्द्र शर्मा, राम किशोर राय

feedback@chauthiduniya.com

नीतीश विरोधियों पर
अनुशासन का डंडा

पृष्ठ 17 का शेष

उन्होंने कोशिश भी की कि मणि रास्ते पर आएं, लेकिन वह तो एमएलसी के अलावा कुछ और भी पाने के हिमायती थे. उनकी इस महत्वाकांक्षा ने आज यह दुर्गति करवाई है. बिहार की जनता के मन में आज भी यह सवाल है कि मणि ने बिहार की साहित्य संस्कृति विषयक समस्याओं को लेकर आख़िर क्यों नहीं कोई पहल की. नवनिर्मित हिंदी भवन, राष्ट्रभाषा परिषद और भाषा अकादमियों की आज जो बिहार में स्थिति है, अगर इसके बाबत मणि कोई सवाल उठाते तो मैं उनका स्वागत करता और मुख्यमंत्री जी को भी ख़ुशी होती, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की संवेदनशीलता को भुनाने की तिकड़म में इस तरह की कटुक्तियां प्रसार माध्यमों में फैलानी शुरू की है. आख़िर किसी दल का कोई अनुशासन होता है या नहीं? अगर दल के जनतांत्रित ढांचे पर ही मणि जैसे अवसरपरस्त चोट करने लगेंगे तो फिर इसका क्या भविष्य होगा यह सोचने वाली बात है. साहित्य को संवेदना की मातृभूमि माना गया है और यह समाज अपने साहित्यकारों को ऋषि तुल्य मानती आई है. अगर दल और सरकार बहुसंख्यक आबादी के हितपोषण में डंडी मार रही है तो नैतिकता कहती है कि मणि को अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. अगर उनमें ऐसी नैतिकता और पात्रता होती तो वह मुख्यमंत्री की छवि मर्दन की अपनी इस कटुतापूर्ण आग्रह से बचते, इस्तीफ़ा देते और समाज के सामने अपनी दलील रखते कि किन कारणों से उन्होंने ऐसा किया, लेकिन चूंकि उनके पास सरकार और दल की कमियों पर उंगली रखने का कोई नैतिक साहस नहीं है, इसलिए वह इस तरह की छिछली कारगुज़ारियों में व्यस्त नज़र आ रहे हैं. मणि विधान परिषद की प्रकाशन कमेटी के अध्यक्ष थे. अभी हाल ही में उन्हें गुरुत्तर दायित्व से छुटकारा दिया गया. जानकारों की मानें तो उनकी नाराज़गी की बड़ी और तात्कालिक वजह यही है,क्योंकि कमेटी में रहकर जो सुख सुविधाएं उन्होंने 5 वर्षों तक भोगीं, अब वह पीड़ा उन्हें सालने लगी है. कमेटी से इनके अलग होने की वजहों पर विचार करें तो आपको समझने में यह देर नहीं लगेगी कि उन्होंने कोई भी ऐसी पहलक़दमी नहीं कि जिससे कमेटी में विकास की कोई रूपरेखा दिखे. मणि परिषद की चर्चित पत्रिका साक्ष्य ओर संवाद के भी संपादक रहे. ज्ञातव्य हो कि पूर्व संपादक जाबिर हुसैन ने एक विशेषांक निकालकर इसे अखिल भारतीय स्तर पर चर्चित किया था. यह जानना दिलचस्प होगा कि मणि ने 5 वर्षों में इस पत्रिका के कितने अंक निकाले और इन अंकों की अहमियत क्या है? ज्ञातव्य कि मणि ने प्रेमचंद और दिनकर पर महज़ दो विशेषांक इन पत्रिकाओं के निकाले. यहां सहज सवाल उठता है कि ये विशेषांक उन चर्चित लेखकों पर ही क्यों? फिर यह भी कि इनमें 90 प्रतिशत न सिर्फ़ दूसरी पत्रिकाओं से लिए गए अपितु संपादकीय निर्लज्जता की पराकाष्ठा देखिए कि इनमें साभार लिखने की नैतिकता भी धो डाली . परिषद कोई राष्ट्रभाषा परिषद या बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी जैसी संस्था नहीं है कि वहां से साहित्यिक शख्सियत पर कोई विशेषांक निकले. मणि अपने भाषणों और लेखन में दलित और पिछड़ावाद की पुरज़ोर वकालत करते हैं, लेकिन क्या वह अनूपलाल मंडल और रेणु पर यह विशेषांक नहीं निकाल सकते थे. यहां किसने अड़चन डाली. आज वह नीतीश कुमार की जीत को भाजपा की जीत बता ख़ुद को क्रांतिकारी और सेकुलरिज्म के सिपाही के तौर पर पेश कर रहे हैं.

अंतिम बात, प्रेम कुमार मणि अपने अनुशासनहीन साथियों के बचाव में इस हद तक गिर सकते हैं, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी . वह ख़ुद को शहीद कहलवाने पर तुले हुए हैं. भविष्य जानता है कि उनकी जगह कूड़ेदान में ही होगी. जो लोग शहीद कहलवाने की जुगत में लगे हैं वे सभी अमरलत्ती मार्का नेता हैं, जनता में इनका कोई वजूद नहीं है. नीतीश कुमार जैसे लोकतंत्र की मर्यादा को समझने ओर निभाने वाले राजनेता पर अनर्गल आरोप लगाना प्रेम कुमार मणि के मानसिक संतुलन खो देने का परिचायक है और यह बतलाता है कि वह मानसिक दिवालियापन के चरम पर हैं.

– उपेंद्र चौहन *कवि एवं जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष*

एक नज़र

रिहैब-मीट जारी रहे : डॉ. अनिल सुलभ

पटना में फिर मिलेंगे अगले वर्ष नए मुद्दों, नई तैयारी के साथ. इसी संकल्प के साथ विकलांगजनों के शत-प्रतिशत पुनर्वास राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पांच पुनर्वास विशेषज्ञों को रिहैब-मीट प्रोफेशनल एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया. इस अवसर पर आयोजन समिति के संरक्षक तथा हेल्थ इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. अनिल सुलभ ने आयोजक संस्थाओं-भारतीय पुनर्वास परिषद्, बिहार शिक्षा परियोजन परिषद् तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च के अधिकारियों एवं आयोजन समिति को बधाई दी. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष से इस देश में पुनर्वास कर्मीदल के साझा-मंच के रूप में जो सिलसिला रिहैब-मीट के रूप में आरंभ हुआ है, वह निरंतर जारी रहना चाहिए. समारोह के मुख्य अतिथि ग्रामीण-कार्य विभाग के मंत्री प्रो. भीम सिंह ने सम्मेलन को जनहित का एक बड़ा अभियान बताते हुए कहा कि ऐसे सम्मेलन विकलांगता की चुनौतियों का समाना करने के लिए सरकार और समाज के सामने ठोस उपाय बताने में सफल होते हैं.

-अनुमेहा झा

कैसर अली प्रदेश महासचिव बने

अररिया ज़िला के रजोखर गांव निवासी जदयू के वरिष्ठ नेता कैसर अली को जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी. उन्होंने कहा कि आज मैं आप लोगों कि वजह से यहां तक पहुंचा हूं. इसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूं. इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मो. सलाम सहित ज़िलाध्यक्ष नौशाद आलम, पूर्व मंत्री मंजर आलम, शौकत अली, उमेश राय, रमेश सिंह आदि ने उन्हें साधुवाद दिया.

बसें हिचकोले खाती हैं

मधुबनी रेलवे स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर से 13 नंबर गुमटी को जोड़ने वाली सड़क विभागीय उदासीनता के कारण धंसती जा रही है. इसके कारण दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है. इस पथ से प्रतिदिन रामपट्टी, राजनगर, कोइलबर, कोठिया सहित विभिन्न जगहों के लिए यात्री-वाहन गुज़रते हैं. बरसात के दिनों में यह सड़क नदी में तब्दील हो जाती है.

रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं का अभाव

आदर्श रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त मधुबनी रेलवे स्टेशन पर व्याप्त कुव्यवस्था के प्रति रेल विभाग पूरी तरह उदासीन बना हुआ है. रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का घोर अभाव है. परिसर के प्रवेश द्वार पर लोग यहां-वहां गंदगी फैलाए हुए हैं. पीने का पानी भी नहीं है. सभी प्लेटफार्म का एक ही जैसा हाल है. यहां तक की बैठने की सुविधा तक नहीं है. टिकट काउंटर पर बिचौलियों का जमावड़ा लगा रहता है.

अधिवक्ता संघ का चुनाव

सीवान में हुए द्विवार्षिक सत्र अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद के वरीय अधिवक्ता हरेन्द्रनाथ श्रीवास्तव ने विजय मत हासिल किया, वहीं वरीय अधिवक्ता प्रेम कुमार सिंह महासचिव चुने गए. अध्यक्ष पद पर अधिवक्ता हरेंद्रनाथ श्रीवास्तव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी शिवशंकर तिवारी को 510 मतों से पराजित किया. प्रेम कुमार ने 328 मत पाकर विजय हासिल की.

प्रधानाध्यापकों पर केस दर्ज होगा

ज़िलाधिकारी लोकेश कुमार सिंह ने अपने कक्ष में सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षात्मक बैठक की. उन्होंने बताया कि वर्ष 2008-09 तक ज़मीन अनुपलब्धता या अन्य कारणों से अतिरिक्त वर्ग कक्ष की राशि वापस न करने वाले प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है. साथ ही वापस की गई राशि से इसी प्रखंड के वर्ग कक्ष का निर्माण के लिए विद्यालय का चयन भी किया गया है. बैठक में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई. जिलाधिकारी ने अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि पहले से निर्देशित प्राथमिकी दर्ज कराने के हर आदेश को जल्द से जल्द पूरा करवाएं.

-चौथी दुनिया ब्यूरो

पुलिस के ख़िलाफ़ बवाल

किशनगंज के बहादुरगंज में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों ने बवाल खड़ा किया. झांसी रानी चौक पर प्रदर्शन और सड़क जाम किया. लोगों का कहना था कि थाना अध्यक्ष आरती जायसवाल के निलंबन के उपरांत थाना अध्यक्ष का प्रभार इंस्पेक्टर को सौंपा गया था. वहां लोगों की शिकायत नहीं सुनी जा रहा थीं.

-विश्वमोहन झा

गया नगर निगम
लूट सको तो लूटो

सुनील सौरभ

गया शहर की साफ़-सफ़ाई से लेकर नागरिकों को तमाम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा सर्वांगीण विकास की ज़िम्मेवारी नगर निगम की है. पहले इस नगर निगम का दायरा 40 वार्ड तक ही था, लेकिन अब बढ़कर 53 वार्ड हो गया है. इस शहर का दुर्भाग्य है कि जब नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ था, तो क़रीब ढाई दशक तक यहां क़ाबिज़ पदाधिकारी इसे अपना मतलब साधने और लूट का अड्डा मान बैठे थे. लेकिन जब लंबे अर्से के बाद नगर निकाय का चुनाव हुआ तो शहर के नागरिकों को उम्मीद बंधी थी कि निर्वाचित प्रतिनिधि शहर की तक़दीर और तस्वीर बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सुधार की उम्मीद लिए शहर के नागरिकों ने जब नगर निकाय के दूसरे चुनाव में 53 प्रतिनिधियों को चुना तो लगा कि अब कुछ बेहतर होगा, परंतु गया नगर निगम स्वार्थ की राजनीति, ऐन-केन-प्रकारेण रुपये कमाने के साथ-साथ अजीबो-ग़रीब फ़ैसले के लिए चर्चित हो गया. सही में गया नगर निगम की आज की स्थिति लूट सको सो लूटो वाली हो गई है.

गया नगर निगम में कमीशनख़ोरी की हालत यह है कि कई बार तो निगम कर्मियों और वार्ड पार्षदों के बीच मारपीट तक हो चुकी है. उप मेयर अखौरी ओंकारनाथ उर्फ़ मोहन श्रीवास्तव ने तमाम आरोपों को नकारात्मक सोच बताते हुए कहा कि गया नगर निगम में कोई भी निर्णय सदन तथा स्टैंडिंग कमेटी व बोर्ड द्वारा लिया जाता है.

शगुफ्ता परवीन, चितरंजन वर्मा, मोहन श्रीवास्तव

अधिकांश वार्ड आयुक्त से लेकर अपर पायदान पर बैठक निर्वाचित प्रतिनिधि तक कमीशनख़ोरी में लिप्त है. किसी भी वार्ड में होने वाली विकास योजनाओं में 18 प्रतिशत कमीशन देना पड़ता है. नगर निगम की ओर से किर्लोस्कर कंपनी का एक जेनरेटर ख़रीदा गया है. इस कंपनी के पैंतीस से चालीस केवीए के जेनरेटर का बाज़ार मूल्य क़रीब साढ़े तीन लाख रुपये है, लेकिन नगर निगम द्वारा इस जेनरेटर की ख़रीद साढ़े आठ लाख रुपये में की गई है. शहर को रात में रोशनी से जगमग करने के लिए बारह हाई मास्क लाइट की ख़रीद प्रति लाइट पांच लाख पचीस हज़ार रुपये में की गई है. 24 मिनी हाई मास्क लाइट की ख़रीद एक लाख पचहत्तर हज़ार रुपये प्रति की दर से ख़रीदी गई है, जबकि इसे लगाने के लिए एक फर्म ने एक लाख पचपन हज़ार रुपये का टेंडर डाला था, लेकिन इस फर्म के टेंडर को काग़ज़ात की कमी बताकर टेंडर से अलग कर दिया गया और अकेले बचे टेंडर कर्ता से दर वार्ता कर एक लाख पचहत्तर हज़ार रुपये प्रति की दर से काम दे दिया गया. इससे भी निगम को लाखों रुपये का चूना कमीशन के लिए लगाया गया. मज़ेदार बात यह है कि इन सभी हाई मास्क लाइट की जांच की जाए तो वह सब नक़ली कंपनी का निकलेंगी. सिर्फ़ इसमें लगे बल्ब ही असली कंपनी के हैं.

गया नगर निगम के वार्ड 36 के पार्षद और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चितरंजन प्रसाद वर्मा ने बताया कि मेयर, उपमेयर तथा कुछ वार्ड पार्षदों की मिलीभगत से हर काम में कमीशनख़ोरी की जा रही है. उन्होंने बताया कि शहर को धार्मिक पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से मॉडल रूप देने के लिए शहर की सफ़ाई का ठेका राज्य सरकार की पहल पर रैम्की नामक संस्था को दिया गया है. इसके 18 लाख रुपये के पहले बिल के भुगतान के लिए 16 प्रतिशत कमीशन वसूला गया. इसी प्रकार आने वाले समय में इस कंपनी के बिल के नियमित भुगतान के लिए दो करोड़ रुपये का 16 प्रतिशत की दर से 32 लाख रुपये कमीशन की अग्रिम मांग की जा रही है. चितरंजन वर्मा ने बताया कि इन लोगों की मनमानी से पटना उच्च न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना की जा रही है. मामला मगध ट्यूबेल इंजीनियरिंग को सार्वजनिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों, आवासों पर ट्यूबवेल व अन्य कार्य के लिए पैंतीस लाख पचास हज़ार रुपये अग्रिम दिए गए थे, जिसमें से इस कंपनी ने दो लाख सतहत्तर हज़ार आठ सौ बावन रुपये का कार्य किया. शेष बत्तीस लाख बहत्तर हज़ार एक सौ अड़तालीस रुपये इस कंपनी से वसूलने का आदेश नगर निगम के तत्कालीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने 15 सितंबर 2006 को दिया था. इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय ने भी मगध ट्यूबेल इंजीनियरिंग का दावा ख़ारिज कर दिया है. बावजूद इसके संबंधित कंपनी से बकाया राशि वसूलना तो दूर रहा, बिना काम कराए बक़ाया राशि का भी भुगतान कराने की साज़िश की जा रही है, जबकि नगर निगम के तत्कालीन नगर आयुक्त राय मदन किशोर ने अपने पत्रांक 990/10 द्वारा एक टेंडर के लिए डाले गए 2 लाख रुपये को ज़ब्त करने का आदेश दिया था, जिससे 32 लाख 72 हज़ार एक सौ अड़तालीस रुपये की बक़ाया राशि में इस राशि को सामंजन किया जा सके. बताया जाता है कि इस फाइल को ही ग़ायब करा दिया गया है. इसी प्रकार हर वार्ड पार्षद को उपकृत करने के लिए चार-पांच निजी मज़दूर रखकर अपने वार्ड की सफ़ाई कार्य कराने का स्थाई आदेश है.

बताया जाता है कि इस मामले में फ़र्ज़ी बिल बनाकर भुगतान ले लिया जाता है. नगर निगम में कमीशनख़ोरी की हालत यह है कि कई बार तो निगम कर्मियों और वार्ड पार्षदों के बीच मारपीट तक हो चुकी है. उपमेयर अखौरी ओंकारनाथ उर्फ़ मोहन श्रीवास्तव ने तमाम आरोपों को नकारात्मक सोच बताते हुए कहा कि नगर निगम में कोई भी निर्णय सदन तथा स्टैंडिंग कमेटी व बोर्ड द्वारा लिया जाता है. कोई भी कार्य हवा में नहीं बल्कि फाइल के माध्यम से होता है, जिसमें मेरी भूमिका सकारात्मक सोच के साथ सदन के अन्य वार्ड पार्षदों की तरह ही है. मैंने व्यक्तिगत स्तर पर भी शहर के विकास के लिए काफ़ी पहल की है. वार्ड पार्षदों के आपसी द्वेष और निगमकर्मियों की भूमिका से अंतत: शहर तथा शहरवासियों को ही ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ रहा है. किसी भी काम के लिए महीनों तक नगर निगम के चक्कर लगाना यहां के नागरिकों की लाचारी बन गई है.

feedback@chauthiduniya.com

राजमार्ग ओवरलोडिंग से दरक रहे हैं

नीरज कुमार सिंह

वर्तमान सुशासन की सरकार जहां राज्य में सड़कों का जाल बिछाने में व्यस्त है, वहीं उनके परिवहन विभाग के प्रवर्तन अवर निरीक्षकों, एमवीआई, ट्रक एंट्री माफ़िया की मिलीभगत से ओवरलोडिंग ट्रकों के कारण राज्य मार्ग तो क्या राष्ट्रीय राजमार्ग की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है. सड़कें टूट रही हैं. सीमाचंल के पूर्णिया, किशनगंज, अररिया एवं कटिहार होते हुए कई राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ महत्वपूर्ण राज्य मार्ग गुजरते हैं, जिसमें फोर लेन एनएच 31 जो पूर्णिया, किशनगंज, सिलीगुड़ी होते हुए पूर्वोत्तर भारत को देश के शेष भागों से जोड़ता है, वहीं एनएच 57 फोर लेन पूर्णिया अररिया सुपौल होते हुए दिल्ली को जाता है व नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूता है. इसके साथ बंगाल बोर्डर गलगलिया से ठाकुरगंज होते हुए अररिया पथ, ठाकुरगंज-किशनगंज पथ, पूर्णिया-सहरसा पथ, पूर्णिया-रुपौली पथ व पूर्णिया-कटिहार पथ जैसे सड़कों का निर्माण अभी हाल ही में हुआ है, लेकिन ओवरलोडिंग ट्रकों के थपेड़ों से ये सड़कें दरककर टूट रही हैं. इन सड़कों से पत्थर छिटक गए हैं व जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं. सीमांचल में ट्रक ओवरलोडिंग का कारोबार कई वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें प्रवर्तन अवर निरीक्षक, एमवीआई से लेकर कई ट्रक इंट्री माफ़िया संलग्न है. हालांकि राज्य सरकार के कड़े रुख़ एवं वर्तमान कठोर क़ानून प्रवेंशन ऑफ डेमेज पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट 1984 के तहत न्यूनतम 6 माह या अधिकतम 5 वर्ष करावास की सज़ा का प्रवधान है, जिसके कारण ट्रक एंट्री धंधे में कमी आई थी, लेकिन रात के अंधेरे में यह धंधा पुन: अपने शबाब पर है. परिवहन विभाग ने सड़कों पर अवर प्रवर्तन निरीक्षकों को नियम के प्रतिकूल चलने वाले ट्रकों, गाड़ियों से अधिक से अधिक राजस्व वसूली के लिए बहाल किया है. लोगों के अनुसार उनका क्रियाकलाप परिवहन विभाग के नियम-क़ानून के प्रतिकूल चलता है. प्रवर्तन निरीक्षक के साथ चलने वाले व्यक्ति के मोबाइल पर ट्रक एंट्री माफ़िया गाड़ी नंबर का संदेश भेजते हैं, जिसका मतलब है एंट्री शुल्क वसूल हो चुका है. कुछ ट्रक ड्राइवरों ने जानकारी दी की पूर्णिया के बेलगच्छी व किशनगंज के केलटेक्स चौक के पास प्रवर्तन निरीक्षक की निगरानी में ओवरलोडेड ट्रकों को पास कराया जाता है. प्रवर्तन निरीक्षक की कमाई को देखते हुए पूर्णिया के डगरूआ थाना में पदास्थापित एक थानेदार ने परिवहन विभाग का रुख़ किया व सुशासन में ही अपना पहला पदास्थापना प्रवर्तन अवर निरीक्षक के रूप में पूर्णिया कराया, क्योंकि डगरूआ में ही परिवहन विभाग का सरकारी बेरियर है और प्रवर्तन निरीक्षक के कमाई के स्रोत को जान चुका था. वर्तमान में ये महोदय किशनगंज में पदास्थापित हैं. वर्तमान में ओवरलोडेड 50-60 टन बेडमिसाली सिलीगुड़ी से सीमांचल के ज़िलों में आ रहा है. वहीं से 50-60 टन ईंट लेकर ट्रक बंगाल के सिलीगुड़ी, दार्जलिंग, जलपाईगुड़ी पहुंच रहा है. सीमांचल में ईंट भट्ठों की प्रचुरता है, वहीं बंगाल में क़ानूनी दाव-पेंच के कारण ईंट भट्ठा खोलना आसान नहीं है, जिससे यहां ईट महंगें दामों में बिकती हैं. प्रवर्तन निरीक्षकों के साथ चलने वाले निजी व्यक्तियों के बारे में जब ज़िला परिवहन पदाधिकारी से जानकारी ली गई तो उनका कहा कि प्रवर्तन निरीक्षकों को सरकारी सिपाही रखने का प्रवधान है, लेकिन नियम के प्रतिकूल ये लोग निजी व्यक्तियों को साथ रखते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

A. KUMAR WISHES YOU A HAPPY HOLI

Join EXPERT BANK COACHING for BANK, RLY, SSC, AIR FORCE, NAV Y, ARMY

Join MODERN STUDY CENTRE for English Classes (XI, XII, Spoken & Competitive)

VENUE-KASHIPUR, SAMASTIPUR

A.KUMAR CHAIRMAN CUM FACULTY : ENGLISH

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

नामांकन सूचना-2011

(A) Bachelor of Library and information Sc. (सत्र-2011-12) के एक वर्षीय पाठ्यक्रम (दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से) में नामांकन के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते हैं।

योग्यता- किसी भी विषय में कम-से-कम 50% अंक से स्नातक में उतीर्ण या वैसे अभ्यर्थी जिन्हें पुस्तकालय/सूचना केन्द्र (राजकीय/राष्ट्रीय) में कम-से कम 2 वर्षो का अनुभव और 45% से उतीर्ण हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। (पाठ्यक्रम शुल्क Rs. 12000/- एवं अन्य शुल्क Rs. 1500/-) आवेदन पत्र (विवरणिका के साथ) रूपये 375/- (अनु.जा. एवं ज.जा के लिए 200/- रूपये मात्र) नकद या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 13 अप्रैल 2011 तक निम्नलिखित केन्द्रों से प्राप्त एवं जमा किया जा सकता है। 1. DDE Office M.U, 2. Gaya College, Gaya 3. J.D. Women's College, Patna, 4. A.N. College, Patna 5. M.U. Branch Office Patna, 6. Nalanda College, Biharsharif. 7. S.Sinha College, Aurangabad, 8. Sri Arvind Mahila College, Patna, बैंक ड्राफ्ट सिर्फ सेन्ट्रल बैंक से बना होना चाहिए जो Director, DDE, MU के नाम से देय तथा अदाकर्ता शाखा Bodh Gaya हो। आवेदन वेबसाईट www.mudde.org से भी डाउनलोड कर आवेदन पत्र डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा किया जा सकता है। डाक द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए 50 रूपये अतिरिक्त का डिमांड ड्राफ्ट भेज कर मुख्यालय से मंगवाया जा सकता सकता है।

Date of Counselling-cum-Admission	:	18 एवं 19 अप्रैल, 2011
Venue	:	DDE मुख्यालय, बोधगया

उक्त तिथि को समस्त मूल अंक-पत्र/मूल प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम शुल्क एवं अन्य शुल्क के साथ उपस्थित हों।

सभी प्रमाण पत्र सही पाये जाने पर उसी दिन नामांकन कर लिया जायेगा।

माननीय कुलपति के आदेशानुसार
डॉ. मो. इसराईल खाँ
निदेशक

चौथी दुनिया की रिपोर्ट पर प्रशासन हरकत में आया
जॉर्ज की जन्मस्थली का कायापलट

मनोज कुमार राव

चौथी दुनिया ने अपने बिहार झारखंड संस्करण में पूर्वी चंपारण स्थित प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय लेखक जॉर्ज आरवेल की जन्म स्थली की दुर्दशा पर एक रिपोर्ट झूठे वादों के मार से बेहाल नामक शीर्षक से प्रकाशित की थी. इसमें पूर्वी चंपारण स्थित इस पर्यटक स्थल की सरकारी अनदेखी पर एक रिपोर्ट को बिहार झारखंड के पाठकों के सामने एक मुद्दा बनाकर रखा गया था, जिसमें ज़िलाधिकारी नर्मदेश्वर लाल ने शीघ्र ही उचित कार्रवाई का चौथी दुनिया को आश्वासन भी दिया था. इस रिपोर्ट में पूर्वी चंपारण के अन्य पर्यटक स्थलों मसलन मोती झील, सोमेश्वर नाथ मंदिर, मेहसी का सीप उद्योग व पश्चिमी चंपारण के भीतीहरवा आश्रम की दुर्दशा के बारे में भी चर्चा की गई थी. फ़िलहाल पूर्वी चंपारण प्रशासन ने अपने कार्य की शुरुआत जॉर्ज ऑरवेल के जन्म स्थली के जीर्णोद्धार के प्रयास से की है.

ज़िलाधिकारी नर्मदेश्वर लाल ने चौथी दुनिया को एक गंभीर साप्ताहिक अख़बार बताते हुए इसके प्रयासों की प्रशंसा की और शीघ्र ही अन्य पूर्वी व पश्चिमी चंपारण के अन्य पर्यटक स्थलों की समुचित जीर्णोद्धार का आश्वासन भी दिया. ज़िलाधिकारी ने बताया कि इस कार्य के लिए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र ही रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है. एनआरईपी निदेशक उमाशंकर राम ने बताया कि जॉर्ज ऑरवेल की इस जन्म स्थली पर मनमोहक सुंदर व विशाल भवन बनाया जाएगा, जिसका नक्शा तैयार किया जा रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि क़रीब तीन हज़ार 500 फीट में बाउंड्री बनाई जाएगी, जिसको एक आधुनिक रोड से जोड़ा जाएगा, ताकि पर्यटकों को यहां तक आने में कोई असुविधा न हो. इस स्थल को कई प्रकार के पार्कों से भी सजाया जाएगा तथा इससे जुड़ने वाली सड़क के दोनों ओर पौधे लगाए जाएंगे.

- 3500 फीट में बनेगी चाहरदीवारी
- जीर्णोद्धार के लिए 28 लाख रुपये आवंटित

सरकारी सूत्रों के अनुसार जॉर्ज ऑरवेल की जन्म स्थली के जीर्णोद्धार के लिए पर्यटन विभाग की ओर से फ़िलहाल 28 लाख रुपये का आवंटन कर दिया गया है. इसकी रूपरेखा ज़िला प्रशासन की ओर से तैयार की जा रही है.

पूर्व ज़िलाधिकारी प्रेम सिंह मीणा ने भी इस कार्य में रुचि ली थी एवं आर्किटेक्ट हाशमी ने इस स्थल के जीर्णोद्धार के लिए एक रूपरेखा प्रशासन को सौंपी भी थी, लेकिन ज़िलाधिकारी के तबादले से यह कार्य अधूरा रह गया था. उधर दो सप्ताह पूर्व चौथी दुनिया में इस ख़बर के प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अब वह दिन दूर नहीं जब जॉर्ज ऑरवेल की जन्म स्थली पूरे विश्व के लिए एक धरोहर साबित होगी. ग़ौरतलब है कि जॉर्ज ऑरवेल का जन्म मोतिहारी में 25 जून 1903 को हुआ था. उनके पिता का नाम रिचर्ड वॉल मेसले व माता का नाम ईरा था. इनके पिता अंग्रेजों के समय में चंपारण स्थित अफ़ीम के गोदामों की देखरेख किया करते थे. 1905 में उनके पिता इंग्लैंड वापस चले गए. उनकी पुस्तक 1984 व एनिमल फॉर्म के लिए उन्हें ख़ासी उपलब्धि हासिल हुई. 2000 में जॉर्ज ऑरवेल को मिलेनियम लेखक घोषित किया गया था, जिसके बाद विदेशी समाचार पत्र गार्जियन के साउथ एशिया संवाददाता ल्यूक हार्डिंग व छायाकार लेंसी एडेरियो मोतिहारी आए थे और जॉर्ज ऑरवेल की जन्म स्थली की दुदर्शा से अवगत हुए थे. बहरहाल, प्रशासन द्वारा इस कार्य में तेज़ी लाने की पहल को पूर्वी चंपारण की जनता ने सराहा है.

feedback@chauthiduniya.com

हम मकान नहीं घर बनाते हैं...

Yash Raj Enterprises Pvt. Ltd.

excellence in Real Estate...

An ISO 9001:2008 Certified Company

- PROMOTER
- DEVELOPER
- MARKETER
- SERVICE PROVIDER

9234601786, 9234602786, 9234603786

E-mail: yashraj221@gmail.com

Website : www.yashrajenterprises.com

K. Singh

VISION CLASSES

IIT-JEE

एक सपना

''पटना को कोटा बनाने का''

विजन क्लासेज की स्थापना कमेस्ट्री के प्रख्यात शिक्षक श्री के. सिंह द्वारा सन् 2008 में की गई। सन् 2009 में आईआईटी–जेईई में अपार सफलता के पश्चात्, यह संस्थान विद्यार्थियों की पहली पसंद बन गया। जिस संकल्प के साथ संस्थान की नींव रखी गयी थी, उसका उद्देश्य विद्यार्थियों का कोटा की ओर पलायन को रोकना और राष्ट्रस्तरीय गुणवत्ता को पटना में मुहैया करना था जो विजन क्लासेज का स्लोगन से स्पष्ट जाहिर होता है – एक सपना पटना को कोटा बनाना

2008–09 तक जहां कोटा के सर्वोच्च कोचिंग संस्थान 80 प्रतिशत से कम प्रतिशत पाने वाले छात्रों का दाखिला नहीं लेते थे वहीं अब बिहारी विद्यार्थियों के लिए लुभावने विज्ञापन देकर 60 प्रतिशत वाले छात्रों का दाखिला नहीं लेते थे। वहीं अब बिहारी विद्यार्थियों के लिए लुभावने विज्ञापन देकर 60 प्रतिशत वाले छात्रों का भी दाखिला ले रहे हैं। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि उन संस्थानों में पहुंचने वाले छात्रों की सांख्या या तो घट रही है अथवा वह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, जो कहीं न कहीं उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करेगा। यह इस बात का द्योतक है कि बिहारी छात्रों का कोटा की तरफ पलायन में भारी कमी आयी है। विजन क्लासेज की अपार सफलता एवं हजारों छात्रों का विश्वास, इशारा करता है कि परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस पलायनवाद पर अंकुश लगाने में विजन क्लासेज का भी भारी योगदान है।

विजन क्लासेज के सफलतम् कोचिंग होने के पीछे छुपे रहस्य को हम जग जाहिर करके आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे।

संस्थान के प्रोमोटर श्री के. सिंह अपने कोटा में अध्यापन काल के दौरान, वहां के पैर्टन का गहन अवलोकन करने के पश्चात कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे और संकल्प लिया कि, पटना में ऐसे संस्थान का होना अति आवश्यक है जो आईआईटी–जेईई एवं अन्य इंजिनियरिंग प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों को सफलता दिलाने में सक्षम हो, साथ ही शुल्क भी कम हो ताकि देहाती क्षेत्र के अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए प्रथम जरूरत तो यह थी कि राष्ट्र स्तर के वैसे शिक्षकों को पटना लाना जो इस सपने को पुरा कर सकें। यह कोई आसान काम न था परन्तु श्री के सिंह की कोचिंग दुनिया में लोकप्रियता के कारण कई नामी गिरामी संस्थाओं के शिक्षकों ने इस मिशन में सहभागी बनने की इच्छा जाहिर की अपने आपको पटना में रिलोकेट किया। इसमें बिहार के बदलते माहौल का भी योगदान रहा।

चूंकि सभी शिक्षक हमारे साथ स्थायी रूप से जुड़े हैं जिस कारण संस्था का एकीकरण एवं समुचित विकास हुआ साथ ही अभिभावकों एवं विद्यार्थियों का विश्वास अर्जित हुआ।

प्रदेश के बाहर के. सिंह विजन क्लासेज की प्रतिष्ठा बढ़ी

बिहार के विद्यार्थियों के बीच ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर भी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में के.सिंह विजन क्लासेज केवल चर्चित न होकर एक अतिप्रतिष्ठित संस्थान के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रदेश के बाहर कोटा, दिल्ली, हैदराबाद आदि नगरों के विशिष्ट शिक्षकगण भी अब बिहार में पढ़ाने को इच्छुक हैं। यह बिहार में विकसित हो रहे कोचिंग संस्थानों के भविष्य के लिए शुभ संकते हैं, विद्यार्थियों के अतिलोकप्रिय शिक्षाविद श्री के. सिंह द्वारा एक संकल्प ''एक सपना पटना को कोटा बनाना'' के साथ किया गया शुरूआती दौर में हमें तीन पहलुओं से रू-ब-रू होना पड़ा। सर्वप्रथम हमें अच्छे शिक्षकों को अपने संस्थान में जोड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। दूसरा एक राष्ट्रीय स्तर का वातावरण विकसित भी करना पड़ा, ताकि दूर-दराज से आये शिक्षकों को निर्भिक एवं सुरक्षित माहौल मुहैया कराया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद बिहार के परिवेश में अकाल्पनिक बदलाव आया एवं बिहार भी विकास की राह पर चल पड़ा। इस बदलाव से प्रभावित होकर अच्छे शिक्षकण, हमारे संस्थान से जुड़ने को तैयार हुए। के.सिंह विजन क्लासेज माननीय मुख्यमंत्री जी को विद्यार्थियों, उनके माता-पिता शिक्षकण एवं संस्थान प्रबंधन समूह की ओर से ग्रान्ड सैलूट देता है। तीसरा पहलू, शिक्षा शुल्क से कटौती की थी, यह इसलिए सम्भव हो पाया क्योंकि हमारे निदेशक का विश्वास है कि - ''एक मनुष्य का, मनुष्य के लिए मनुष्य होने का कर्ज चुकाना सबसे बड़ा धर्म है।

विजन क्लासेस क्यों

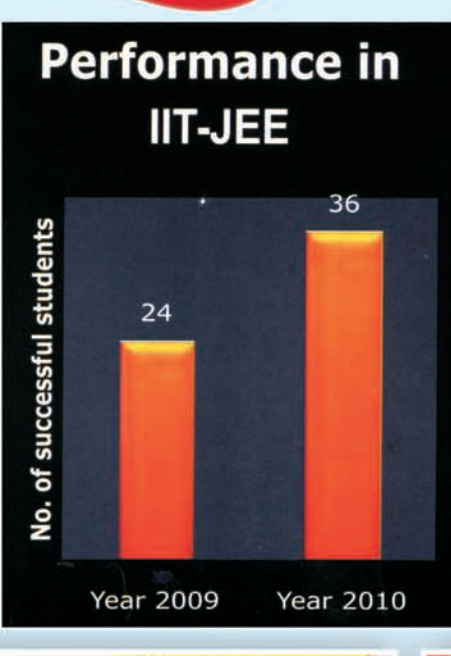

के सिंह विजन क्लासेज बिहार में आई आई टी जे ई ई की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के बीच सरस्वती मंदिर के रूप में प्रख्यात है।
आपके बच्चों के उज्जवल,गुणात्मक एवं प्रशंसनीय भविष्य के लिए निर्देशक से लेकर पिऊन तक पूर्ण रूप से समर्पित है।

अगर मुझे पैसा कमाने की ललक होती तो मैं अपने संस्थान की स्थापना बिहार के बाहर किसी बड़े शहर में करता, क्योंकि जो संस्थान देश के बड़े शहरों में चल रहे हैं, वहां छात्रों को एक मोटी रकम चुकानी पड़ती जो निम्न एवं मध्यवर्गीय अभिभावाकों के लिए एक बड़ी रकम होती है। यह सम्भव नहीं हो पाता है कि एक गरीब अभिभावक ऐसे संस्थानों में अपने बच्चों को भेज पाएं साथ ही विद्यार्थी अपने घरेलू वातावरण एवं अभिभावक कि निगरानी से भी वंचित रह जाते हैं जिस कारण आई आई टी- जे ई ई में भी उनका परिणाम बहुत अच्छा नहीं हो पाता है।

यह जो कथित बड़े संस्थान हैं वह भी अपने जीवन काल में दो से तीन बार विघटित हो जाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप जितने भी अनुभवी एवं सफल शिक्षक हैं, उनका पलायन एक आम बात है। मैं भी इस विघटन का अंग हूं। इस वजह से इन नामी गिरामी संस्थानों मे अच्छे शिक्षकों का जमावड़ा जरा मुश्किल होता है।

मैंने इस संस्थान की स्थापना सन् 2008 में कुछ चुनिंदा शिक्षकों के साथ किया यह सभी शिक्षक बड़े संस्थानों से विघटित थे और उन्होंने सैकड़ों विद्यार्थियों को आईआईटीयन बनाये हैं।

मैंने जब भी ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया जो कि मैं अक्सर समाज सेवा इत्यादि के लिए किया करता हूं, मैंने देखा है कि हमारे बिहारी गरीब बच्चों के आंखों में आईआईटीयन बनने का सपना है ,परन्तु सुविधाओं का अभाव में वह साकार नहीं हो पाते, क्योंकि बड़े शहरों के संस्थान उनकी पहुंच से बाहर हैं। मैं भी निःशुल्क शिक्षा तो नहीं दे सकता क्योंकि जो शिक्षकगण मेरे संस्थान से जुड़े हैं, जो विद्यार्थियों को सफलता दिलाने में सक्षम रहे हैं, उन्हें एक हैन्डसम रकम सैलरी के रूप में चुकानी पड़ती है। शुरूआती दौर में मुझे तीन पहलुओं से रूबरू होना पड़ा। सर्वप्रथम मुझे अच्छे शिक्षकों को अपने संस्थान में जोड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। दूसरा एक राष्ट्रीय स्तर का वातावरण विकसित भी करना पड़ा ताकि दूर-दराज से आये शिक्षकों को निर्भिक एवं सुरक्षित माहौल मुहैया कराया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद बिहार के परिवेश में अकल्पनीय बदलाव आया एवं बिहार भी विकास की राह पर चल पड़ा। इस बदलाव से प्रभावित होकर अच्छे शिक्षकगण मेरे संस्थान से जुड़ने को तैयार हुए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विद्यार्थियों उनके माता-पिता, शिक्षकगण एवं संस्थान प्रबंधन समूह की ओर से सादर धन्यवाद देता हूं। तीसरा पहलु, शिक्षा शुल्क में कटौती की थी, यह इसलिए सम्भव हो पाया क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि एक मनुष्य का मनुष्य के लिए, मनुष्य होने का कर्ज चुकाना सबसे बड़ा धर्म है।

आज, यह मैं अति गर्व के साथ कह सकता हूं कि के.सिंह विजन क्लासेज एक अति सफल एवं प्रगतिशील संस्थान है, इसकी मांग न केवल विद्यार्थियों के बीच बल्कि देश भर के शिक्षकों में भी है। अन्य राज्यों के विद्यार्थी एवं अभिभावक भी के. सिंह विजन क्लासेज के केन्द्रों की मांग अपने शहर के लिए करते हैं क्योंकि हमारे संस्थान के अनुशासन, वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति, दबाव रहित शिक्षा, मनोजंन पूर्ण आईआईटी-जे ईई से बेहतर परिणाम से प्रभावित हैं।

के. सिंह (निदेशक)

मंथन

कंकड़बाग सेन्टर

कुंवर सिंह (एकेडमिक हेड)

बोरिंग रोड सेन्टर

Head Office: : In front of gate No. 2, Kendriya Vidayalaya, Kankarbagh, Patna-20, Ph: 0612-3265424, 6567270, 9204324122

Branch Office: : Jai Kamla plaza, near lalita Hotel, East Boaring Canal Road, Patna-01, Ph : 0612-3265423, 2532441

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 28 मार्च–03 अप्रैल 2011

www.chauthiduniya.com

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना

शीर्ष नेताओं ने निधि ख़र्च नहीं की

आख़िर हमारे सांसद यह क्यों नहीं समझ रहे हैं कि इस योजना का उद्देश्य बेरोज़गारों को काम दिलाना है. अगर वे काम नहीं कराएंगे और अपनी निधि ख़र्च नहीं करेंगे तो बेरोज़गारों का क्या होगा. हमने केवल महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना पर इन सांसदों की राजनीतिक सोच व ग़रीबों के हित की बात करने की वास्तविकता जनता के सामने रखने का प्रयास किया है.

डॉ. सुनील कौशिक

सत्ता पक्ष द्वारा विकास कार्यों की डींग हांकना, विपक्षी दलों द्वारा विकास के नाम पर सरकार को कठघरे में खड़ा करना, चुनाव के समय ग़रीबों व असहायों के हितों के बड़े-बड़े लुभावने भाषण व नारे देकर जनता को बेवकूफ़ बनाना सभी दलों को बख़ूबी आता है. अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती द्वारा सभी ज़िलों में दौरे कर विकास की समीक्षा की गई. इसी को ध्यान में रखकर सभी दल ग़रीबों के हितों की बात कर रहे हैं. सांसद जनपदीय सतर्कता निगरानी समिति के अध्यक्ष होते हैं. विकास से संबंधित समस्त परियोजनाओं की निगरानी रखना सांसदों का दायित्व होता है, लेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना केंद्र सरकार की योजना है इसलिए सांसदों की ज़िम्मेदारी इस योजना पर अधिक ध्यान देने की हो जाती है.

यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के क्षेत्र में कुल 36837 कार्यों में से सिर्फ़ 17 ही पूरे हो पाए. भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह तो कुल 3128 कार्यों में से एक भी काम नहीं करा पाए. विकास के नाम पर हरित प्रदेश की मांग करने वाले राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजित सिंह कुल 2331 में से सिर्फ़ एक ही काम करा पाए. समाजवादी पार्टी सुप्रीमो व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी कुल 12905 कार्यों में से केवल पांच काम ही करा पाए. इन आंकड़ों से यह साबित हो जाता है कि ये नेता जनता के कितने हितैषी हैं. सोनिया गांधी, सलमान ख़ुर्शीद, पी. एल. पूनिया, राज बब्बर ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं. इसलिए इस योजना की ज़िम्मेदारी अन्य सांसदों की अपेक्षा उनकी अधिक हो जाती है, क्योंकि यह योजना इनकी सरकार की उपलब्धि है. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथसिंह, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह जैसे विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं के जनपदों में जब इस योजना की स्थिति इतनी ख़राब है तो अन्य सामान्य सांसदों के क्षेत्र में स्थिति कितनी भयानक होगी, समझा जा सकता है. ऐसी स्थिति में राजनेताओं द्वारा विकास की बात करना वास्तव में बेमानी है. ये वे नेता हैं जिनके नाम पर जनता आंख बंद करके विश्वास कर लेती है, ऐसे सांसदों के क्षेत्रों में ग़ौर करें कि वे वास्तव में ग़रीबों के हितों के बारे में कितना गंभीरतापूर्वक सोच रहे हैं. उनके क्षेत्रों में ग़रीबों के लाभ के लिए करोड़ों रुपये मौजूद हैं, लेकिन वे ख़र्च नहीं करा पा रहे हैं. राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून 25 अगस्त 2005 को पारित हुआ जिसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना नाम दे दिया गया. इस क़ानून में ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल वयस्क को 100 दिनों की रोज़गार गारंटी दी गई है. भारत सरकार इस योजना को राज्य सरकारों के साथ मिलकर क्रियान्वयन कर रही है. यह क़ानून ग़रीबी रेखा से नीचे रह रहे अर्द्ध या अकुशल ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया है. यह देश में अमीर और ग़रीब के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास है. इसमें काम करने वाले लोगों में एक तिहाई संख्या महिलाओं की होनी चाहिए. लोगों को रोज़गार पांच किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध कराया जाएगा. यदि कार्य पांच किलोमीटर के दायरे से बाहर होता है तो मज़दूर को अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा. वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान 200 ज़िलों और वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान 130 ज़िलों में योजना की शुरुआत हुई. अप्रैल 2008 में उपराज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सभी 614 ज़िलों, 6096 ब्लॉकों और 2.65 ग्राम पंचायतों में विस्तार किया गया. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना के लिए ग्रामीण परिवारों के वे सभी वयस्क आवेदन कर सकते हैं जिनके पास जॉब कार्ड है. एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को 100 दिनों तक रोज़गार मिलने की गारंटी होगी और इस परिवार के वयस्क सदस्यों के बीच विभाजित किया जाएगा. कार्य की अवधि लगातार 14 दिन होगी, लेकिन सप्ताह में 6 दिन से अधिक नहीं होगी. आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर या कार्य की मांग के दिन से आवेदक को रोज़गार प्रदान किया जाएगा. राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम को तैयार करना और उसे कार्यान्वित करने को एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा गया. इसका आधार अधिकार और मांग को बनाया गया है जिसके कारण यह पूर्व के इसी तरह के कार्यक्रमों से भिन्न हो गया है. अधिनियम के बेजोड़ पहलुओं में समयबध्द रोज़गार गारंटी और 15 दिन के भीतर मज़दूरी का भुगतान आदि शामिल हैं. इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे रोज़गार प्रदान करने में कोताही न बरतें, क्योंकि रोज़गार प्रदान करने के व्यय का 90 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करती है. इसके अतिरिक्त इस बात पर भी बल दिया जाता है कि रोज़गार शारीरिक श्रम आधारित हो. मगर इस योजना का पर्याप्त लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सियासी दलों के प्रमुख नेता इसे लेकर गंभीर नहीं हैं. जिस समय यह योजना प्रारंभ हुई थी, उस समय इसके अच्छे नतीजे सामने आए थे. आशा व्यक्त की जा रही थी कि अब यह योजना देश के ग़रीबों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी. काम की तलाश में प्रदेश के मज़दूरों का दूसरे राज्यों में जाना कम हो जाएगा, क्योंकि यहां से लाखों लोग रोज़गार के लिए हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में जाते हैं. इस योजना को लेकर गांवों में ख़ुशी की लहर देखने को मिल रही थी, किंतु इस योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया. कहीं लोगों को काम नहीं मिला तो कहीं उन्हें पारिश्रमिक नहीं मिला. आख़िर वे यह क्यों नहीं समझ रहे हैं कि इस योजना का उद्देश्य बेरोज़गारों को काम दिलाना है. अगर वे काम नहीं कराएंगे और अपनी निधि ख़र्च नहीं करेंगे तो बेरोज़गारों का क्या होगा. ऐसा नहीं है कि सरकार या सांसदों के पास पैसा नहीं है. उनके पास पर्याप्त पैसा है इसके बावजूद लापरवाही बरती जा रही है. हमने केवल महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना पर इन सांसदों की राजनीतिक सोच व ग़रीबों के हित की बात करने की वास्तविकता जनता के सामने रखने का प्रयास किया है.

feedback@chauthiduniya.com

इस योजना को लेकर आशा व्यक्त की जा रही थी कि यह योजना ग़रीबों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी. काम की तलाश में मज़दूरों का दूसरे राज्यों में जाना कम हो जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया.

रायबरेली

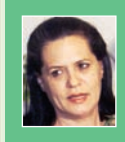

सोनिया गांधी
कांग्रेस

कुल निधि : 124.23 करोड़ रुपये
व्यय : 61.21 करोड़ रुपये
कुल कार्य : 36837
पूर्ण कार्य : 17

बाराबंकी

पी.एल.पूनिया
कांग्रेस

कुल निधि : 98.05 करोड़ रुपये
व्यय : 70.13 करोड़ रुपये
कुल कार्य : 35823
पूर्ण कार्य : 2

पीलीभीत

वरुण गांधी
भारतीय जनता पार्टी

कुल निधि : 58.32 करोड़ रुपये
व्यय : 40.32, करोड़ रुपये
कुल कार्य : 17761
पूर्ण कार्य : 1

ग़ाज़ियाबाद

राजनाथ सिंह
भारतीय जनता पार्टी

कुल निधि : 5.47 करोड़ रुपये
व्यय : 2.8 करोड़ रुपये
कुल कार्य : 3128
पूर्ण कार्य : 0

लखनऊ

लालजी टंडन
भारतीय जनता पार्टी

कुल निधि : 73.11 करोड़ रुपये
व्यय : 27.96 करोड़ रुपये
कुल कार्य : 16030
पूर्ण कार्य : 1

बाग़पत

अजित सिंह
राष्ट्रीय लोकदल

कुल निधि : 9.4 करोड़ रुपये
व्यय : 2.53 करोड़ रुपये
कुल कार्य : 2331
पूर्ण कार्य : 1

मैनपुरी

मुलायम सिंह यादव
समाजवादी पार्टी

कुल निधि : 47.35 करोड़ रुपये
व्यय : 29.74 करोड़ रुपये
कुल कार्य 12905
पूर्ण कार्य : 5

कन्नौज

अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी

कुल निधि : 36.63 करोड़ रुपये
व्यय : 15.02 करोड़ रुपये
कुल कार्य : 10064
पूर्ण कार्य : 5

फ़िरोज़ाबाद

राज बब्बर
कांग्रेस

कुल निधि : 36.00 करोड़ रुपये
व्यय : 17.11 करोड़ रुपये
कुल कार्य : 8951
पूर्ण कार्य : 450

एटा

कल्याण सिंह
जन क्रांति पार्टी

कुल निधि : 67.53 करोड़ रुपये
व्यय : 27.05 करोड़ रुपये
कुल कार्य : 13625
पूर्ण कार्य : 327

फर्रुख़ाबाद

सलमान ख़ुर्शीद
कांग्रेस

कुल निधि : 48.38 करोड़ रुपये
व्यय : 18.43 करोड़ रुपये
कुल कार्य : 8906
पूर्ण कार्य : 20

उत्तर प्रदेश में आजकल भू-माफ़िया काफ़ी बड़े स्तर पर सक्रिय हैं. उन्हें राजनीति में पैठ रखने वाले बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है. ज़मीन की रजिस्ट्री में यहां नियम क़ानून का उल्लंघन आम बात है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मानवाधिकार के उल्लंघन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि राजधानी दिल्ली दूसरे स्थान पर.

उत्तर प्रदेश
सियासी दलों की छटपटाहट

मायावती मुलायम सिंह यादव अमर सिंह

उत्तर प्रदेश में इन दिनों सभी राजनीतिक दल किसी न किसी बहाने शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे हैं. [illegible]

कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं हैं. उसके पास तो सभी नेता हैं. हर नेता के पास अपने क्षेत्र के चुनावी आंकड़े और समीकरणों का गणित ही नहीं, बल्कि प्रदेश के चुनावों का भी समीकरण और गणित मौजूद है. प्रत्याशी बन जाने पर चंदा उगाही का मौक़ा तो मिलेगा.

[illegible]

आंदोलन में इनकी अच्छी ख़ासी पिटाई हो चुकी थी, लेकिन मुलायम सिंह जानते हैं कि चैलेंज न स्वीकारने का मतलब पार्टी का रसातल में चले जाना होगा सो उन्होंने दोबारा आंदोलन छेड़ दिया. भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी जिजीविषा दिखाने के लिए विभिन्न समस्याओं को लेकर हर ज़िले में ज्ञापन देने का सिलसिला शुरू कर दिया और इसके बाद राजभवन मार्च का आयोजन रख दिया. इसमें प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही के नेतृत्व में अपने सभी मेयर, निकाय अध्यक्ष और स्थानीय निकायों से जुड़े प्रतिनिधियों को साथ लेकर राजभवन मार्च किया. इस मार्च का मुख्य उद्देश्य नगर निगम के चुनावों में अप्रत्यक्ष निर्वाचन का विरोध करना था. पार्टी ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधेयक को तत्काल वापस लेने की मांग की. पार्टी ने ज्ञापन में यह भी मांग की कि नगर निगम के पार्षदों के चुनाव भी दलीय आधार पर कराए जाएं. कांग्रेस आंदोलनों में तो तभी उतरेगी जब इसके पास कार्यकर्ता होंगे. कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं हैं. उसके पास तो सभी नेता हैं. हर नेता के पास अपने क्षेत्र के चुनावी आंकड़े और समीकरणों का गणित ही नहीं, बल्कि प्रदेश के चुनावों का भी समीकरण और गणित मौजूद है यानी हर नेता टिकट का दावेदार है. प्रत्याशी बन जाने पर क्षेत्र के उद्यमियों से चंदा उगाही का मौक़ा तो मिलेगा. यदि भाग्य ने साथ नहीं दिया तो इतिहास में नाम तो लिखा ही जाएगा. सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र क़ायम नहीं है. इसका मुख्य कारण है यह है टिकट वितरण के समय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होना. हर राजनीतिक दल का चुनावों के समय टिकट बांटने का एक ही पैमाना होता है कि प्रत्याशी में सबसे पहले तो जीत की संभावना सबसे प्रबल हो, दूसरे नंबर पर इसका आर्थिक दृष्टि से गांठ का पूरा होना बहुत ही ज़रूरी है. इस कारण अक्सर ऐसा होता है कि एक कार्यकर्ता जो अपने क्षेत्र में काम करके जनता में पैठ बनाता है, लेकिन ऐन समय पर पार्टी इस क्षेत्र में कोई दूसरा बाहरी आदमी प्रत्याशी बनाकर कार्यकर्ताओं पर थोप देती है. फिर कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे पूरी कर्मठता, तन्मयता और ईमानदारी से काम करके इस थोपे गए प्रत्याशी को जितवाएं. सोचिए यह इस कार्यकर्ता के लिए कितनी पीड़ा की बात होगी.

यही वजह है कि आजकल हर पार्टी का कार्यकर्ता राजनीति को व्यापार मानकर चल रहा है. वह यह मानकर चलता है कि राजनीति में किया गया इसका इंवेस्टमेंट बेकार नहीं जाएगा. अपनी पार्टी में इसकी हैसियत और क्षेत्र में पकड़ का अन्य पार्टियों में भी ध्यान रखा जाता है. दूसरी पार्टियां उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए इसी अनुपात में इन कार्यकर्ताओं को प्रलोभन देती हैं. विचारधारा वाली बात की तो अब कोई अहमियत रह ही नहीं गई है.

डॉ. सुनील कौशिक
feedback@chauthiduniya.com

हरित प्रदेश के लिए जनांदोलन की दरकार

केपी त्रिपाठी

विधानसभा चुनाव से ऐन पहले राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी अजित सिंह ने फिर से हरित प्रदेश निर्माण का जिन्न बोतल से निकाल दिया. इस पृथक राज्य की मांग के अपने कई राजनीतिक निहितार्थ हैं, लेकिन इसके सामाजिक और आर्थिक सरोकारों से भी इंकार नहीं किया जा सकता. यही कारण है कि लंबे समय से अलग हरित प्रदेश की मांग को लेकर आंदोलन कर रही हरित प्रदेश निर्माण संघर्ष समिति ने मौक़े की नज़ाकत को देखते हुए एक बार फिर से माहौल को गरमाने के लिए गत 13 जनवरी को एक सम्मेलन आयोजित कर डाला. सम्मेलन में ख़ुद राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह आए और ठंडे पड़े आंदोलन में स्फूर्ति भरने की कोशिश कर गए. इस बार इस सम्मेलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 ज़िलों के बार एसोसिएशन व व्यापार संघ के पदाधिकारी भी पहुंचे और आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की. संघर्ष समिति के सचिव सोहनवीर सिंह तोमर ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण की मांग बहुत पुरानी है. चौधरी अजित सिंह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हरित प्रदेश चाहिए तो दिलों में तेलंगाना के लोगों जैसी आग पैदा करनी होगी. समाज के हर तबक़े में हरित प्रदेश संघर्ष समिति के आनुशांगिक संगठन खड़े करने होंगे और जनजागरण की कमान नौजवानों के हाथों में देनी होगी. इस बार चौधरी साहब के तेवरों में जो तीखापन देखने को मिला उससे लगा कि अब आंदोलन ज़ोर पकड़ेगा. केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए अजित सिंह ने कहा कि दोनों सरकारों की मंशा ठीक नहीं है. मायावती पीएम को चिट्ठी लिखती हैं, पर उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर नहीं भेजा. केंद्र सरकार ने भी बयानबाज़ी के सिवा कोई पहल नहीं की.

तेलंगाना के बहाने ही सही अलग प्रदेशों की मांग का पिटारा एक बार फिर नए सिरे से खुल गया है. वर्ष 1994 में कांग्रेस द्वारा पश्चिम उत्तर प्रदेश को पृथक कर हरित प्रदेश बनाने की कल्पना आज तक साकार नहीं हो पाई. पश्चिम उत्तर प्रदेश आज भी पृथक राज्य के लिए छटपटा रहा है. मांग के 17 सालों बाद भी यह आंदोलन तेज़ धार नहीं पकड़ सका और न ही यह जनआंदोलन में परिवर्तित हो सका, जबकि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्य पहले बन गए. इसे महज़ इत्तेफ़ाक़ कह सकते हैं या फिर जनआंदोलनों के आगे केंद्र का झुकाव. हरित प्रदेश की दबी चिंगारी को हवा देने का काम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को इस आशय का पत्र लिखकर किया था कि उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांट दिया जाना चाहिए. हालांकि इसके पीछे राजनीति साफ़ नज़र आ रही थी. यदि मुख्यमंत्री मायावती उत्तर प्रदेश का बंटवारा करना ही चाहती है तो उन्हें केंद्र को पत्र लिखने के बजाय उत्तर प्रदेश विधानसभा में बंटवारे का प्रस्ताव पारित कराकर अपनी ईमानदारी का सबूत देना चाहिए था. मायावती पूर्ण बहुमत में हैं. इसलिए प्रस्ताव पारित होने में भी कोई अड़चन नहीं आने वाली है. हालांकि अजित सिंह समय-समय पर हरित प्रदेश की मांग को उठाते रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि वे हरित प्रदेश की मांग के प्रति ईमानदार हैं. मेरठ में हरित प्रदेश निर्माण समिति का गठन किया गया है. इस बैनर के तले 21 दिसंबर को हरित प्रदेश निर्माण के लिए एक विचार-विमर्श गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें हरित प्रदेश बनाने के लिए आंदोलन चलाने की मांग की गई. सवाल यह है कि क्या हरित प्रदेश का निर्माण करने का संकल्प लेने वाले ईमानदारी से इसे आगे बढ़ा पाए. विधानसभा 2007 का चुनाव भी राष्ट्रीय लोकदल इसी मुद्दे पर लड़ा था, लेकिन विधायकों और सांसदों में एकता का अभाव देखने को मिला. तेलंगाना में विधायकों और सांसदों ने एकमत होकर इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन यहां ऐसा होना संभव नहीं लगता. अन्य राजनीतिक दल अजित सिंह को हरित प्रदेश का ब्रांड नेता मानने लगे हैं. अब तो सियासी हलक़ों में हरित प्रदेश की मांग को केवल चुनावी नारा माना जाने लगा है. जनता में भी अलग राज्य की मांग का वैसा जोश कभी नहीं दिखा जैसा कभी उत्तराखंड के लोगों में था. आम सभाओं में छोटे चौधरी यानी उनके सुपुत्र जयंत चौधरी इस मुद्दे को ज़रूर उठाते रहे हैं, लेकिन अपनी मजबूरियां गिनाने के साथ. हरित प्रदेश को लेकर पश्चिम में जो बेचैनी होनी चाहिए वह कभी नहीं दिखी. पिछले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने जब भारतीय जनता पार्टी से मित्रता की तो भी हरित प्रदेश के मुद्दे को अहमियत दी. चूंकि भारतीय जनता पार्टी भी छोटे राज्यों के गठन की हिमायती रही है. ख़ैर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी-राष्ट्रीय लोकदल की दोस्ती से कोई नया समीकरण नहीं बन पाया. साथ ही हरित प्रदेश मुद्दा भी मुरझाया रहा. इससे थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो भी हरित प्रदेश आंदोलन मात्र कुछ ज़िलों तक सिमट कर रह गया. जहां तक अन्य दलों की बात है तो वह इसे राष्ट्रीय लोकदल का सियासी हथियार कहकर अपना हाथ खींचते रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की मांग नई नहीं है. लंदन में सन 1931 में हुई एक गोलमेज़ कांफ्रेंस में उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की मांग की गई थी. इस कांफ्रेंस में कांग्रेस से महात्मा गांधी मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना और हिंदू महासभा के भाई परमानंद ने भाग लिया था. आज़ादी के बाद 1953 में राष्ट्रीय स्तर पर फ़ैज़ल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था. इस आयोग के सदस्यों में हृदयनाथ कुंजरू तथा के एम पनिक्कर थे. आयोग ने तेलंगाना, विदर्भ बिहार और उत्तर प्रदेश को बांटने की संस्तुति की थी. डॉ. भीमराव अंबेडकर ने फ़ैज़ल अली आयोग की सिफ़ारिशों के संदर्भ को लेकर प्रदेश को तीन भागों में बांटने का समर्थन किया था. 1977 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी छोटे राज्यों के निर्माण के लिए अपना समर्थन दिया था. सन 1978 में मोदीनगर के विधायक सोहनवीर सिंह तोमर ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के लिए सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था. प्रस्ताव पर चर्चा से पहले ही दुर्भाग्य से केंद्र ने बनारसीदास मंत्रिमंडल को भंग कर दिया था. इसी दौरान चौधरी चरणसिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भी किया था. यहां भी दुर्भाग्य से इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पार्टी की सरकार ही गिर गई थी.

हरित प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष और पूर्व विधायक सोहनवीर तोमर कहते हैं कि प्रदेश के राजस्व में 72 से 75 प्रतिशत का योगदान पश्चिम उत्तर की जनता करती है, जबकि यहां के विकास की दर मात्र 20 फ़ीसदी है. प्रदेश का इतना विशालकाय होना ही पश्चिम के विकास में पिछड़ने का मुख्य कारण है. राजधानी का इतना दूर होना पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत अन्याय है. देश के सात राज्यों उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के हाईकोर्ट राज्य के तीन सौ किलोमीटर से कम के दायरे में है. इलाहाबाद हाइकोर्ट से नज़दीक तो पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट की दूरी पर है. पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए अलग विकास निधि, लेकिन पश्चिमांचल के लिए कोई बजट नहीं है. पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर अलग राज्य होता तो योजना आयोग की नीति के अनुसार केंद्र से अधिक आर्थिक सहायता मिलती.

70,000 हज़ार वर्ग किलोमीटर में फैले पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क़रीब 5 करोड़ है. जिस हरित प्रदेश की मांग की जा रही है इसमें चार मंडल सहारनपुर, मेरठ आगरा, मुरादाबाद, बरेली के क़रीब 23 ज़िले शामिल हैं. इनमें ग़ाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, बाग़पत, मुजफ़्फ़रनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, जेपीनगर, रामपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, फ़िरोज़ाबाद, महामाया नगर, एटा, मैनपुरी, बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर. मेरठ को राजधानी बनाने का प्रस्ताव है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दोआब प्रदेश के नाम से बनाने की मांग 37 साल लड़ी जा रही है. जनक्रांति दल ने इसे 1973 में उठाया था. 1977 में जनक्रांति दल का नाम बदलकर दोआब प्रदेश संघर्ष समिति रख दिया गया. तब से लेकर आज तक समिति दोआब प्रदेश की लड़ाई को लड़ रही है. समिति के केंद्रीय अध्यक्ष सुभाष गोस्वामी और मुख्यालय महासचिव सुरेश नारायण कहते हैं कि अब तक जिसने भी प्रदेश विभाजन का मुद्दा उठाया वह व्यक्तिगत रहा है. हरित प्रदेश की मांग को लेकर राजनीतिक दल भी एक मत नहीं हो पाए. मंच पर एकसुर वाले नेताओं की ज़ुबान दिल्ली या लखनऊ पहुंचते ही हरित प्रदेश के नाम पर लड़खड़ाने लगती है. भाजपा के नागेंद्र नाथ कहते हैं जिस समय केंद्र में भाजपा सरकार थी, उस दौरान तीन नए राज्य अस्तित्व में आए. पार्टी प्रदेश विभाजन के कभी ख़िलाफ़ नहीं हुई, लेकिन हरित प्रदेश का जो परिसीमन है वह ग़लत है. कांग्रेसनीत केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन तो किया, लेकिन इससे आगे कोई बात नहीं बन पाई. कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी का कहना है कि कांग्रेस विकास की पक्षधर रही है. प्रदेश सरकार विधानसभा से प्रस्ताव पास कराके केंद्र को भेजे तभी विचार होगा. समाजवादी पार्टी हमेशा से हरित प्रदेश के ख़िलाफ़ रही है. मुलायम सिंह कभी इसके पक्षधर नहीं रहे. बहुजन समाजपार्टी को भी हरित प्रदेश मुद्दे से कभी कोई सरोकार नहीं रहा. मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती ने इस मुद्दे से पीछा छुड़ाने के लिए गेंद केंद्र के पाले में डाल दी. पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी और सांसद बाबू मुनकाद अली कहते हैं कि बहन जी ने केंद्र को पत्र भेजकर राज्य के तीन टुकड़े करने की मांग की है. भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हरित प्रदेश अब व्यक्ति विशेष का मुद्दा बनकर रह गया है. चुनाव के दौरान ही अजित सिंह को हरित प्रदेश की याद आता है. भारतीय किसान यूनियन हरित प्रदेश के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इससे आपसी झगड़े बढ़ेंगे. अखंड हिंदुस्तान मोर्चा की संयोजिका चेतना शर्मा कहती हैं कि हरित प्रदेश के निर्माण से यह प्रदेश मिनी पाकिस्तान में बदल जाएगा. आतंकवाद बढ़ेगा और देश की एकता अखंडता को ख़तरा उत्पन्न होगा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण युवा मोर्चा के अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेंद्र शर्मा का कहना है कि प्रदेश बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि बड़ा प्रदेश होने से इस क्षेत्र का विकास रुक गया है, जबकि यह क्षेत्र सर्वाधिक साधन संपन्न है. मेरठ प्रदेश स्थापना मंच संयोजक नरेंद्र खोडावाला का कहना है कि हम हरित प्रदेश नहीं मेरठ प्रदेश की बात कर रहे हैं. मेरठ प्रदेश संघर्ष समिति कोई राजनीतिक संगठन नहीं है. हरित प्रदेश को अजित सिंह ने अपना राजनीतिक हथियार बना लिया है. इसलिए अन्य दल इससे नहीं जुड़ सकें. पश्चिम उत्तर प्रदेश बेंच स्थापना समिति के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह धामा कहते हैं कि प्रदेश का बंटवारा होने से इस क्षेत्र का विकास होगा. अगर राजनीतिक कारणों से हरित प्रदेश नहीं बन सकता तो इसे दिल्ली प्रदेश में शामिल कर दें.

feedback@chauthiduniya.com

मांग तारीख़ों के आईने में

- वर्ष 1930 में लंदन गोलमेज़ कांफ्रेंस में हिंदू महासभा के प्रतिनिधि भाई परमानंद ने संयुक्त प्रदेश के बंटवारे की मांग की.
- डॉ. बीआर अंबेडकर ने भी पश्चिम ज़िलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने का सुझाव दिया था. 1952 में कांधला से विधायक रहे श्रीचंद पंवार ने विधानसभा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग बनाने की मांग की थी.
- 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य केएम पाणिकर ने उत्तर प्रदेश बंटवारे की संस्तुति की थी.
- 1973 में जनता पार्टी के घोषणा पत्र में छोटे राज्यों के गठन की बात कही गई थी.
- 1977 में बनी दोआब प्रदेश संघर्ष अब तक बड़े राज्यों का विभाजन करके देश को 100 प्रदेश में बांटने की लड़ाई लड़ रही है.
- 1978 में विधायक सोहनवीर सिंह तोमर ने विधानसभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा था.
- 2000 में इस मुद्दे को राष्ट्रीय लोकदल ने क़ब्ज़ा लिया और तब से लगातार उठाता रहा है.
- 2009 में मुख्यमंत्री मायावती ने प्रदेश विभाजन के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा.

हाईकोर्ट बेंच भी न मिल सकी

मेरठ, मुजफ़्फ़रनगर, सहारनपुर और बिजनौर की जनता को न्याय के लिए क़रीब 700 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, तब कहीं जाकर वे अपनी बात अदालत तक पहुंचा पाते हैं. पश्चिम में हाईकोर्ट बेंच की मांग 1955 से चली आ रही है. तत्कालीन मुख्यमंत्री संपूर्णानंद के कार्यकाल में उठी मांग आज मायावती के शासनकाल तक जस की तस पड़ी हुई हैं. इस दौरान 29 मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया. आंदोलन हुए, लेकिन कोई समाधान न निकला. इतना ही नहीं सन् 1981 से लगातार सप्ताह के हर शनिवार को पश्चिम की सभी अदालतों में हड़ताल होती आ रही है. नारायण दत्त तिवारी और राजनाथ सिंह के शासनकाल में भी प्रस्ताव केंद्र को भेजे गए, लेकिन इसकी मंज़ूरी नहीं मिल पाई. देश की कुल 21 हाईकोर्ट में 49,50000 मुक़दमें चल रहे हैं. इनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में 16,00000 मुक़दमें हैं यानी एक तिहाई से अधिक. उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त एकमात्र खंडपीठ लखनऊ में स्थापित है.

इलाहाबाद के जनप्रतिनिधियों में अमिताभ बच्चन, मुरली मनोहर जोशी, केशरी नाथ त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे क़द्दावर नेता पश्चिम में बेंच की मांग में रोड़ा बनते रहे, जबकि राष्ट्रपति से लेकर क़ानून मंत्री, चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया से लेकर चीफ़ जस्टिस ऑफ़ हाईकोर्ट तक पश्चिम में बेंच की मांग को जायज़ ठहरा चुके हैं.

रजिस्ट्रार कार्यालय का काला कारनामा

अरविंद त्रिपाठी

उत्तर प्रदेश में आजकल भू-माफ़िया सक्रिय है. इसमें सरकार के आला अधिकारी भी उसका साथ दे रहे हैं. खुलेआम ऊपर तक देना होता है, का नारा आजकल वे अधिकारी भी लगाते हुए मिल जाते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा माना जाता है. स्थिति यह है कि प्रदेश में नियम-क़ायदों को ताक़ पर रखकर रजिस्ट्रियां की जा रही हैं.

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, सुपरवाइज़री हाउसिंग सोसाइटी, लिमिटेड कानपुर को अनियमित तरीक़े से भूखंडों के क्रय-विक्रय पर अपर आवास आयुक्त/अपर निबंधक वी.डी. मिश्र द्वारा 4 जनवरी, 2011 को रोक लगा दी गई थी. ऐसा इस हाउसिंग सोसायटी में व्याप्त भ्रष्टाचार के उजागर हो जाने के बाद क़ानूनी स्थिति मजबूत करने के मद्देनज़र किया गया था. जांच में भूखंडों की ख़रीद-फरोख्त में गड़बड़ साबित होने के बाद ही ऐसा निर्णय लिया गया था. इस आदेश को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) कानपुर सहित समस्त संबंधित अधिकारियों को भेजा गया था.

प्रदेश सरकार के इस आदेश की अवहेलना करते हुए कानपुर रजिस्ट्रार कार्यालय में उक्त सोसायटी द्वारा 19 जनवरी, 2011 को सैनी शिक्षा संस्थान के मैनेजर सरदार मनमोहन सिंह के पक्ष में 0.215 हेक्टेयर ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी गई. यह ज़मीन लगभग एक बीघे से ज़्यादा है, जबकि उक्त सोसायटी का यह नियम है कि दो सौ वर्ग गज़ से अधिक का कोई भूखंड नहीं बेचा जाएगा. इस सोसायटी में लंबे समय से विवाद चल रहा था. यह बात सरदार मनमोहन सिंह को भी पता थी, पर कथित राजनीतिक और आपराधिक संपर्कों के बल पर उन्होंने ज़मीन का सौदा कर दिया. हद तो तब हो गई जब रजिस्ट्री में यह दर्शाया गया कि वे कृषि कार्यों के लिए भूमि को ले रहे हैं. ज़मीन का प्रायोगिक परिवर्तन भी उन्होंने लगे हाथ करा लिया. रजिस्ट्रार कार्यालय सहित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) आर.के. राम के संज्ञान में पूरा मामला था. इसके बावजूद रजिस्ट्री कर दी गई.

मनोज कुमार गौतम विमलेश दूबे

feedback@chauthiduniya.com

घपला शासन के संज्ञान में लाया जाएगा

इस पूरे मामले की जांच करने आए आवास अधिकारी विमलेश कुमार दुबे और आवास अधिकारी मनोज कुमार गौतम सोसायटी के मामलों से हतप्रभ रह गए हैं. उनका कहना है कि प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर किसी माफ़िया ने इस पूरी सोसायटी को हाइजैक कर लिया है. वर्तमान अध्यक्ष और सचिव तो सत्ताधारी राजनीतिक दल के दबंग मोहरे मात्र हैं. राजनीति में ऊंची पैठ रखने वाले आपराधिक छवि के नेताओं की रजिस्ट्रार कार्यालय में तूती बजती है और अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) आर.के.राम का उन्हें संरक्षण प्राप्त है. सभी मामले हमारे संज्ञान में है और उनकी जांच के बाद उन्हें दोषपूर्ण मानते हुए प्रदेश शासन के समक्ष रखा जाएगा और दोषियों के विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी. श्री गौतम कहते हैं कि नियम-क़ानून को ताक़ पर रखकर की गई इस रजिस्ट्री में समिति की निबंधित उपविधि की धारा 104 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है. साथ ही इस भूमि के विक्रय से प्राप्त रुपयों का समिति के अभिलेखों और बैंक खातों में उल्लेख भी नहीं किया गया है. अत: यह सीधे-सीधे गबन के मामले बनते हैं. उन्होंने रजिस्ट्री के अतिरिक्त इस सोसायटी की समिति द्वारा की गई अन्य सभी दस रजिस्ट्रियों को भी रद्द करने का फ़ैसला किया है. आवास अधिकारी मनोज कुमार गौतम कहते हैं कि सोसायटी ने इस क़ानून विरुद्ध किए गए काम से ख़ुद को पाक-साफ़ जताते हुए सचिव चंद्रमोहन कुरील को पद से हटा दिया है और इसके सभी ऐसे कार्यों से पल्ला झाड़ने का प्रयास किया है. दरअसल यह सचिव के किए गए घपले से बचने के लिए उठाया गया क़दम है, जो नाकाफ़ी है, परंतु इसी बीच इन दोनों आवास अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है और इसका कारण मामले की निष्पक्ष जांच करना बताया जा रहा है. बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त भू-माफ़िया ने स्वयं को फंसता देख दोनों अधिकारियों का स्थानांतरण करवा दिया. अंतत: वी. डी. मिश्र ने सोसायटी द्वारा की गई सभी रजिस्ट्रियों को रद्द करने का फ़ैसला किया है. सरकार के एक आला अधिकारी की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय कमेटी भी गठित की गई है.

मानवाधिकार उल्लंघन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे

प्रियंका ठाकुर

मानवाधिकार हनन पर लगाम कसने के मानवाधिकार आयोग कितने ही दावे करता हो, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले चार साल से मानवाधिकार हनन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर बना हुआ है. चौंकाने वाली बात यह है कि मानवाधिकार हनन के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं.

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में 1.63 लाख घटनाओं के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 16871 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है. वर्ष 2007 से 2010 के बीच देशभर में मानवाधिकार के 2273408 मामले पंजीकृत किए गए. इनमें 163627 मामले केवल उत्तर प्रदेश में ही पंजीकृत हुए. मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को 21 श्रेणियों में बांटा गया है. इनमें बच्चे, स्वास्थ्य, जेल, न्यायपालिका, माफ़िया, श्रम, अल्पसंख्यक, पुलिस, प्रदूषण एवं पर्यावरण, शरणार्थी, सेवा मामले, महिलाएं, अर्द्धसैनिक, रक्षा बल, आतंकवाद, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, किशोर, विदेशी नागरिक व दंगे शामिल हैं. उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार उल्लंघन के सर्वाधिक मामले पुलिस के ख़िलाफ़ हैं. ताज़ा प्रकरणों की बात करें तो मार्च 2011 के पहले सप्ताह में मेरठ में एक व्यक्ति को हफ्ते भर थाने में रखने और उत्पीड़न के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आरोपी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जांच करने के आदेश दिए हैं. हुआ ऐसा कि एक माह पूर्व शास्त्रीनगर स्थित एच ब्लॉक से आनंदित नर्सिंग होम के डॉक्टर की गाड़ी चुराने के आरोप में अलीगढ़ निवासी एक युवक पकड़ा गया था. आरोपी को नौचंदी पुलिस थाने ले आई.

आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने इसे छोड़ने के लिए सैटिंग का खेल शुरू कर दिया. इस चक्कर में इस युवक को हफ्ते भर थाने में ही रखा गया. इसी बीच युवक के घरवालों ने राज्यपाल और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इस मामले की शिकायत कर दी. बाद में बात न बनने पर तत्कालीन एस ओ सोहनवीर ने युवक को तमंचे रखने के आरोप में जेल भेज दिया. दूसरी ओर युवक के घरवालों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले में जांच के निर्देश दिए, जिसकी जांच सीओ सदर अतुल श्रीवास्तव को सौंपी गई है. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा बर्बरता से पीटे जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी किया है. लखनऊ में हुए समाजवादी पार्टी के आंदोलन के दौरान कथित रूप से कार्यकर्ताओं की पिटाई के मामले में आयोग ने कहा है कि पुलिस इसकी चार सप्ताह के अंदर रिपोर्ट पेश करे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इन मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लिया, जिनमें कथित रूप से कहा गया था कि लखनऊ में गत नौ मार्च को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं की पिटाई की. आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस जिस समय कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रही थी उस समय पुलिस महानिरीक्षक ने एक कार्यकर्ता को अपने पैरों से मसला. इस घटना में कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें भी आई हैं. आयोग ने कहा कि यदि मीडिया रिपोर्टें सही हैं तो ये राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती हैं. मीडिया रिपोर्टों की क्लीपिंग्स के साथ प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को एक नोटिस जारी करते हुए उनसे इस मामले में चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है.

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

आवास विकास परिषद 7200 सौ आवास बनाएगी

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद वित्तीय 2011-12 में 7200 नए आवास बनाएगी. नगरों में लोकनिर्माण विभाग बाइपास सड़कें बना रहा है. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिशद के अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी ने निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया. निदेशक मंडल ने 138.26 एकड़ भूमि के लिए बरेली-शाहजहांपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, बरेली के प्रस्ताव को अनुमोदित भी किया. बैठक में तय किया गया कि परिषद आवासों के अतिरिक्त निर्माण के लिए निजी क्षेत्र की भूमि को सम्मिलित करते हुए दीर्घकालीन योजना तैयार करेगी. परिषद के निदेशक मंडल द्वारा परिषद कर्मियों को ग्रेच्युटी की सीमा में की गई वृद्धि के फलस्वरूप गठित ग्रेच्युटी ट्रस्ट के लिए 69.39 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किए जाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया. भूमि अधिग्रहण के मामलों में परियोजना में प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वासन के लिए तीन दिसंबर 2010 के शासनादेश को अंगीकृत किया गया. इस शासनादेश में 33 वर्ष तक किसानों को वार्षिकी दिए जाने का प्रावधान है.

महिला को डायन बताकर प्रताड़ित किया

उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार और उनके ख़िलाफ़ घिनौने उत्पीड़नों को लेकर राजनीतिक दलों व समाजसेवियों द्वारा निरंतर आवाज़ उठाई जाती रही है, लेकिन इन उत्पीड़नों का सिलसिला फिर भी नहीं रुक पाया है. उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में महिलाओं को डायन कहकर महीनों तक यातना दी गई और पूरा गांव देखता रहा. इस ज़िले के जामपानी गांव में दो महिलाओं पहवा व जासो देवी को डायन और भूतनी कहकर न केवल लाठी-डंडों से पीटा गया, बल्कि उनके ज़ख्मों पर मिर्च भी डाली गई. यह सब देखने वालों की संख्या सैकड़ों में थी, लेकिन बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया. सोनभद्र ज़िले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि महिला की शिकायत पर धारा 323, 504, 506 के अंतर्गत मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि आदिवासी बहुल इलाक़ों में महिलाओं को डायन कहा जाना आम बात है. दरअसल यह एक सामान्य मारपीट का मामला है. बाक़ी की कार्रवाई वे कोर्ट के आदेश पर ही करेंगे.

संपत्तियों की क्षति रोकने के लिए बिल

उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ़ डैमेज प्रॉपर्टी बिल 2011 बनाकर आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक और निज़ी संपत्तियों की क्षति को रोकने के लिए क़ानूनी शिकंजा कसने में जुट गई है. विपक्षी दलों के आंदोलनों के डर ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है. मुख्य सचिव ने सार्वजनिक और निजी संपति के नुक़सान को प्रभावी रूप से रोकने के लिए कई वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श किया है. प्रस्तावित बिल को क़ानूनी रूप देने के लिए कमेटी के गठन का निर्णय लिया है. इस कमेटी के अध्यक्ष प्रमुख सचिव न्याय होंगे तथा डीजीपी, गृहसचिव सहित कई प्रमुख अधिकारी कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल किए जाएंगे. हाई पावर्ड मॉनीटरिंग कमेटी में राज्य विधि आयोग के सचिव विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे. यह कमेटी निजी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति की हानि के संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखेगी.

बुंदेलखंड के सभी ज़िलों में केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे

अब बुंदेलखंड के अभिभावकों को अपने बच्चों को सस्ती और गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए कहीं दूर नहीं भेजना पड़ेगा. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा बुंदेलखंड के हर ज़िले में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे. इन केंद्रीय विद्यालयों के लिए जिलाधिकारियों से 10 एकड़ भूमि चिन्हित कर विद्यालय से जुड़े प्रस्ताव भेजने को कहा गया है. सभी जनपदों से प्रस्ताव मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी. राज्य में इस समय 35 ज़िलों में केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं.

बिजली के बिल अब डाकघरों में जमा होंगे

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली के बिल जमा करने के लिए अब लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा. वे अपना बिल स्थानीय डाकघरों में जमा करा सकेंगे. इस योजना को लागू करने के लिए लखनऊ में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (मेरठ डिस्कॉम) और डाक विभाग के अधिकारियों के बीच समझौता हुआ है. शक्ति भवन मुख्यालय में पावर कॉरपोरेशन के सीएमडी नवनीत सहगल, चीफ पोस्टमास्टर जनरल (उत्तर प्रदेश परिमंडल), कर्नल कमलेश चंद्र मेरठ डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक आशिष गोयल की मौजूदगी में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए. इससे मेरठ, ग़ाज़ियाबाद, मुजफ़्फ़रनगर, बुलंदशहर, सहारनपुर, गौतमबुद्ध नगर, रामपुर, मुरादाबाद, जेपी नगर ज़िलों के 35 लाख बिजली उपभोक्ता 2358 डाकघरों में बिजली के बिल जमा कर सकेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com